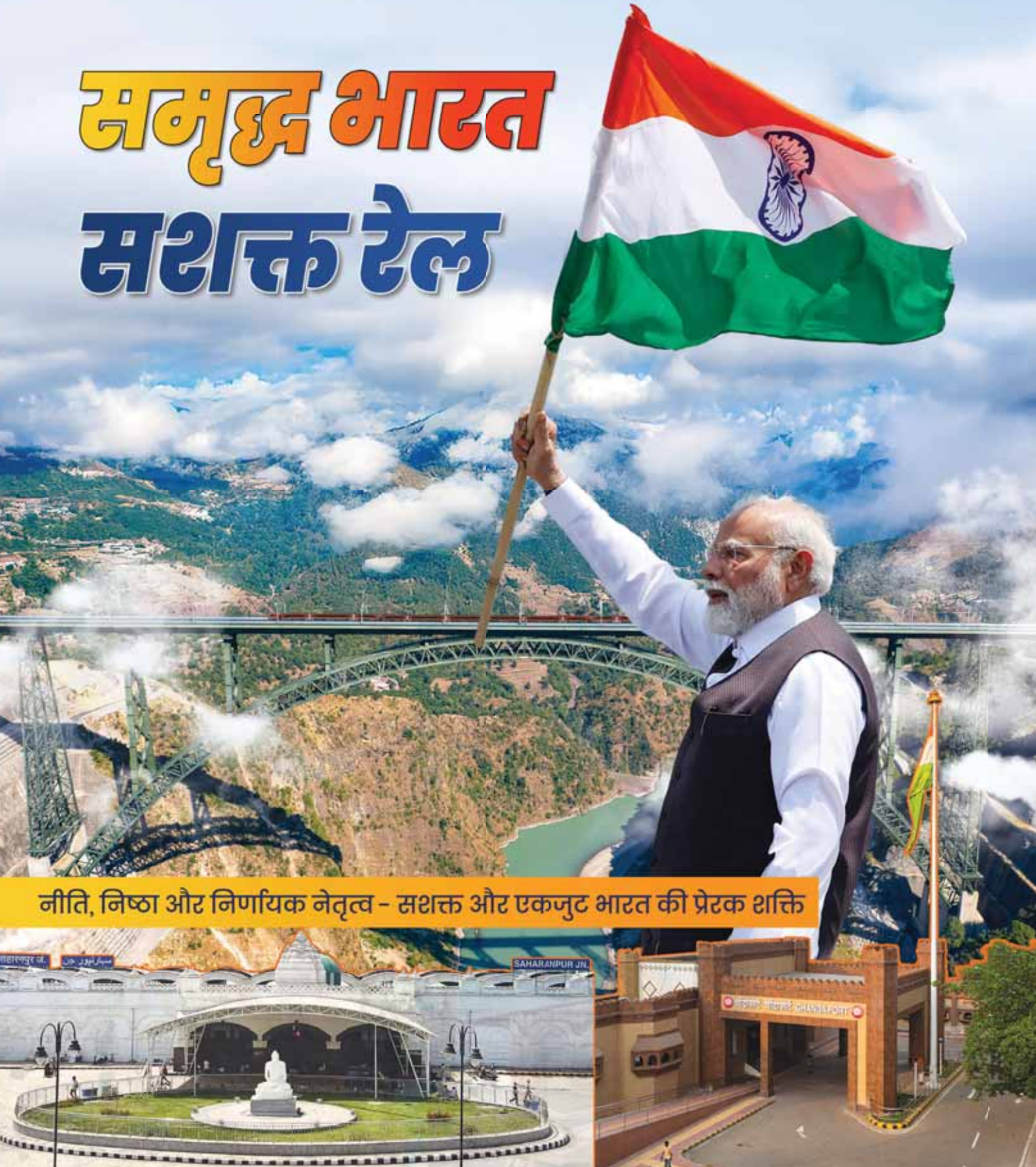
भारतीय रेल

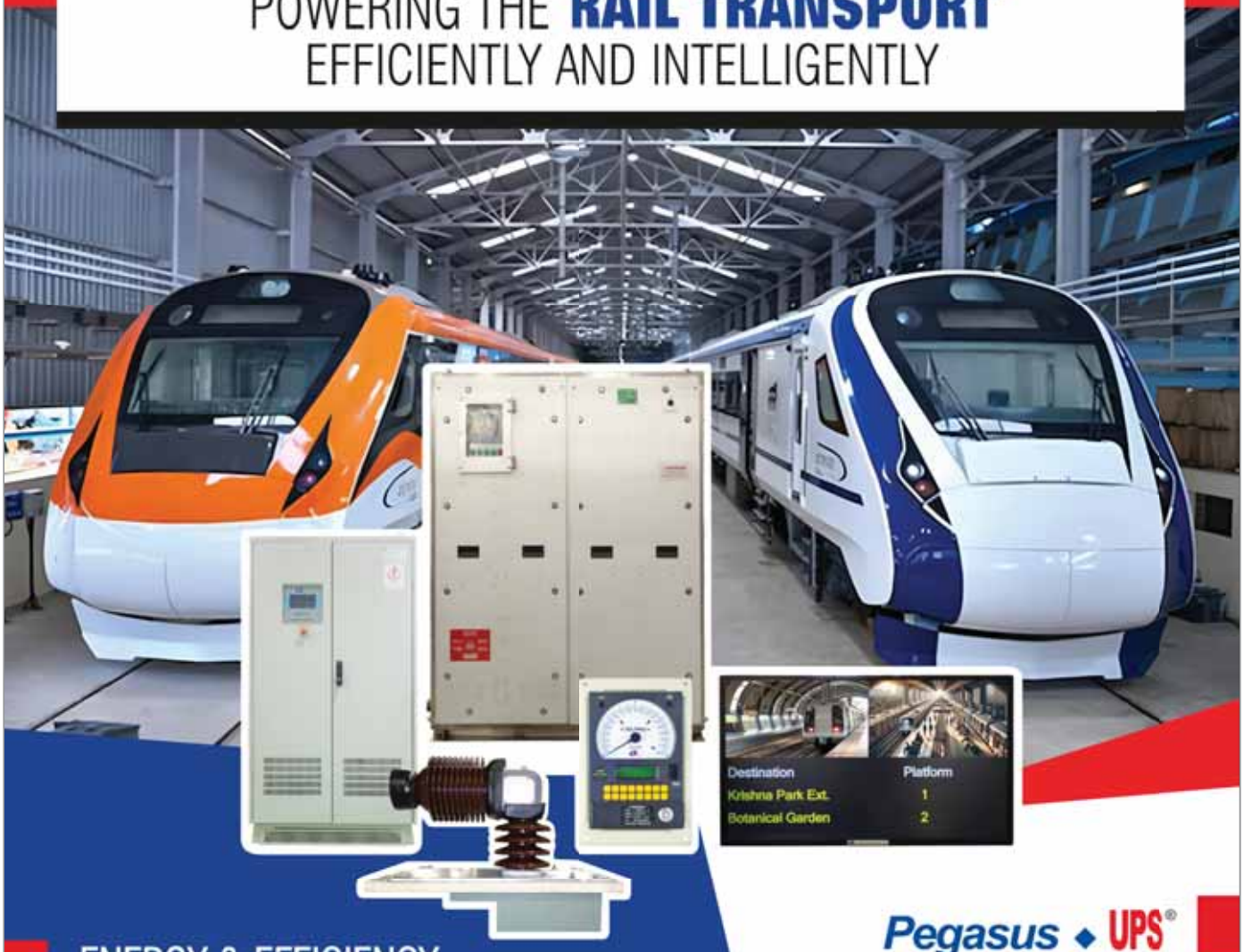
जुलाई 2025

मूल्य ₹ 20



AAL®
Autometers Alliance Ltd

POWERING THE **RAIL TRANSPORT** EFFICIENTLY AND INTELLIGENTLY



ENERGY & EFFICIENCY
SAFETY & RELIABILITY

Power Electronics & Propulsion System | Traction Switchgear and Panels | Data Acquisition and Control Device

Display and Passenger Information System | Uninterruptible Power Supplies

ISO 9001:2015 | ISO 14001:2015 | ISO 45001:2018

Pegasus ◆ UPS®

MAKE IN INDIA COMPANY

C-63, Sector-57, Noida - 201 307 (U.P.) India

mktre@autometers.com
www.autometers.com

भारतीय रेल

रेल मंत्रालय की एकमात्र हिंदी मासिक पत्रिका

आरंभ: अगस्त-1960 | वर्ष: 65 | अंक: 13 | राजभाषा कीर्ति पुरस्कार से सम्मानित पत्रिका | जुलाई-2025 | मूल्य: ₹20

संपादक मंडल

सतीश कुमार
अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, रेलवे बोर्ड

उषा वेणुगोपाल
सदस्य वित्त, रेलवे बोर्ड

अरुणा नायर
सचिव, रेलवे बोर्ड

दिलीप कुमार
कार्यकारी निदेशक, सूचना एवं प्रचार

शिवाजी मारुती सुतार
निदेशक, सूचना एवं प्रचार

संपादक
योगेश अवस्थी

संपादकीय कार्यालय
संपादक, भारतीय रेल,
कमरा नं. 411, रेल भवन,
रायसीना रोड, नई दिल्ली-110 001
editorbhartiyarailrb@gmail.com
editorbhartiyarail@gmail.com

विज्ञापन व सदस्यता हेतु संपर्क
ललित कुमार धनकड़
व्यापार प्रबंधक
कमरा नं. 310, रेल भवन
रायसीना रोड, नई दिल्ली-110 001
टेलीफोन: 011-47845378, 47845089
bmpr310rb@gmail.com

आवरण
समृद्ध भारत, सशक्त रेल

फॉलो करें
Twitter :
@bhartiyarailrb

वार्षिक सदस्यता शुल्क
(ऑफलाइन)
सर्वसाधारण -₹250
रेलकर्मियों के लिए -₹200
विदेश में
सी-मेल द्वारा -₹1,250
एयर-मेल द्वारा -₹2,500
एक प्रति-₹20 वार्षिक विशेषांक-₹70

इस पत्रिका में छपी हर सामग्री का सम्बन्ध, जब तक विशेषत: स्पष्ट न लिखा जाए, किसी सरकारी सूत्र से न समझा जाए।

© भारतीय रेल

5 विकास और हरित भविष्य की ओर अग्रसर भारतीय रेल

6 USBRL परियोजना राष्ट्र को समर्पित

10 प्रधानमंत्री द्वारा 103 अमृत स्टेशनों का उद्घाटन

15 प्रधानमंत्री ने किया दाहोद इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री का उद्घाटन

17 प्रधानमंत्री ने सोन नगर-मोहम्मद गंज के बीच तीसरी रेल लाइन राष्ट्र को किया समर्पित

18 प्रधानमंत्री ने सिवान में नई वैशाली-देवरिया रेल परियोजना का किया उद्घाटन और नई ट्रेन सेवाओं को दिखाई हरी झंडी

18 ओडिशा को दो नई ट्रेन सेवाओं सहित कई रेल परियोजनाओं की सौगात

19 आंध्र प्रदेश में कई रेल विकास कार्यों का शिलान्यास एवं उद्घाटन

20 भारत को लॉजिस्टिक्स पावर बनाने की ऐतिहासिक पहल

22 मैरबी-साईरंग रेलवे परियोजना साईरंग, आइजोल तक का ट्रायल रन सफल

22 छत्रपति शिवाजी महाराज भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने दिखाई हरी झंडी

23 रतलाम नागदा तीसरी और चौथी रेल लाइन परियोजना को मिली स्वीकृति

24 रेल मंत्री ने जमालपुर लोकोमोटिव वर्कशॉप में वैगन पीओएच क्षमता वृद्धि परियोजना की रखी आधारशिला

25 देश के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल गति शक्ति मल्टी-मॉडल कार्गो टर्मिनल का रेल मंत्री ने किया उद्घाटन

26 जोधपुर रेलवे स्टेशन पर जल्द मिलेंगी विश्वस्तरीय सुविधाएँ

27 ग्वालियर-बेंगलुरु नई साप्ताहिक ट्रेन प्रारंभ- मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के यात्रियों को सीधी कनेक्टिविटी

28 रेल मंत्री द्वारा पुरुलिया-हावड़ा के लिए ट्रेन का शुभारंभ

29 महाराष्ट्र, तमिलनाडु और राजस्थान के बीच सीधी रेल सेवा का शुभारंभ

30 रेलवन वन-स्टॉप सॉल्यूशन ऐप

31 ट्रेनों के रवाना होने से 8 घंटे पहले आरक्षण चार्ट बनना प्रारम्भ

38 भारतीय रेल ने मनाया अंतराष्ट्रीय योग दिवस

44 क्षेत्रीय रेलों एवं उत्पादन इकाइयों के समाचार

48 वीर सैनिकों के सम्मान में जगमगाए देशभर के रेलवे स्टेशन

51 प्रगति रिपोर्ट

58 अमृत भारत स्टेशन : भारतीय रेल ढाँचे की कायापलट करने वाली योजना — वी. सी. प्रमोद

62 दक्षिण भारत में वादियों की सैर कराती *वैगई एक्सप्रेस* — विमलेश चंद्र

66 एक पृथ्वी, एक स्वास्थ्य योग — डॉ. वी चन्नामल्लिकार्जुना

69 पर्यटकों का पसंदीदा ठिकाना गुजरात का शिवराजपुर बीच — नीलेश शुक्ला

संपादकीय



कुछ क्षण इतिहास रचते हैं, कुछ भविष्य गढ़ते हैं– और कभी–कभी दोनों एक साथ होते हैं। ऐसा ही एक अविस्मरणीय क्षण तब सामने आया, जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊँचे रेलवे ब्रिज पर तिरंगा लेकर राष्ट्र के नाम एक नई ऊँचाई समर्पित की। लहराती हवाओं और गूंजते स्वाभिमान के बीच उन्होंने इसे 'महत्त्वाकांक्षा और क्रियान्वयन का संगम' बताया– और ठीक यही है आज की भारतीय रेल की पहचान।

यह दृश्य केवल एक ब्रिज पर तिरंगा फहराने तक सीमित नहीं था, बल्कि एक संदेश था– कि भारत अब केवल सपने नहीं देखता, बल्कि उन्हें साकार करने का सामर्थ्य भी रखता है। दुनिया का सबसे ऊँचा रेलवे ब्रिज चिनाब और भारतीय रेल का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज–अंजी न केवल इंजीनियरिंग की दृष्टि से अद्‌भुत संरचनाएँ हैं, बल्कि ये राष्ट्रीय एकता, सामरिक मजबूती और समावेशी विकास की भी प्रतिमूर्ति हैं।

यह क्षण उधमपुर–श्रीनगर–बारामूला रेल लिंक (यूएसबीआरएल) परियोजना को राष्ट्र को समर्पित करने के अवसर का हिस्सा था– दिन था दिनांक 6 जून, 2025। यह परियोजना जो जम्मू–कश्मीर को देश की मुख्यधारा से स्थायी रूप से जोड़ती है। दुर्गम हिमालयी क्षेत्र में यह रेल संपर्क एक सपना था, जिसे भारतीय रेल ने अत्याधुनिक तकनीक, अथक परिश्रम और अडिग संकल्प से साकार किया।

पिछले कुछ महीनों में भारतीय रेल ने विकास के नए प्रतिमान स्थापित किए हैं। दिनांक 6 अप्रैल, 2025 को पांबन ब्रिज का उद्‌घाटन, 22 मई, 2025 को 103 अमृत स्टेशनों का लोकार्पण और 6 जून, 2025 को यूएसबीआरएल का राष्ट्र को समर्पण– ये सभी मील के पत्थर हैं। दाहोद में नई इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री, वंदे भारत ट्रेनों का विस्तार और अन्य यात्री सेवाओं की शुरुआत ने रेल संपर्क को एक नई गति दी है।

यूएसबीआरएल परियोजना सिर्फ एक नाम नहीं है, यह जम्मू–कश्मीर के नए सामर्थ्य की पहचान है, भारत के नए सामर्थ्य का जयघोष है– ये शब्द हैं प्रधानमंत्री के। जम्मू और कश्मीर भारत का मुकुट रत्न बताते हुए उन्होंने कहा है कि विशाल अवसंरचना परियोजनाओं का उद्‌घाटन जम्मू और कश्मीर की विकास यात्रा में एक महत्त्वपूर्ण मोड़ है। चिनाब और अंजी ब्रिज जम्मू और कश्मीर के लिए समृद्धि के प्रवेश द्वार के रूप में काम करेंगे।

'अमृत भारत स्टेशन योजना' के अंतर्गत स्टेशनों को केवल भव्य नहीं, बल्कि सुविधासम्पन्न और क्षेत्रीय सांस्कृतिक पहचान के अनुरूप बनाया जा रहा है। यह रेल अवसंरचना के मानवीय पक्ष को दर्शाता है, जिसमें विकास केवल आंकड़ों में नहीं, बल्कि मुस्कानों में परिलक्षित होता है।

आज भारत यह दिखा रहा है कि वह केवल भविष्य के सपने नहीं देखता, बल्कि उन्हें बुनने और जीने का माद्दा भी रखता है। भारतीय रेल इसी भावना के साथ देश को जोड़ने, सशक्त बनाने और मुस्कुराने की नई वजहें देने में जुटी है– हर दिन, हर दिशा में।

आपको हमारा यह अंक कैसा लगा, हमें अवश्य बताएं।

विकास और हरित भविष्य की ओर अग्रसर भारतीय रेल



अश्विनी वैष्णव
रेल मंत्री

जब भी आप सड़क या अन्य साधनों की जगह ट्रेन से यात्रा करते हैं, तो आप सिर्फ सुविधा नहीं, बल्कि एक स्वच्छ और हरित भारत को चुनते हैं। पिछले साल 700 करोड़ से ज्यादा यात्रियों ने भारतीय रेल से सफर किया। यह हमारी जीवनरेखा है और आने वाले कल के लिए एक हरित संकल्प भी।

भारतीय रेल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के पंचामृत लक्ष्य '2070 तक शून्य उत्सर्जन (नेट जीरो)' में अहम भूमिका निभा रही है। हम माल और यात्री परिवहन को सड़क से रेल पर ले जा रहे हैं। साथ ही स्वच्छ ऊर्जा का इस्तेमाल बढ़ा रहे हैं। इससे भारत की अर्थव्यवस्था को कार्बनमुक्त करने में मदद मिल रही है।

सड़क से रेल की ओर

वित्त वर्ष 2013-14 में भारतीय रेल ने लगभग 1,055 मिलियन टन माल की ढुलाई की। वित्त वर्ष 2024-25 में यह बढ़कर 1,617 मिलियन टन हो गया है। इससे हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मालवाहक रेलवे बन गए हैं। सड़क की जगह रेल से माल ढुलाई करने से अब तक 143 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन रोका गया है। यह 121 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर है।



रेल से माल ढुलाई, सड़क से सस्ती है। इससे पिछले 10 सालों में देश को ₹3.2 लाख करोड़ की बचत हुई है। रेल, ट्रकों के मुकाबले 90% कम कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करती है। इससे हवा साफ रहती है। 2,857 करोड़ लीटर डीजल की भी बचत हुई है, जो कि लगभग 2 लाख करोड़ रुपये की बचत के बराबर है।

विद्युतीकरण से आत्मनिर्भरता

भारी मात्रा में तेल आयात करता है। ऐसे में रेलवे का विद्युतीकरण सामरिक रूप से जरूरी है। 2014 से पहले 60 वर्षों में 21,000 कि.मी. रेलवे लाइन ही विद्युतीकृत हुई थी। लेकिन पिछले 11 सालों में हमने 47,000 कि.मी. रेल लाइन को विद्युतीकृत किया है। अब तक 99% ब्रॉड गेज नेटवर्क विद्युतीकृत हो चुका है। रेलवे अब स्टेशनों, वर्कशॉप और ट्रेनों के लिए भी हरित ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहा है। हम राज्यों के साथ मिलकर ट्रेनों को हरित ऊर्जा से चलाने की दिशा में काम कर रहे हैं।

माल ढुलाई का नया मॉडल

डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (डीएफसी) भी पूरी तरह से विद्युतीकृत होते हैं। ये कॉरिडोर सिर्फ माल ढुलाई के लिए बनाए गए हैं। वर्तमान में 2,741 कि.मी. के फ्रेट कॉरिडोर संचालित हैं। इससे सड़कों पर भीड़ घटी है, डीजल की खपत कम हुई है और कार्बन उत्सर्जन भी घटा है।

भारत अब हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों को भी अपनाने जा रहा है। पहली ट्रेन हरियाणा में जींद और सोनीपत के बीच चलेगी। यह दुनिया की सबसे लंबी और ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेन होगी।

अर्थव्यवस्था और पर्यावरण

भारत ने दिखाया है कि आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण एक साथ संभव हैं। वर्ष 2023 के वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का स्थान 139 देशों में 38वें पर रहा। वर्ष 2014 की तुलना में यह 16 स्थान ऊपर है। रेलवे के विद्युतीकरण से प्रदूषण और लागत दोनों में कमी आई है। साथ ही लॉजिस्टिक्स की क्षमता और गति दोनों बढ़ी हैं।

वर्ष 2030 तक नेट-शून्य उत्सर्जन

प्रधानमंत्री मोदी ने रेलवे के लिए वर्ष 2030 तक नेट जीरो का लक्ष्य रखा है। तेजी से हो रहे विद्युतीकरण और सड़क से रेल की ओर शिफ्ट हो रहे यातायात से भारतीय रेल वर्ष 2025 तक ही स्कोप 1 नेट जीरो का लक्ष्य हासिल कर लेगी।

इस विश्व पर्यावरण दिवस पर भारतीय रेल सतत विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराती है। हर ट्रैक का विद्युतीकरण, हर सोलर पैनल और सड़क से हटाया गया हर कंटेनर, हमारे देश और पर्यावरण के उज्ज्वल भविष्य के लिए एक कदम है।



US परियोजना

“चिनाब रेल पुल पर गर्व से लहरा रहा है तिरंगा !

यह अत्यंत गर्व की बात है कि यह पुल महत्वाकांक्षा के साथ क्रियान्वयन का मेल है, जो भारत के सबसे चुनौतीपूर्ण स्थानों पर अत्याधुनिक बुनियादी ढ़ांचा निर्माण की बढ़ती क्षमता को प्रदर्शित करता है।”

नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दिनांक 6 जून, 2025 को जम्मू-कश्मीर के कटरा से उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेल लिंक (यूएसबीआरएल) परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया। 272 कि.मी. लंबी यूएसबीआरएल परियोजना, जिसका निर्माण लगभग ₹43,780 करोड़ की लागत से किया गया है, जिसमें 36 सुरंगें और (943 ब्रिज 119 कि.मी. तक फैली हुई) शामिल हैं। यह परियोजना कश्मीर घाटी और देश के बाकी हिस्सों के बीच सभी मौसमों में निर्बाध रेल संपर्क स्थापित करती है, जिसका उद्देश्य क्षेत्रीय गतिशीलता को बदलना और सामाजिक-आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देना है।

BRL

राष्ट्र को समर्पित





ताकत का प्रतीक

"उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेल लाइन परियोजना एक नए, सशक्त जम्मू और कश्मीर का प्रतीक है और भारत की बढ़ती ताकत का एक शानदार उद्घोष है

विशाल अवसंरचना परियोजनाओं का उद्घाटन जम्मू और कश्मीर की विकास यात्रा में एक महत्त्वपूर्ण मोड़ है

चिनाब और अंजी पुल जम्मू और कश्मीर के लिए समृद्धि के प्रवेश द्वार के रूप में काम करेंगे"

नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

चिनाब ब्रिज एवं अंजी ब्रिज का प्रधानमंत्री ने किया उद्घाटन

नदी तल से 359 मीटर की ऊँचाई पर स्थित वास्तुकला का चमत्कार चिनाब रेल ब्रिज दुनिया का सबसे ऊँचा रेलवे आर्च ब्रिज है। यह 1,315 मीटर लंबा स्टील आर्च ब्रिज है जिसे भूकंप और तेज हवा की स्थिति में दृढ़ता के साथ अडिग रहने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस ब्रिज का एक प्रमुख लक्ष्य जम्मू और श्रीनगर के बीच संपर्क को बढ़ाना है। ब्रिज पर चलने वाली वंदे भारत ट्रेन के जरिए कटरा और श्रीनगर के बीच यात्रा करने में सिर्फ 3 घंटे लगेंगे, जिससे वर्तमान यात्रा समय में 2-3 घंटे की कमी आएगी। अंजी ब्रिज भारत का पहला केबल-स्टेड रेल ब्रिज है, जो इस चुनौतीपूर्ण भूभाग में राष्ट्र की सेवा करेगा।



प्रधानमंत्री ने श्री माता वैष्णो देवी कटरा से श्रीनगर और वापस जाने वाली दो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को भी झंडी दिखाई। ये ट्रेनें स्थानीय निवासियों, पर्यटकों, तीर्थयात्रियों और अन्य लोगों के लिए शीघ्र, आरामदायक और विश्वसनीय यात्रा का विकल्प प्रदान करेंगी।

इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह कार्यक्रम भारत की एकता और दृढ़ संकल्प का भव्य उत्सव है। माता वैष्णो देवी के आशीर्वाद से कश्मीर घाटी अब भारत के विशाल रेल नेटवर्क से जुड़ गई है। प्रधानमंत्री ने कहा, "हमने हमेशा गहरी श्रद्धा के साथ कश्मीर से कन्याकुमारी तक 'जय माता दी' कहते हुए मां भारती का आह्वान किया है। आज यह हमारे रेल नेटवर्क में भी एक वास्तविकता बन गई है।" उन्होंने कहा, उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेल लाइन परियोजना केवल एक नाम नहीं, बल्कि यह जम्मू-कश्मीर की नई ताकत और भारत की बढ़ती क्षमताओं का प्रतीक है। क्षेत्र में रेल बुनियादी ढाँचे और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता के अनुरूप, उन्होंने चिनाब और अंजी रेल ब्रिजों का उद्घाटन किया और जम्मू-कश्मीर के भीतर कनेक्टिविटी को बढ़ाते हुए वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई।

प्रधानमंत्री ने कहा कि जम्मू-कश्मीर की पीढ़ियों ने रेलवे कनेक्टिविटी का सपना लंबे समय से देखा था, आज यह सपना सच हो गया है। लंबे समय से प्रतीक्षित इस आकांक्षा की पूर्ति जम्मू-कश्मीर के लाखों लोगों के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है, जो बेहतर कनेक्टिविटी और प्रगति का मार्ग प्रशस्त करता है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि यह उनकी सरकार के लिए सौभाग्य की बात है कि इस महत्त्वाकांक्षी रेल परियोजना ने उनके कार्यकाल के दौरान गति पकड़ी और अब सफलतापूर्वक पूरी हो गई है। इस परियोजना में कई चुनौतियाँ थीं, जैसे कि कठिन भूभाग, खराब मौसम और पहाड़ों में गिरती चट्टानें, जिनसे यह परियोजना बेहद कठिन और चुनौतीपूर्ण हो गई थी। हालांकि, उनकी सरकार ने हमेशा चुनौतियों का सामना करने और दृढ़ संकल्प के साथ उन पर विजय पाने का विकल्प चुना है। जम्मू-कश्मीर में चल रही सभी मौसमों में कार्यशील रहने वाली कई बुनियादी ढाँचा परियोजनाएँ इस प्रतिबद्धता का उदाहरण हैं। उन्होंने सोनमर्ग सुरंग, चिनाब ब्रिज और अंजी ब्रिज पर यात्रा करने के अपने अनुभव को उल्लेखनीय उपलब्धि बताया। प्रधानमंत्री ने भारत के इंजीनियरों और श्रमिकों की इंजीनियरिंग प्रतिभा और अटूट समर्पण की सराहना करते हुए कहा कि दुनिया का सबसे ऊँचा रेलवे आर्च ब्रिज चिनाब भारत की महत्त्वाकांक्षा का प्रमाण है।

जहाँ लोग एफिल टावर देखने के लिए पेरिस जाते हैं, वहीं चिनाब ब्रिज की ऊँचाई उससे भी अधिक है, जिससे यह न केवल एक महत्त्वपूर्ण बुनियादी ढाँचा बन गया है, बल्कि एक उभरता हुआ आकर्षक पर्यटन स्थल भी बन गया है। इसी तरह, प्रधानमंत्री ने अंजी ब्रिज को इंजीनियरिंग का चमत्कार बताया, जो भारत का पहला केबल-समर्थित रेलवे ब्रिज है। ये संरचनाएँ केवल स्टील



प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अंजी खड्ड रेल ब्रिज का उद्घाटन किया। इस अवसर पर जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला तथा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव एवं केन्द्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह उपस्थित रहे



प्रधानमंत्री को यूएसबीआरएल परीयोजना की विस्तृत जानकारी साझा करते हुए अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीश कुमार

और कंक्रीट से बनी नहीं हैं, बल्कि भारत की शक्ति के जीवंत प्रतीक हैं, जो पीर पंजाल पहाड़ों के ऊबड़-खाबड़ ऊँचे स्थान पर खड़े हैं। ये उपलब्धियाँ एक विकसित राष्ट्र के लिए भारत के विजन का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो साबित करता हैं कि भारत की प्रगति का सपना जितना बड़ा है, उतना ही उसका लचीलापन, उसकी क्षमता और दृढ़ संकल्प है। इसके अतिरिक्त उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि शुद्ध इरादे और अथक समर्पण भारत के रूपांतरण के पीछे की प्रेरक शक्तियाँ हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि चिनाब ब्रिज और अंजी ब्रिज दोनों ही जम्मू-कश्मीर में समृद्धि की प्रेरणा के रूप में काम करेंगे। उन्होंने कहा, 'ये ऐतिहासिक परियोजनाएँ न केवल पर्यटन को बढ़ावा देंगी बल्कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को भी लाभान्वित करेंगी, जिससे व्यवसायों और उद्योगों के लिए नए अवसर पैदा होंगे।' उन्होंने कहा कि जम्मू और कश्मीर के बीच बेहतर रेल संपर्क स्थानीय उद्यमियों के लिए अवसरों के नए द्वार खोलेगा, जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।

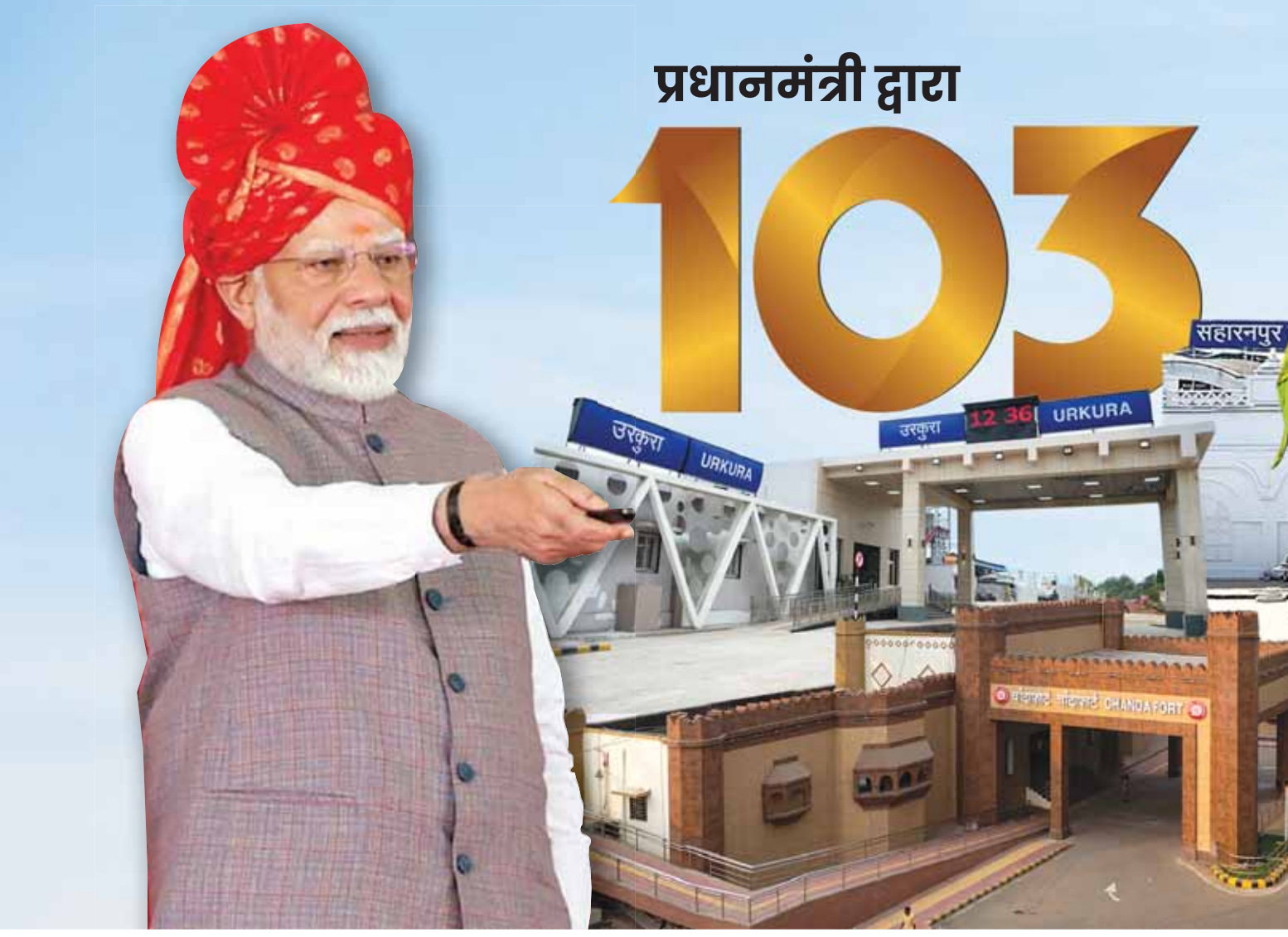
प्रधानमंत्री ने संगलदान के एक विद्यार्थी की मार्मिक टिप्पणी साझा की, जिसने कहा था कि अब तक केवल उन लोगों ने ही वास्तविक जीवन में रेलगाड़ी देखी थी, जिन्होंने गांव से बाहर कदम रखे थे। अधिकांश ग्रामीणों ने केवल वीडियो में ही रेलगाड़ियाँ देखी थीं। उन्हें विश्वास नहीं था कि शीघ्र ही उनकी आंखों के सामने से एक वास्तविक रेलगाड़ी भी गुजरेगी। कई लोगों ने अब रेलगाड़ियों की समय-सारिणी को भी याद करना शुरू कर दिया है और वे नई कनेक्टिविटी को लेकर काफी उत्साहित हैं। उन्होंने एक युवती की एक विचारशील टिप्पणी पर प्रकाश डाला, जिसमें उसने कहा कि अब मौसम यह तय नहीं करेगा कि सड़कें खुली रहेंगी या बंद। यह नई रेल सेवा सभी मौसमों में लोगों की मदद करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा, 'जम्मू और कश्मीर भारत माता का मुकुट है, जो उज्ज्वल रत्नों से सुसज्जित है। प्रत्येक रत्न इस क्षेत्र की असीम शक्ति और सौंदर्य का प्रतिनिधित्व करता है।' उन्होंने इसकी प्राचीन संस्कृति, परंपराओं, आध्यात्मिक चेतना, मनमोहक परिदृश्यों, औषधीय जड़ी-बूटियों, फलते-फूलते बागों और जीवंत युवा प्रतिभा की प्रशंसा करते हुए कहा कि ये गुण भारत के मुकुट में बहुमूल्य रत्नों की तरह चमकते हैं। दशकों से जम्मू-कश्मीर का दौरा कर रहे प्रधानमंत्री ने क्षेत्र की क्षमता के बारे में अपनी गहरी समझ की पुष्टि की और जम्मू-कश्मीर के निरंतर विकास और उत्थान के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई, जिससे वहाँ के लोगों की समृद्धि सुनिश्चित हो सके।

प्रधानमंत्री ने कहा, 'जम्मू और कश्मीर लंबे समय से भारत की शिक्षा और सांस्कृतिक विरासत का एक स्तंभ रहा है।' उन्होंने कहा कि जैसे-जैसे भारत खुद को वैश्विक ज्ञान केंद्र के रूप में स्थापित कर रहा है, इस रूपांतरण में जम्मू और कश्मीर की सहभागिता बढ़ रही है।



वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाते हुए प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री द्वारा 103



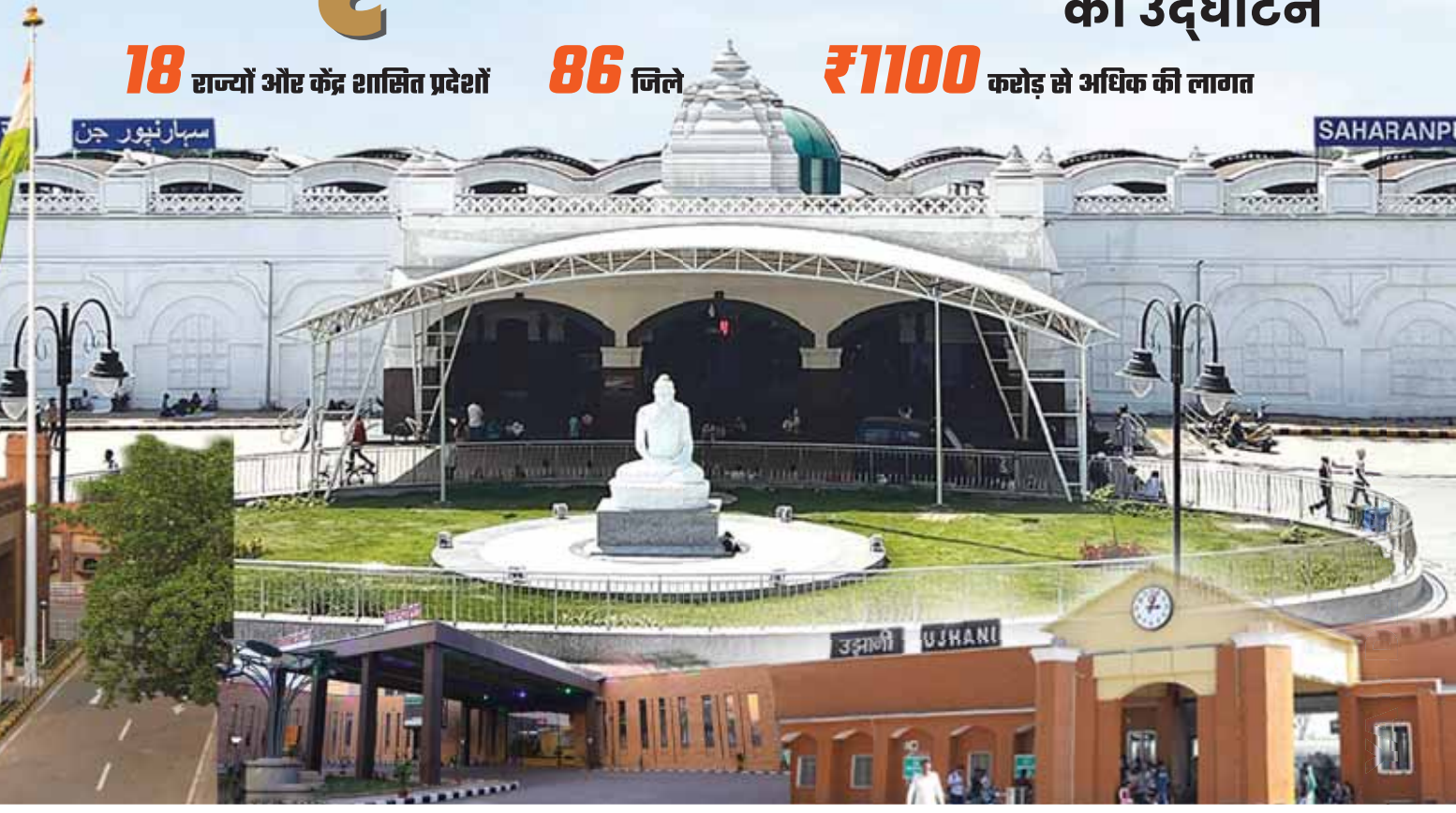
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दिनांक 22 मई, 2025 को राजस्थान के बीकानेर से देश के 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 86 जिलों में ₹1,100 करोड़ से अधिक की लागत से विकसित 103 पुनर्विकसित अमृत स्टेशनों का उद्घाटन किया। 'अमृत भारत स्टेशन योजना' के अंतर्गत 1,300 से अधिक स्टेशनों को आधुनिक सुविधाओं के साथ पुनर्विकसित किया जा रहा है, जिन्हें क्षेत्रीय वास्तुकला को प्रतिबिंबित करने और यात्री सुविधाओं को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

बीकानेर के करणी माता मंदिर में आने वाले तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को देशनोक रेलवे स्टेशन मंदिर की वास्तुकला और मेहराब एवं स्तंभ से साक्षात्कार कराता है। तेलंगाना में बेगमपेट रेलवे स्टेशन काकतीय साम्राज्य की वास्तुकला से प्रेरित है। बिहार में थावे स्टेशन में 52 शक्तिपीठों में से एक माँ थावेवाली का प्रतिनिधित्व करने वाले विभिन्न भित्ति चित्र और कलाकृतियाँ शामिल हैं। यहाँ मधुबनी पेंटिंग को भी दर्शाया गया है। गुजरात में डाकोर स्टेशन रणछोड़राय जी महाराज को श्रद्धांजलि देता है। भारत भर में पुनर्विकसित अमृत स्टेशनों में आधुनिक अवसंरचना को सांस्कृतिक विरासत, दिव्यांगजनों के लिए यात्री-केंद्रित सुविधाओं और यात्रा अनुभवों को बढ़ाने के लिए दीर्घकालिक कार्य प्रणालियों के साथ एकीकृत किया गया है। भारतीय रेल अपने नेटवर्क के शत-प्रतिशत विद्युतीकरण की ओर अग्रसर है, जिससे रेलवे संचालन अधिक कुशल और पर्यावरण के अनुकूल बन रहा है। इसी क्रम में, प्रधानमंत्री ने चूरू-सादुलपुर (दोहरीकरण) रेल लाइन (58 कि.मी.) की आधारशिला रखी और सूरतगढ़-फलोदी (336 कि.मी.); फुलेरा-डेगाना (109 कि.मी.); उदयपुर-हिम्मतनगर (210 कि.मी.); फलोदी-जैसलमेर (157 कि.मी.) और समदड़ी-बाड़मेर (129 कि.मी.) रेल लाइन का विद्युतीकरण राष्ट्र को समर्पित किया।

इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, पिछले 11 वर्षों में सड़कों, हवाई अड्डों, रेलवे और रेलवे स्टेशनों में हुई तीव्र प्रगति की चर्चा की। उन्होंने कहा कि भारत अब पिछले वर्षों की तुलना में बुनियादी ढाँचे के विकास में छह गुना अधिक निवेश कर रहा है, जो एक ऐसी प्रगति है, जिसने वैश्विक ध्यान आकर्षित किया है। उन्होंने देश भर में प्रतिष्ठित बुनियादी ढाँचा

अमृत स्टेशनों का उद्घाटन

18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों **86** जिले **₹1100** करोड़ से अधिक की लागत



परियोजनाओं की चर्चा करते हुए उत्तर में उल्लेखनीय चिनाब ब्रिज, अरुणाचल प्रदेश में सेला सुरंग और पूर्व में असम के बोगीबील ब्रिज का उदाहरण दिया। उन्होंने पश्चिमी भारत में, मुंबई में अटल सेतु का उल्लेख किया जबकि दक्षिण में, भारत के अपनी तरह के पहले पांबन ब्रिज की चर्चा की।

प्रधानमंत्री ने देश की नई गति और प्रगति के प्रतीक के रूप में वंदे भारत, अमृत भारत और नमो भारत ट्रेनों की शुरुआत का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि वंदे भारत ट्रेनों से दूरदराज के क्षेत्रों में आधुनिक रेल संपर्क स्थापित हो रहा है। उन्होंने पिछले 11 वर्षों में महत्त्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे की प्रगति की ओर भी ध्यान दिलाया, जिसमें सैकड़ों सड़क ओवरब्रिज और अंडरब्रिज के निर्माण के साथ ही 34,000 कि.मी. से अधिक नई रेल लाइन बिछाना शामिल है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि ये अमृत भारत स्टेशन न केवल भारत की हजारों वर्ष पुरानी विरासत को संरक्षित करते हैं, बल्कि राज्यों में पर्यटन विकास के लिए उत्प्रेरक के रूप में भी कार्य करते

> *"देश ने आधुनिक किए जा रहे रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन नाम दिया है, आज इनमें से 100 से अधिक अमृत भारत स्टेशन बनकर तैयार हैं।"*
>
> **नरेन्द्र मोदी**
> प्रधानमंत्री

हैं, जिससे युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसरों का सृजन होता है। उन्होंने लोगों से स्टेशनों की स्वच्छता और सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया, क्योंकि वे ही इन बुनियादी ढाँचे के असली मालिक हैं।

प्रधानमंत्री ने राजस्थान में जारी बुनियादी ढाँचे के विकास से होने वाले लाभों की भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इस वर्ष राज्य में रेलवे विकास पर लगभग ₹10,000 करोड़ खर्च करने वाली है, जो वर्ष 2014 से पहले के स्तर की तुलना में 15 गुना वृद्धि को दर्शाता है।



आंध्र प्रदेश

- सूल्लूरूपेटा रेलवे स्टेशन
- विशेष रूप से दिव्यांगजन अनुकूल सर्कुलेटिंग एरिया
- लिफ्ट, एस्केलेटर, प्रवेश द्वार पोर्च और वेटिंग हॉल जैसी आधुनिक सुविधाएँ



असम

- हयवरगांव स्टेशन
- नई स्टेशन बिल्डिंग, नया प्रतीक्षालय, पोर्च और नया पार्किंग के साथ ग्रीन एरिया
- दीवारों पर स्थानीय संस्कृति और वन्य जीवों का चित्रण





बिहार

- पीरपैंती और थावे स्टेशन
- स्थानीय थावे माता मंदिर से प्रेरित स्टेशन बिल्डिंग (थावे स्टेशन), दीवारों पर स्थानीय कला-संस्कृति का चित्रण
- नया प्लेटफॉर्म शेल्टर, उन्नत पार्किंग एरिया, बेहतर प्रतीक्षालय, उन्नत साइनेज



छत्तीसगढ़

- डोंगरगढ़, भानुप्रतापपुर, भिलाई, उरकुरा, अम्बिकापुर स्टेशन
- स्थानीय धरोहर और संस्कृति को दर्शाती दीवारें (भानुप्रतापपुर)
- पार्किंग और सर्कुलेटिंग एरिया का उन्नयन और सेल्फी प्वाइंट



गुजरात

- सामाख्याली, मोरवी, हापा, जामवणथली, कानालुस जंक्शन, ओखा, मीठापुर, राजुला जंक्शन, सिहोर जंक्शन, पालीताना, महुवा, जामजोधपुर, लींवडी, डेरोल, करमसद, उत्राण, कोसंवा जंक्शन, डाकोर स्टेशन
- परंपरागत फर्नीचर और यात्रियों के लिए बेहतर सुविधाएं, बैलगाड़ी हांकते भगवान द्वारकाधीश की प्रतिमा



हरियाणा

- मंडी डबवाली स्टेशन
- स्टेशन बिल्डिंग का उन्नयन, उन्नत प्रतीक्षालय और लिफ्ट
- दीवारों पर स्थानीय कला और संस्कृति का चित्रण



हिमाचल प्रदेश

- बैजनाथ पपरोला स्टेशन
- शानदार कॉनकोर्स, सुदृढ़ और भव्य प्लेटफॉर्म
- प्रतीक्षालय और एग्जीक्यूटिव लाउंज में उन्नत फर्नीचर



झारखंड

- राजमहल, शंकरपुर, गोबिंदपुर रोड स्टेशन
- 10 फीट फुट ओवर ब्रिज, द्वितीय प्रवेश द्वार और बेहतर प्रतीक्षालय
- स्टेशन बिल्डिंग का उन्नयन



कर्नाटक

- बागलकोट, धारवाड, गोकाक रोड, मुनिराबाद, गदग स्टेशन
- नए प्रतीक्षालय, उन्नत पार्किंग और सर्कुलेशन एरिया
- सेकेंड एंट्री, लिफ्ट, पोर्च और एस्केलेटर



केरल

- वडकरा, चिरयिनकिष स्टेशन
- केरल शैली आधारित वास्तुकला (वडकरा), तालाब और ग्रीन एरिया
- स्टेशनों का उन्नयन, बेहतर प्रतीक्षालय और पार्किंग क्षेत्र





मध्य प्रदेश

- शाजापुर, नर्मदापुरम, कटनी साउथ, श्रीधाम, सिवनी और ओरछा स्टेशन
- रामकथा पार्क और प्रतिमा (ओरछा) के साथ मोगली थीम (सिवनी) पर स्टेशनों का उन्नयन
- हाई लेवल पर एक प्लेटफॉर्म का विकास, नए प्रतीक्षालय, नया स्टेशन भवन और फुटओवर ब्रिज



महाराष्ट्र

- पटेल, चिंचपोकली, वडाला रोड, माटुंगा, सावदा, लोनंद,नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी जंक्शन, केडगांव, लासलगांव, मुर्तिजापुर जंक्शन, देवलाली, धुले, सावडा, चांदा फोर्ट, आमगांव स्टेशन
- नया फर्नीचर, पार्किंग एरिया और सूचना प्रणाली का उन्नयन



पुडुचेरी

- माहि स्टेशन
- स्टेशन भवन का उन्नयन, द्वितीय प्रवेश द्वार, नया पार्किंग एरिया और पोर्च
- वर्टिकल गॉर्डन में लिखा स्टेशन का नाम



राजस्थान

- देशनोक, बूंदी, माण्डलगढ़, गोगामेड़ी, गोविंदगढ़, मण्डावर महुआ रोड ,फतेहपुर शेखावाटी और राजगढ़ स्टेशन
- नए रिटायरिंग रूम, डॉरमेट्री और डबल हाइट कॉन्कोर्स
- छतरी और जाली जैसे परंपरागत वास्तुकला से जुड़े कार्य और पत्थरों की नक्काशी



तमिलनाडु

- सामलपट्टि, तिरुवण्णामलै, चिदंबरम, वृद्धाचलम जंक्शन, मन्नारगुडी, पोलूर, श्रीरंगम, कुलित्तुरै, सेंट थॉमस माउंट (परंगिमलै) स्टेशन
- नया फेस्टिवल ब्लॉक (तिरुवण्णामलै), नया रिटायरिंग रूम और डॉरमेट्री



तेलंगाना

- बेगमपेट, करीमनगर, वरंगल स्टेशन
- लैंडस्केपिंग के लिए पहाड़ और पेड़ों का संरक्षण, 40 फीट रूफ प्लाजा
- काकतीय कला आधारित बिल्डिंग डिजाइन (बेगमपेट)



उत्तर प्रदेश

- बिजनौर, सहारनपुर जंक्शन, गोवर्धन, फतेहाबाद, ईदगाह आगरा जंक्शन, रूरकला, गोविंदपुरी, पुखरायां, इज्जतनगर, बरेली सिटी, हाथरस सिटी, उझानी, सिद्धार्थनगर, स्वामीनारायण छपिया, मैलानी जंक्शन, गौरा गोकर्णनाथ, रामघाट हाल्ट, मुरईमानपुर, बलरामपुर स्टेशन
- नया एग्जीक्यूटिव लाउंज, 10 फीट चौड़ा फुट ओवर ब्रिज, पार्किंग एरिया, उन्नत फर्नीचर



पश्चिम बंगाल

- पानागढ़, जयचण्डी पहाड़, कल्याणी घोषपाड़ा स्टेशन
- नया द्वितीय प्रवेश द्वार, उन्नत साइनेज, पोर्च और नया पार्किंग एरिया
- वेटिंग रूम, रिटायरिंग रूम और डॉरमेट्री



प्रधानमंत्री ने किया

दाहोद इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री का उद्घाटन



प्रधानमंत्री ने
फैक्ट्री से निर्मित पहले इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, वेरावल-अहमदाबाद वंदे भारत और वलसाड-दाहोद एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी

कनेक्टिविटी बढ़ाने और विश्व स्तरीय यात्रा के लिए बुनियादी ढाँचे के निर्माण की अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दिनांक 26 मई, 2025 को दाहोद में भारतीय रेल के दाहोद इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री का उद्घाटन किया। यह संयंत्र घरेलू उद्देश्यों और निर्यात के लिए 9000 एचपी के इलेक्ट्रिक इंजनों का उत्पादन करेगा। उन्होंने फैक्ट्री से निर्मित पहले इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव को भी हरी झंडी दिखाई। लोकोमोटिव्स भारतीय रेल की माल ढुलाई क्षमता बढ़ाने में मदद करेंगे। ये लोकोमोटिव पुनरुत्पादक ब्रेकिंग सिस्टम से लैस होंगे और ऊर्जा की खपत को कम करने के लिए डिज़ाइन किए जा रहे हैं, जो पर्यावरणीय स्थिरता में योगदान देता है। इस अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने विभिन्न रेल परियोजनाएँ राष्ट्र को समर्पित कीं, जिनमें आणंद-गोधरा रेल लाइन दोहरीकरण, राजकोट-हड़मतिया रेल का दोहरीकरण तथा साबरमती-बोटाद रेल लाइन का विद्युतीकरण शामिल हैं। साथ ही, वेरावल और अहमदाबाद के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस और वलसाड और दाहोद स्टेशनों के बीच एक्सप्रेस ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई।

इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा, '140 करोड़ भारतीय एक विकसित भारत के निर्माण में एकजुट हैं।' उन्होंने भारत के भीतर आवश्यक वस्तुओं के निर्माण के महत्त्व पर जोर देते हुए कहा कि आत्मनिर्भरता समय की मांग है। भारत वैश्विक विनिर्माण क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और घरेलू उत्पादन और निर्यात दोनों में लगातार वृद्धि कर रहा है। भारत अब स्मार्टफोन, ऑटोमोबाइल, खिलौने, रक्षा उपकरण और दवाओं सहित कई तरह के उत्पादों का निर्यात कर रहा है। भारत न केवल रेल और मेट्रो तकनीक का निर्माण कर रहा है, बल्कि इसका वैश्विक स्तर पर निर्यात भी कर रहा है। इस प्रगति के एक प्रमुख उदाहरण दाहोद



प्रधानमंत्री को 9000 एचपी के इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव की विशेषताएँ बताते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव

को बताते हुए, हजारों करोड़ रुपये की प्रमुख परियोजनाओं का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने दाहोद इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव उत्पादन फैक्ट्री को एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में उजागर किया। उन्होंने याद किया कि तीन साल पहले इसकी आधारशिला रखी गई थी और गर्व व्यक्त किया कि अब पहला इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव सफलतापूर्वक निर्मित किया गया है। उन्होंने लोकोमोटिव को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो गुजरात और पूरे देश के लिए गौरव का क्षण था। इसके अतिरिक्त, उन्होंने घोषणा की, 'गुजरात ने अपने रेलवे नेटवर्क का 100% विद्युतीकरण हासिल कर लिया है' इसे उन्होंने एक उल्लेखनीय मील का पत्थर बताया और इस उपलब्धि के लिए गुजरात के लोगों को बधाई दी।

पिछले 10-11 वर्षों में भारत के रेलवे क्षेत्र के तेजी से हुए विकास पर प्रकाश डालते हुए, प्रधानमंत्री ने मेट्रो सेवाओं के विस्तार और सेमी-हाई-स्पीड ट्रेनों की शुरुआत पर जोर दिया, जिससे पूरे देश में कनेक्टिविटी बढ़ रही है। वंदे भारत ट्रेनें अब लगभग 70 मार्गों पर चल रही हैं, जो भारत के परिवहन नेटवर्क को और मजबूत बनाती हैं।

अहमदाबाद और वेरावल के बीच एक नई वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में आधुनिक ट्रेनों का उदय देश की प्रौद्योगिकी में प्रगति के कारण है। कोच और लोकोमोटिव अब घरेलू स्तर पर निर्मित होते हैं, जिससे आयात पर निर्भरता कम होती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत रेलवे उपकरणों के एक प्रमुख निर्यातक के रूप में उभरा है। भारत ऑस्ट्रेलिया को मेट्रो कोच और इंग्लैंड, सऊदी अरब और फ्रांस को ट्रेन कोच निर्यात करता है। मैक्सिको, स्पेन, जर्मनी और इटली भी भारत से रेलवे से संबंधित उपकरण आयात करते हैं। भारतीय यात्री कोच मोजांबिक और श्रीलंका में इस्तेमाल किए जा रहे हैं और 'मेड इन इंडिया' लोकोमोटिव कई देशों को निर्यात किए जा रहे हैं। यह 'मेक इन इंडिया' पहल के निरंतर विस्तार को दर्शाता है तथा राष्ट्रीय गौरव को मजबूत करता है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि एक मजबूत रेलवे नेटवर्क सुविधा को बढ़ाता है और उद्योगों और कृषि को बढ़ावा देता है, भारत के कई क्षेत्रों को पिछले दशक में पहली बार रेल कनेक्टिविटी मिली है। गुजरात के कई इलाकों में पहले केवल छोटी, धीमी गति वाली ट्रेनें थीं, लेकिन अब कई नैरो-गेज मार्गों का विस्तार किया गया है। दाहोद और वलसाड के बीच नई एक्सप्रेस ट्रेन सहित कई रेल मार्गों के उद्घाटन से आदिवासी क्षेत्र को बहुत लाभ होगा।

उन्होंने कहा कि दाहोद की रेल फैक्ट्री 9,000 हॉर्स पावर के इंजनों का निर्माण करेगी, जिससे भारत की ट्रेनों की शक्ति और क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। दाहोद में बनने वाले हर इंजन पर शहर का नाम होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले वर्षों में सैकड़ों इंजन बनाए जाएंगे, जिससे स्थानीय युवाओं के लिए पर्याप्त रोजगार पैदा होगा। यह कारखाना रेलवे के पुर्जे बनाने वाले छोटे उद्योगों को भी समर्थन देगा, जिससे आसपास के क्षेत्रों में आर्थिक विकास होगा। रोजगार के अवसर फैक्ट्री से परे भी हैं, जिससे किसानों, पशुपालकों, दुकानदारों और मजदूरों को लाभ मिलता है तथा व्यापक आर्थिक प्रगति सुनिश्चित होती है।

उन्होंने कहा कि दाहोद, वडोदरा, गोधरा, कलोल और हलोल ने सामूहिक रूप से गुजरात में एक उच्च तकनीक इंजीनियरिंग और विनिर्माण गलियारा स्थापित किया है। वडोदरा भारत के पहले गति शक्ति विश्वविद्यालय का भी घर है। सावली में पहले से ही एक प्रमुख रेल-कार निर्माण कारखाना है। यह राष्ट्र के लिए गौरवशाली उपलब्धि है।

प्रधानमंत्री ने सोन नगर-मोहम्मद गंज के बीच तीसरी रेल लाइन राष्ट्र को किया समर्पित



सोन नगर-मोहम्मद गंज के बीच तीसरी रेल लाइन राष्ट्र को समर्पित करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी। इस अवसर पर बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दिनांक 30 मई, 2025 को बिहार के काराकाट में ₹1,330 करोड़ की लागत वाली सोन नगर-मोहम्मद गंज के बीच तीसरी रेल लाइन राष्ट्र को समर्पित किया, साथ ही हार्डिंग पार्क, पटना में 5 टर्मिनल प्लेटफॉर्म का शिलान्यास किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने बिहार के रेलवे बुनियादी ढाँचे में आए बदलाव का उल्लेख करते हुए कहा कि छपरा, मुजफ्फरपुर और कटिहार जैसे क्षेत्रों में काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। सोन नगर और अंडाल के बीच मल्टीट्रैकिंग का काम चल रहा है, जिससे ट्रेनों की आवाजाही में काफी सुधार होगा। यह रेल यात्रियों के लिए बड़ा उपहार साबित होगा। अब सासाराम में 100 से अधिक ट्रेनें रुकती हैं, जो इस क्षेत्र की बढ़ती कनेक्टिविटी को दर्शाता है। साथ ही रेलवे नेटवर्क को आधुनिक बनाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं।

कानपुर का पनकी धाम रोड ओवर ब्रिज जनता को समर्पित



कानपुर में आरओबी का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी। इस अवसर पर उपस्थित रहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दिनांक 30 मई, 2025 को कानपुर के कल्याणपुर पनकी पावर हाउस रेलवे क्रॉसिंग और पनकी धाम क्रॉसिंग पर रेल ओवर रेल का भी उद्घाटन किया। इससे पनकी थर्मल पावर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट के लॉजिस्टिक्स को कोयला और तेल परिवहन की सुविधा मिलेगी और स्थानीय लोगों के लिए यातायात में भीड़भाड़ से राहत मिलेगी।

प्रधानमंत्री ने कहा, फर्रुखाबाद-अनवरगंज खंड में सिंगल-लाइन रेलवे ट्रैक के कारण कानपुर के निवासियों को लंबे समय से चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। उन्होंने कहा कि यात्रियों को 18 रेलवे क्रॉसिंग के बार-बार बंद होने से यात्रा बाधित होती थी। उन्होंने घोषणा की कि इस क्षेत्र में एलिवेटेड रेल कॉरिडोर के निर्माण में ₹1,000 करोड़ का निवेश किया जाएगा, जिससे यातायात में उल्लेखनीय सुधार होगा, गति बढ़ेगी और प्रदूषण में कमी आएगी। तथा कानपुर के लोगों का कीमती समय बचेगा।

प्रधानमंत्री ने कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन के चल रहे परिवर्तन को रेखांकित करते हुए कहा कि इसे विश्व स्तरीय सुविधा में अपग्रेड किया जा रहा है। जल्द ही, स्टेशन आधुनिक सुविधाओं और बुनियादी ढाँचे से लैस होगा, जो किसी हवाई अड्डे जैसा दिखाई देगा। सरकार अमृत भारत रेलवे स्टेशन पहल के तहत उत्तर प्रदेश में 150 से अधिक रेलवे स्टेशनों का विकास कर रही है, जिससे कनेक्टिविटी और यात्रा सुविधा में और वृद्धि होगी।

प्रधानमंत्री ने सिवान में नई वैशाली-देवरिया रेल परियोजना का किया उद्घाटन और नई ट्रेन सेवाओं को दिखाई हरी झंडी



सिवान में पाटलिपुत्र और गोरखपुर के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी। साथ में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार

दिनांक 20 जून, 2025 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सिवान, बिहार में ₹400 करोड़ से अधिक की लागत वाली वैशाली-देवरिया नई रेल लाइन परियोजना का उद्घाटन किया और वैशाली-देवरिया नई ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाई। इसके अतिरिक्त, उत्तर बिहार में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ने मुजफ्फरपुर और बेतिया के रास्ते पाटलिपुत्र और गोरखपुर के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाई।

'मेक इन इंडिया-मेक फॉर द वर्ल्ड' विजन को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री ने गिनी गणराज्य को निर्यात के लिए मढ़ौरा फैक्ट्री में निर्मित अत्याधुनिक लोकोमोटिव को भी हरी झंडी दिखाई। यह इस कारखाने में निर्मित पहला निर्यात लोकोमोटिव है। वे उच्च-हॉर्सपावर इंजन, उन्नत एसी प्रणोदन प्रणाली, माइक्रोप्रोसेसर-आधारित नियंत्रण प्रणाली, एर्गोनोमिक कैब डिज़ाइन से सुसज्जित हैं और पुनरुत्पादक ब्रेकिंग जैसी तकनीकों को शामिल करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार में एनडीए के विकास मॉडल के एक प्रमुख उदाहरण के रूप में मढ़ौरा लोकोमोटिव फैक्ट्री का हवाला दिया। उन्होंने बताया कि मढ़ौरा फैक्ट्री में निर्मित पहला इंजन अफ्रीका को निर्यात किया जा रहा है, जो एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि यह कारखाना सारण जिले में है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार को लगातार नई ट्रेनें मिल रही हैं, जिनमें अत्याधुनिक वंदे भारत ट्रेनें भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने एक बड़ी उपलब्धि की घोषणा करते हुए कहा कि सावन की शुरुआत से पहले बाबा हरिहरनाथ की धरती अब नई वंदे भारत एक्सप्रेस के माध्यम से बाबा गोरखनाथ की धरती से जुड़ गई है। उन्होंने कहा कि नई पटना-गोरखपुर वंदे भारत ट्रेन पूर्वांचल में भगवान शिव के भक्तों को आधुनिक यात्रा का विकल्प देगी। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि यह ट्रेन भगवान बुद्ध की तपस्थली और उनके महापरिनिर्वाण स्थल कुशीनगर के बीच एक महत्त्वपूर्ण कड़ी का काम भी करती है।

ओडिशा को दो नई ट्रेन सेवाओं सहित कई रेल परियोजनाओं की सौगात

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दिनांक 20 जून, 2025 को भुवनेश्वर में ओडिशा सरकार के एक वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह के दौरान राज्य को कई महत्त्वपूर्ण रेल परियोजनाओं की सौगात दी। कार्यक्रम में उन्होंने सरला-साशन तीसरी और चौथी रेल लाइन का शिलान्यास और सोनपुर-पुरुणाकटक नई रेल लाइन का उद्घाटन किया, जो खोरधा रोड-बलांगीर रेल परियोजना का हिस्सा है।

प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर सरला में फ्रेट ट्रेन मेंटेनेंस फैसिलिटी, बामड़ा-धारुआडीही खंड के बीच सब-वे, डुमेत्रा लिंक-सी (बंडामुंडा-रांची दोहरीकरण परियोजना का भाग), जलेश्वर में रोड ओवर ब्रिज और झारसुगुड़ा-जामगा चौथी रेल लाइन (झारसुगुड़ा-बिलासपुर के बीच 206 कि.मी. लंबे सेक्शन का हिस्सा) राष्ट्र को समर्पित किया। रेल कनेक्टिविटी को और सुदृढ़ करते हुए प्रधानमंत्री ने सोनपुर-पुरुणाकटक-बौद्ध नए सेक्शन को जोड़ने वाली बौद्ध-भुवनेश्वर एक्सप्रेस ट्रेन सेवा और पुरुणाकटक-सोनपुर-बलांगीर पैसेंजर ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।



बौध जिले में पहली बार रेल संपर्क बढ़ाने वाली नई ट्रेन सेवाओं को हरी झंडी दिखाते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी। इस अवसर पर ओडिशा के राज्यपाल डॉ. हरि बाबू कंभमपति, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान उपस्थित रहे

इस कार्यक्रम में ओडिशा के राज्यपाल डॉ. हरि बाबू कंभमपति, मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी, केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम और धर्मेंद्र प्रधान सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

आंध्र प्रदेश में कई रेल विकास कार्यों का शिलान्यास एवं उद्घाटन



आंध्र प्रदेश में रेल विकास कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल सैयद अब्दुल नजीर, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू भी उपस्थित थे

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दिनांक 2 मई, 2025 को आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में आयोजित एक कार्यक्रम में राष्ट्र को रेल परियोजनाएँ समर्पित कीं, जिनका उद्देश्य कनेक्टिविटी और क्षमता को बढ़ाना है। इन परियोजनाओं में गुंतकल वेस्ट और मल्लप्प गेट स्टेशनों को जोड़ने वाली रेल ओवर रेल, बुग्गानपल्ली सीमेंट नगर और पान्यम स्टेशनों के बीच रेल लाइन का दोहरीकरण और रायलसीमा-अमरावती के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाना और न्यू वेस्ट ब्लॉक हट केबिन और विजयवाड़ा स्टेशनों के बीच तीसरी रेल लाइन का निर्माण शामिल है।

इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा, तेजी से विकास करने वाले देशों ने अपने रेलवे नेटवर्क को बहुत महत्त्व दिया है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि पिछला दशक भारतीय रेल के लिए परिवर्तनकारी अवधि रहा है, जिसमें भारत सरकार ने आंध्र प्रदेश में रेलवे विकास के लिए रिकॉर्ड धनराशि आवंटित की है। प्रधानमंत्री ने बताया कि वर्ष 2009 से 2014 के बीच, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का संयुक्त रेल बजट ₹900 करोड़ से कम था, जबकि आज अकेले आंध्र प्रदेश का रेल बजट ₹9,000 करोड़ से अधिक है, जो दस गुना से अधिक की वृद्धि को दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने कहा, 'बढ़े हुए रेल बजट के साथ, आंध्र प्रदेश ने 100% रेलवे विद्युतीकरण हासिल किया है।' उन्होंने कहा कि राज्य अब आठ जोड़ी आधुनिक वंदे भारत ट्रेनों के साथ-साथ अमृत भारत ट्रेन का संचालन करता है, जो आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। पिछले 10 वर्षों में, राज्य भर में 750 से अधिक रेल फ्लाईओवर और अंडरपास का निर्माण किया गया है। इसके अतिरिक्त, प्रधानमंत्री ने कहा कि अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश में 70 से अधिक रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है, जिससे यात्रियों के लिए विश्व स्तरीय बुनियादी ढाँचा सुनिश्चित होगा।



भारत को लॉजिस्टिक्स पावर बनाने की ऐतिहासिक पहल

कैबिनेट ने चार मल्टी-ट्रैकिंग परियोजनाओं को दी मंजूरी

महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश होंगे लाभान्वित

अनुमानित लागत **9,804** करोड़

ट्रैक की लंबाई **494** कि.मी.

लाभान्वित आबादी **~47.93** लाख

11 जिले

165 लाख मानव-दिवस का रोजगार

2192 लाभान्वित गाँव

67.4 एमटीपीए अतिरिक्त माल ढुलाई क्षमता

भारतीय रेल को आधुनिक, कुशल और पर्यावरण-अनुकूल बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने चार महत्त्वपूर्ण मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिनकी कुल अनुमानित लागत ₹9,804 करोड़ है।

इन परियोजनाओं से न केवल रेलवे की परिचालन क्षमता में वृद्धि होगी, बल्कि यह कदम 'पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान', 'विकसित भारत 2047' और 'आत्मनिर्भर भारत' के विजन को भी मजबूती प्रदान करेगा।

अनुमोदित परियोजनाएँ एवं स्थान

क्र.सं.	परियोजना	राज्य	लंबाई (कि.मी.)
1	रतलाम-नागदा तीसरी और चौथी लाइन	मध्य प्रदेश	176 कि.मी.
2	वर्धा-बल्हारशाह चौथी लाइन	महाराष्ट्र	
3	कोडरमा-बरकाकाना दोहरीकरण	झारखंड	133 कि.मी.
4	बेल्लारी-चिकजाजुर दोहरीकरण	कर्नाटक और आंध्र प्रदेश	185 कि.मी.



आर्थिक व सामाजिक प्रभाव

- 165 लाख मानव-दिवसों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार, स्वरोजगार और प्रशिक्षण के अवसरों में वृद्धि होगी।
- माल ढुलाई क्षमता में 67.4 मिलियन टन/वर्ष की वृद्धि, जिससे उद्योगों को अधिक तेज और किफायती परिवहन सुविधा मिलेगी।
- **ग्रामीण संपर्क में सुधार :** कुल 2,192 गांवों को बेहतर कनेक्टिविटी।
- **लाभार्थी जनसंख्या :** लगभग 47.93 लाख ग्रामीण नागरिक।

पर्यावरणीय तथा ऊर्जा संरक्षण प्रभाव

- 72 करोड़ लीटर डीजल की बचत, जिससे तेल आयात पर निर्भरता में उल्लेखनीय कमी।
- 264+99 = 363 करोड़ किलोग्राम CO_2 उत्सर्जन में कमी, जो 15 करोड़ पेड लगाने के बराबर है।
- रेलवे एक ग्रीन मोड : सड़क परिवहन की तुलना में रेलवे 70% कम CO_2 उत्सर्जन करता है।

लॉजिस्टिक तथा औद्योगिक लाभ

- प्रमुख औद्योगिक व खनिज बेल्टों (कोयला, लौह अयस्क, स्टील, सीमेंट, पेट्रोलियम, कंटेनर, कृषि वस्तुएँ आदि) से होकर गुजरने वाली परियोजनाएँ।
- कनेक्टिविटी में सुधार से औद्योगिक उत्पादन, आपूर्ति श्रृंखला और निर्यात को मिलेगा प्रोत्साहन।
- रेल नेटवर्क की बॉटल-नेक्स हटेंगी, जिससे ट्रेनों की पंचुअलिटी और फ्रेट टर्नअराउंड टाइम में सुधार होगा।

पीएम गति शक्ति योजना के अंतर्गत बहु-मॉडल संपर्क

ये सभी परियोजनाएँ पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अंतर्गत हैं, जो सड़क, बंदरगाह, रेलवे, हवाई अड्डा, जलमार्ग और लॉजिस्टिक हब को एकीकृत और दक्ष नेटवर्क में जोड़ने का रोडमैप है।



रणनीतिक और राष्ट्रीय महत्त्व

- इन परियोजनाओं से देश की आंतरिक सुरक्षा व सामरिक क्षेत्रों में लॉजिस्टिक सपोर्ट भी बेहतर होगा।
- पूर्वी और दक्षिणी भारत को उत्तर-पश्चिम भारत से जोड़ने वाली लाइनों में सुधार से सांस्कृतिक और आर्थिक एकता को बल मिलेगा।
- ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में विकास की गति तेज होगी, जिससे न्यायसंगत क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलेगा।

निष्कर्ष

इन चार मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं से भारतीय रेल को गति, शक्ति और संतुलन तीनों मिलेंगे। ये न केवल माल और यात्री परिवहन को सशक्त बनाएंगे, बल्कि 'सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास' की अवधारणा को धरातल पर उतारते हुए टिकाऊ और समावेशी विकास को भी साकार करेंगे।

इन परियोजनाओं का पूर्ण होना भारत को एक लॉजिस्टिक सुपरपावर बनाने की दिशा में निर्णायक कदम सिद्ध होगा।

भैरबी-साईरंग रेलवे परियोजना

साईरंग, आइजोल तक का ट्रायल रन सफल

पूर्वोत्तर सीमा रेलवे (पू. सी. रेलवे) ने दिनांक 1 मई, 2025 को मिजोरम में साईरंग, आइजोल तक पहली बार सफलतापूर्वक ट्रायल रन कर एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। यह पूर्वोत्तर राज्य में रेल कनेक्टिविटी बढ़ाने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है। यह मिजोरम को राष्ट्रीय रेलवे नेटवर्क से राजधानी कनेक्टिविटी को जोड़ने वाला चौथा पूर्वोत्तर राज्य बनाता है।

यह ऐतिहासिक ट्रायल रन पू. सी. रेलवे के महाप्रबंधक (निर्माण) अरुण कुमार चौधरी तथा अन्य वरिष्ठ रेल अधिकारियों की उपस्थिति में किया गया। साईरंग में सफल ट्रायल रन के बाद, चौधरी ने मिजोरम के राज्यपाल जनरल (डॉ.) विजय कुमार सिंह तथा मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदुहोमा को भैरबी-साईरंग रेलवे परियोजना के क्षेत्र, प्रगति तथा रणनीतिक महत्त्व पर जानकारी दी।





51.38 कि.मी. लंबी भैरबी-साईरंग नई लाइन रेलवे परियोजना भारतीय रेल का एक इंजीनयरिंग चमत्कार है। इस परियोजना में 48 सुरंगें, 55 बड़े ब्रिज और 87 छोटे ब्रिज शामिल हैं। इस परियोजना में सुरंगों की कुल लंबाई 12,853 मीटर है। ब्रिज संख्या 196 की ऊँचाई 104 मीटर है, जो कुतुबमीनार से 42 मीटर ऊँची है। इस परियोजना में 5 रोड ओवर ब्रिज और 6 रोड अंडर ब्रिज भी शामिल हैं। यह नई लाइन परियोजना चार सेक्शनों में विभाजित है, अर्थात् भैरबी-हरतकी, हरतकी-कौनपुई, कौनपुई-मुआलखांग और मुआलखांग-साईरंग।

भारतीय रेल ने सैरांग (अइजोल) तक अपनी पहली परीक्षण यात्रा सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। इससे अइजोल पूर्वोत्तर की चौथी राजधानी बनने जा रही है जो रेलवे नेटवर्क से जुड़ने वाली है, यह उपलब्धि मिजोरम की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगी और राज्य के विकास के नए रास्ते खोलेगी।

छत्रपति शिवाजी महाराज भारत गौरव पर्यटक

ट्रेन को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने दिखाई हरी झंडी

दिनांक 9 जून, 2025 को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी), मुंबई से छत्रपति शिवाजी महाराज भारत गौरव विशेष पर्यटक ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, महाराष्ट्र सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी और सांस्कृतिक मामलों के मंत्री अशीष शेलार, मध्य रेलवे के महाप्रबंधक धर्मवीर मीणा, आईआरसीटीसी के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक राहुल हिमालियन (टूरिज्म मार्केटिंग निदेशक) तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे। यह ट्रेन भारत की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत से रूबरू कराने के उद्देश्य से चलाई गई है।



रतलाम नागदा तीसरी और चौथी रेल लाइन परियोजना को मिली स्वीकृति

केंद्रीय रेल, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिनांक 29 मई, 2025 को नई दिल्ली स्थित रेल भवन में मीडिया से बातचीत की। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा हाल ही में स्वीकृत रतलाम और नागदा के बीच तीसरी और चौथी रेल लाइन परियोजना के मुख्य विवरण साझा करते हुए, रेल मंत्री ने परियोजना के प्रमुख पहलुओं और मौजूदा रेल लाइनों पर भीड़भाड़ कम करने, माल ढुलाई और यात्री यातायात दक्षता बढ़ाने, महत्त्वपूर्ण आर्थिक गलियारों में कनेक्टिविटी मजबूत करने तथा इसके पूरा होने की लक्षित समयसीमा पर प्रकाश डाला।

उन्होंने बताया कि उच्च-घनत्व नेटवर्क का हिस्सा 41.4 कि.मी. का रतलाम-नागदा खंड ₹1,018 करोड़ की लागत से चार-लाइन वाला होगा, जिससे लाइन क्षमता उपयोग 116% से घटकर 65% रह जाएगा। यह नागदा (उत्तर), वडोदरा (दक्षिण), इंदौर (पूर्व) और चित्तौड़गढ़ (पश्चिम) जैसे प्रमुख जंक्शनों को जोड़ेगा, जो क्षेत्रीय और राष्ट्रीय संपर्क में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

यह परियोजना मध्य प्रदेश से कांडला, मुंद्रा, पिपावाव, हजीरा, दहेज, जेएनपीए और प्रस्तावित वधावन बंदरगाह जैसे प्रमुख पश्चिमी तट बंदरगाहों तक माल की आवाजाही को बढ़ाएगी, जिससे मध्य और उत्तरी आर्थिक क्षेत्रों तक पहुँच बढ़ेगी। इससे इंदौर एसईजेड, छिंदवाड़ा एसईजेड, एमएमपीएल इंदौर, एमएमएलपी भोपाल, दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारा और नागदा थर्मल पावर प्लांट जैसे प्रमुख औद्योगिक केन्द्रों और रतलाम क्षेत्र में संबंधित विस्कोस और रासायनिक उद्योगों को सीधा लाभ होगा।

रेल मंत्री ने बताया कि इस बुनियादी ढाँचे के आधुनिकीकरण से कृषि वस्तुओं, कोयला, कंटेनर और पेट्रोलियम उत्पादों का तेज और अधिक कुशल परिवहन हो सकेगा। खजुराहो, ग्वालियर, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, सांची स्तूप, उज्जैन, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, अमरकंटक और भीम जन्मभूमि जैसे विरासत और धार्मिक स्थलों तक बेहतर पहुँच के साथ मध्य प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।

इस परियोजना से 28 लाख मानव-दिवस रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। पहले वर्ष में 38 करोड़ किलोग्राम कार्बनडाइक्साइड उत्सर्जन कम होगा, जिसमें पर्यावरणीय स्थिरता में योगदान मिलेगा- जो 1.5 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर है- और 11वें वर्ष तक 16.5 करोड़ से अधिक पेड़ों के बराबर की बचत होगी। इसके अतिरिक्त, 7.5 करोड़ लीटर डीजल की बचत होगी। वधावन बंदरगाह के चालू होने के बाद, माल यातायात पहले वर्ष में 7 मीट्रिक टन प्रति वर्ष से बढ़कर 11वें वर्ष तक 76.4 मीट्रिक टन प्रति वर्ष हो जाने का अनुमान है, जिससे भारत की रसद और औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मकता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।



मंत्री ने यह भी बताया कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत मध्य प्रदेश में 80 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है, जिसमें आधुनिक यात्री सुविधाएँ, बेहतर सौंदर्य और सुविधाएँ शामिल हैं। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के लिए बजटीय आवंटन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और राज्य सरकार के साथ घनिष्ठ समन्वय में परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। रेलवे अगले एक से दो वर्षों के भीतर राज्य में सभी प्रमुख रेलवे परियोजनाओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे कनेक्टिविटी और क्षेत्रीय विकास पर परिवर्तनकारी प्रभाव सुनिश्चित होगा।

वैष्णव ने तीन नई रेलगाड़ियाँ शुरू करने की घोषणा की। नई सेवाओं में जबलपुर और सतना होते हुए रीवा से पुणे तक एक ट्रेन, नैनपुर, बालाघाट और गोंदिया होते हुए जबलपुर से रायपुर तक दूसरी ट्रेन तथा गुना और भोपाल होते हुए ग्वालियर से बेंगलुरु तक तीसरी ट्रेन शामिल है। इन ट्रेनों का संचालन अगले दो महीनों में शुरू होने की उम्मीद है।

उज्जैन में आगामी सिंहस्थ कुंभ मेला वर्ष 2028 की तैयारियों के बारे में रेल मंत्री ने कहा कि रेल मंत्रालय ने श्रद्धालुओं की अपेक्षित भारी भीड़ को देखते हुए व्यापक योजना बनानी शुरू कर दी है। उन्होंने आश्वासन दिया कि इस बड़े आयोजन के लिए रेलवे की तैयारियों के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा बैठकें आयोजित की जाएंगी।

इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। उज्जैन (सुरक्षित) लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सांसद अनिल फिरोजिया रेल भवन में मौजूद थे। रतलाम सिटी विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले मध्य प्रदेश सरकार के एमएसएमई मंत्री चैतन्य कश्यप, रतलाम लोकसभा क्षेत्र की सांसद अनीता नागर सिंह चौहान, रतलाम ग्रामीण (सुरक्षित) विधानसभा क्षेत्र के विधायक मथुरा लाल डामर, और नागदा-खचरोड़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉ. तेजबहादुर सिंह चौहान भी मौजूद थे।

रेल मंत्री ने जमालपुर लोकोमोटिव वर्कशॉप में वैगन पीओएच क्षमता वृद्धि परियोजना की रखी आधारशिला



जमालपुर वर्कशॉप में विस्तृत विकास योजना पुस्तिका 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' का विमोचन करते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति

केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिनांक 23 मई, 2025 को जमालपुर लोकोमोटिव वर्कशॉप में वैगन पीओएच (पीरियॉडिक ओवरहॉलिंग) क्षमता वृद्धि परियोजना की आधारशिला रखी। यह परियोजना लगभग ₹79 करोड़ की लागत से विकसित की जाएगी, जिससे वर्तमान 545 वैगनों की मरम्मत क्षमता बढ़ाकर 800 प्रति माह की जा सकेगी।

इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, स्थानीय विधायकगण, पूर्व मध्य रेल के महाप्रबंधक छत्रसाल सिंह तथा पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक मिलिंद देउस्कर सहित कई वरिष्ठ अधिकारी एवं गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

रेल मंत्री ने अपने दौरे की शुरुआत पटना से की, जहाँ उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात कर राज्य में रेल परियोजनाओं पर चर्चा की। इसके उपरांत उन्होंने पटना से जमालपुर तक विंडो ट्रेलिंग निरीक्षण करते हुए रेल पथ, स्टेशन तथा अन्य ढाँचागत सुविधाओं की समीक्षा की।

जमालपुर स्टेशन पर रेल मंत्री ने ₹30 करोड़ की लागत से चल रहे पुनर्विकास कार्यों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य के निर्देश दिए। इसके पश्चात् जमालपुर वर्कशॉप का दौरा करते हुए उन्होंने वैगन निर्माण शॉप, क्रेन शॉप और अन्य महत्त्वपूर्ण इकाइयों का अवलोकन किया। उन्होंने वर्कशॉप में निर्मित बॉक्सएन वैगन, बीएलसीएस वैगन, शौचालय युक्त ब्रेक वैन, 140 टन क्रेन, 8-व्हीलर टावर कार एवं जमालपुर जैक जैसे उत्पादों की सराहना की। जमालपुर स्थित इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग (IRIMEE) में 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' नामक विस्तृत विकास योजना पुस्तिका का विमोचन करते हुए रेल मंत्री ने कहा कि ₹350 करोड़ की अनुमानित लागत से जमालपुर स्टेशन, वर्कशॉप और प्रशिक्षण संस्थान का समेकित विकास किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत वेल्डिंग, हाइड्रोलिक्स, न्यूमेटिक्स तथा मेक्ट्रोनिक्स जैसे विषयों में अत्याधुनिक प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। वर्ष 2026 से इस संस्थान में रेलवे अधिकारियों के अतिरिक्त बाहरी प्रतिभागियों के लिए भी स्किल डेवलपमेंट प्रशिक्षण प्रारंभ किया जाएगा, जिससे यह केंद्र राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट इंजीनियरिंग शिक्षा संस्थान के रूप में प्रतिष्ठित होगा।

रेल मंत्री ने अपने संबोधन में बताया कि वर्ष 2009-14 के दौरान बिहार में रेलवे के लिए जहाँ प्रतिवर्ष औसतन ₹1,132 करोड़ आवंटित किए जाते थे, वहीं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में यह राशि बढ़ाकर वित्त वर्ष 2024-25 में ₹10,066 करोड़ कर दी गई है, जो लगभग 9 गुना वृद्धि है। इसी प्रकार, नई रेल लाइनों के निर्माण में भी बड़ा इजाफा हुआ है- वर्ष 2009-14 के दौरान जहाँ औसतन 64 कि.मी. नई लाइनें प्रतिवर्ष बनती थीं, वहीं वर्ष 2014-24 के बीच यह आंकड़ा बढ़कर 167 कि.मी. प्रति वर्ष हो गया है।

रेल मंत्री ने बताया कि वर्ष 2014 से अब तक बिहार में 1,832 कि.मी. नई लाइनें बिछाई जा चुकी हैं, जो मलेशिया के कुल रेल नेटवर्क के समकक्ष है। साथ ही, राज्य में 3,020 कि.मी. ट्रैक का विद्युतीकरण कर 100% विद्युतीकरण कर लिया गया है। इन पहलों से न केवल रेलवे की क्षमता में वृद्धि होगी, बल्कि बिहार के सामाजिक एवं आर्थिक विकास को भी नई गति मिलेगी।

देश के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल गति शक्ति मल्टी-मॉडल कार्गो टर्मिनल का रेल मंत्री ने किया उद्घाटन

केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिनांक 17 जून, 2025 को हरियाणा के मानेसर स्थित मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड में देश के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल गति शक्ति मल्टी-मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया।

मारुति सुजुकी के मानेसर संयंत्र में गति शक्ति कार्गो टर्मिनल एक प्रमुख अवसंरचना विकास है, जो ऑटोमोबाइल परिवहन की दक्षता को महत्त्वपूर्ण रूप से बढ़ाता है। मानेसर स्थित यह संयंत्र 10 कि.मी. के समर्पित रेल लिंक के माध्यम से पटली रेलवे स्टेशन से जुड़ा हुआ है, जो हरियाणा रेल अवसंरचना विकास निगम (एचआरआईडीसी) द्वारा विकसित किए जा रहे 121.7 कि.मी. लंबे हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर का हिस्सा है। इस 10 कि.मी. के लिंक के निर्माण में ₹800 करोड़ का निवेश हुआ, जिसमें एचआरआईडीसी ने ₹684 करोड़ का योगदान दिया और शेष राशि मारुति सुजुकी द्वारा वित्तपोषित की गई। इस गति शक्ति कार्गो टर्मिनल की लोडिंग क्षमता देश में सबसे अधिक है, यानी प्रति वर्ष 4.5 लाख ऑटोमोबाइल।

सभा को संबोधित करते हुए रेल मंत्री ने पिछले एक दशक में भारतीय रेल में हुए महत्त्वपूर्ण बदलावों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, ''वर्ष 2014 से पहले, भारतीय रेल का वार्षिक बजट ₹24,000-25,000 करोड़ के आसपास रहता था, अब इसे बढ़ाकर ₹2.5 लाख करोड़ कर दिया गया है। कई स्टेशनों और डिब्बों में शौचालय जैसी बुनियादी यात्री सुविधाएँ नदारद थीं। पिछले ढाई साल में सामान्य डिब्बों की संख्या बढ़ाने के लिए एक केंद्रित अभियान शुरू किया गया है। पिछले साल ही 1,200 से ज्यादा सामान्य डिब्बे जोड़े गए हैं।''



रेल मंत्री ने कहा कि हाल ही में यात्री ट्रेन सेवाओं को उन्नत करने के लिए एक बड़ा निर्णय लिया गया है। अब 100 से अधिक मेमू ट्रेनों को बढ़ाया जाएगा, उनकी संरचना को 8 से 12 डिब्बों से बढ़ाकर 16 से 20 डिब्बे किया जाएगा, जिससे कम दूरी के यात्रियों को बहुत लाभ होगा। 100 से अधिक मेमू ट्रेनों के निर्माण के लिए आंध्र प्रदेश के काजीपेट में एक नया कारखाना स्थापित किया गया है।



हरियाणा के मानेसर स्थित मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड में देश के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल गति शक्ति मल्टी-मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन करते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव एवं अन्य गणमान्य अतिथि

नमो भारत ट्रेनों की सफल शुरुआत का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा, ''चल रही दो नमो भारत ट्रेनों के प्रति जनता की मजबूत प्रतिक्रिया से उत्साहित होकर, हमने बढ़ती यात्री मांग को पूरा करने के लिए 50 नई नमो भारत ट्रेनें बनाने का फैसला किया है।''

यात्री और माल ढुलाई के प्रदर्शन के मोर्चे पर मंत्री ने कहा, ''वित्त वर्ष 2023-24 में भारतीय रेल ने लगभग 720 करोड़ यात्रियों और 1,617 मिलियन टन माल का परिवहन किया। इस प्रदर्शन ने भारतीय रेल को विश्व स्तर पर दूसरी सबसे अधिक माल ढुलाई मात्रा हासिल करने में मदद की, जिससे वित्त वर्ष 2023-24 एक ऐतिहासिक वर्ष बन गया।''

वैष्णव ने यात्री सुविधा के बारे में बात करते हुए तत्काल टिकट बुकिंग में एक महत्त्वपूर्ण सुधार की घोषणा की, जिसे दिनांक 1 जुलाई, 2025 से लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा, "नए नियम के अनुसार, केवल आधार-प्रमाणित और केवाईसी-सत्यापित उपयोगकर्ताओं को बुकिंग विंडो के पहले 30 मिनट के दौरान तत्काल टिकट बुक करने की अनुमति होगी। इस उपाय से यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि टिकट वास्तविक यात्रियों को ही उपलब्ध हों।''

उन्होंने बीकानेर मंडल में चल रही एक पायलट परियोजना के बारे में भी बताया, जहाँ अब यात्री आरक्षण चार्ट 24 घंटे पहले तैयार किए जा रहे हैं, जबकि पहले यह ट्रेन के रवाना होने से 4 घंटे पहले तैयार किया जाता था। इस पहल को नागरिकों और जन प्रतिनिधियों से काफी सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है और इससे यात्रा के अनुभव में उल्लेखनीय सुधार होने की उम्मीद है।

अमृत भारत ट्रेनों की शुरुआत पर चर्चा करते हुए रेल मंत्री ने कहा, ''तीन अमृत भारत ट्रेनें वर्तमान में चालू हैं और उन्हें जनता से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है। आने वाले दिनों में छह और अमृत भारत ट्रेनें शुरू की जाएंगी। इसके अलावा, 50 और ट्रेनों का उत्पादन चल रहा है तथा आगे और अधिक बैच आएंगे।''

हरियाणा में विकास की चर्चा करते हुए रेल मंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 से पहले राज्य के लिए वार्षिक रेल बजट आवंटन मात्र ₹300 करोड़ था। उन्होंने कहा, ''इस वर्ष, हरियाणा को ₹3,416 करोड़ का रिकॉर्ड आवंटन प्राप्त हुआ है। पिछले 11 वर्षों में, राज्य में 823 कि.मी. नई रेल लाइनें बिछाई गई हैं और हरियाणा का शत-प्रतिशत रेलवे नेटवर्क अब विद्युतीकृत है।''

उन्होंने कहा, ''वर्तमान में, हरियाणा में ₹11,800 करोड़ की परियोजनाएँ चल रही हैं। 'अमृत भारत स्टेशन योजना' के तहत 34 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास प्रगति पर है। इसके अलावा, राज्य के रेलवे नेटवर्क में 540 रोड ओवरब्रिज और अंडरपास का निर्माण किया गया है।''

रेल मंत्री ने कहा कि सोनीपत स्थित रेलवे कोच फैक्ट्री का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा, ''उन्नत की गई सुविधा जल्द ही उद्घाटन के लिए तैयार हो जाएगी और हमारी कोच उत्पादन क्षमता को बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।''

इस कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, राज्य के उद्योग मंत्री राव नरबीर सिंह, विधायक मुकेश शर्मा और मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के सीईओ एवं प्रबंध निदेशक हिसाशी ताकेउची की उपस्थिति रही।

जोधपुर रेलवे स्टेशन पर जल्द मिलेंगी विश्वस्तरीय सुविधाएँ



दिनांक 5 मई, 2025 को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जोधपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। ₹474 करोड़ की अनुमानित लागत से हो रहे इस कार्य का उद्देश्य जोधपुर की समृद्ध ऐतिहासिक विरासत को सुरक्षित रखते हुए यात्रियों को अत्याधुनिक सुविधाएँ प्रदान करना है।

इस अवसर पर मीडिया से बातचीत में रेल मंत्री ने कहा कि पुनर्विकास परियोजना के पूर्ण होने के पश्चात् जोधपुर रेलवे स्टेशन एक भव्य स्वरूप लेगा और यात्रियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाएँ प्राप्त होंगी। उन्होंने बताया कि इस परियोजना के अंतर्गत दो प्रमुख पहलुओं को ध्यान में रखा गया है- पहला, स्टेशन के दोनों ओर बढ़ते शहरी विस्तार के अनुरूप द्वितीय प्रवेश द्वार को अधिक सुविधाजनक बनाना और स्टेशन तक पहुँच को सुगम बनाने हेतु एक एलिवेटेड रोड का निर्माण, जिससे यातायात सुचारू हो सके और पर्याप्त पार्किंग की सुविधा उपलब्ध कराई जा सके।

स्टेशन पर एक आधुनिक एयर कोनकोर्स एवं रूफ प्लाजा का भी निर्माण प्रस्तावित है, जो यात्रियों को आरामदायक प्रतीक्षा स्थल प्रदान करेगा। यह परियोजना प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में क्रियान्वित की जा रही 'अमृत भारत स्टेशन योजना' का हिस्सा है। इस अवसर पर जोधपुर मंडल के मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी सहित वरिष्ठ अधिकारीगण भी उपस्थित रहे।

ग्वालियर-बेंगलुरु नई साप्ताहिक ट्रेन प्रारंभ

मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के यात्रियों को सीधी कनेक्टिविटी









केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ग्वालियर से बेंगलुरु के लिए शुरू की गई नई साप्ताहिक ट्रेन का शुभारंभ किया। उन्होंने इस अवसर पर रेल भवन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मध्य प्रदेश की जनता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यह ट्रेन ग्वालियर, गुना, भोपाल सहित मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के यात्रियों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगी, जहाँ से बड़ी संख्या में लोग बेंगलुरु की ओर यात्रा करते हैं।

रेल मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में रेलवे के क्षेत्र में ऐतिहासिक प्रगति हुई है। एक दशक पूर्व जहाँ राज्य को ₹600 करोड़ के आसपास रेल बजट प्राप्त होता था, वहीं वर्तमान में ₹14,745 करोड़ का रेल बजट आवंटित किया गया है। मध्य प्रदेश में 100 प्रतिशत रेल विद्युतीकरण पूर्ण किया जा चुका है। बीते 11 वर्षों में राज्य में 2,651 कि.मी. नई रेल पटरियाँ बिछाई गई हैं, जो डेनमार्क जैसे देश के कुल रेल नेटवर्क से भी अधिक है। राज्य में 80 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास कार्य प्रगति पर है, जिनमें ग्वालियर स्टेशन का विकास विशेष वास्तुकला के साथ किया जा रहा है।



रेल मंत्री ने बताया कि ग्वालियर और आगरा के बीच एक नई यात्री ट्रेन सेवा शुरू करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही, मध्य प्रदेश में कई महत्त्वपूर्ण रेल परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है। इनमें मनमाड-इंदौर नई रेललाइन (309 कि.मी.) ₹18,036 करोड़ की लागत से, भुसावल-खंडवा तीसरी और चौथी लाइन ₹3,514 करोड़ की लागत से, मानिकपुर-प्रयागराज तीसरी लाइन ₹1,640 करोड़ में तथा रतलाम-नागदा तीसरी और चौथी लाइन ₹1,018 करोड़ की लागत से शामिल हैं। बीते एक वर्ष में राज्य में ₹24,000 करोड़ की रेल परियोजनाएँ स्वीकृत की गई हैं, जो मध्य प्रदेश के रेल मानचित्र को पूरी तरह बदल देंगी।

सिंहस्थ कुंभ की तैयारियों का उल्लेख करते हुए रेल मंत्री बताया कि उज्जैन स्टेशन के पुनर्विकास के लिए मास्टर प्लान तैयार है। स्टेशन पर कार्य सिंहस्थ आयोजन के बाद आरंभ किया जाएगा, जिससे यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। उज्जैन के साथ ही इंदौर सहित आसपास के अन्य स्टेशनों पर भी कार्य तेजी से चल रहा है।

इस अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, केंद्रीय संचार तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के विकास मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया, मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर तथा रेलवे के वरिष्ठ अधिकारीगण कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित रहे। कार्यक्रम से मध्य प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर मौजूद जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक तथा आमजन भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़कर सहभागी बने।

रेल मंत्री द्वारा पुरुलिया-हावड़ा के लिए ट्रेन का शुभारंभ



सांतरागाछी रेलवे स्टेशन का दौरा करते हुऐ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव

दिनांक 28 जून, 2025 का रेल, सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सांतरागाछी रेलवे स्टेशन का दौरा किया। इस अवसर पर केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री डॉ. सुकांता मजूमदार, बिष्णुपुर के सांसद सौमित्र खान, हावड़ा के सांसद प्रसून बनर्जी भी उपस्थित रहे। अपनी यात्रा के दौरान, रेल मंत्री ने 'अमृत भारत स्टेशन योजना' के तहत सांतरागाछी स्टेशन के पुनर्विकास कार्यों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के उपरांत, रेल मंत्री ने पुरुलिया से हावड़ा तक मेमू सेवा का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया।

इस अवसर पर अनेक गणमान्य व्यक्ति वर्चुअल माध्यम से जुड़े : पुरुलिया के सांसद ज्योतिर्मय सिंह महतो, विधायक सुदीप कुमार मुखर्जी, बाँकुड़ा के विधायकगण : नीलाद्रि शेखर दाना (बाँकुड़ा), सत्यनारायण मुखोपाध्याय (छातना), अमरनाथ शखा (ओंदा), दिवाकर घरामी (सनमुखी), निर्मल कुमार धारा (इंडस)।

रेल मंत्री ने कहा, हमारे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की दूरदर्शिता ने नए भारतीय रेल की नींव रखी है। इस सपने को साकार करने के लिए रेल परिवार के 12 लाख सदस्य पूरे समर्पण से कार्य कर रहे हैं। केवल पश्चिम बंगाल में ही 101 स्टेशनों पर 'अमृत भारत स्टेशन योजना' के तहत तीव्र गति से कार्य हो रहा है।

यह मार्ग बाँकुड़ा-दामोदर रेलवे की ऐतिहासिक सेवा को पुनर्जीवित करता है, जिसकी शुरुआत वर्ष 1916 में हुई थी, जिसे वर्ष 2005 में ब्रॉड गेज में परिवर्तित किया गया था और वर्ष 2012 में मसाग्राम तक विस्तारित किया गया। वर्ष 2021 में विद्युतीकरण पूर्ण हुआ, जिससे कुशल रेल सेवाएं संभव हो सकीं।

साइलो लोडिंग के कारण थर्मल पावर प्लांट में कोयले का स्टॉक 61.3 मिलियन टन के उच्चतम स्तर पर

कोयला लॉजिस्टिक्स और परिवहन प्रणालियों की दक्षता की समीक्षा करने के लिए दिनांक 24 जून, 2025 को केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी. किशन रेड्डी और केंद्रीय रेल, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव के बीच उच्च स्तरीय बैठक हुई।

चर्चा मुख्य रूप से साइलो लोडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में तेजी लाने पर केंद्रित थी, जो कोयला निकासी की गुणवत्ता और गति को बेहतर बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पिछले कुछ वर्षों में, साइलो के माध्यम से लोड किए गए कोयले की हिस्सेदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो वित्त वर्ष 2022-23 में 18.8% से वित्त वर्ष 2025-26 (दिनांक 24 जून, 2025 तक) में 29% तक पहुँच गई है। मंत्रियों ने प्रमुख कोयला क्षेत्रों में साइलो अवसंरचना के विस्तार के उद्देश्य से चल रही और प्रस्तावित परियोजनाओं की समीक्षा की। बैठक में खदान से लेकर संयंत्र तक निर्बाध संचालन सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय बढ़ाने की आवश्यकता पर भी बल दिया गया। एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में, सभी ताप विद्युत संयंत्रों में कोयले का स्टॉक 61.3 मिलियन टन के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुँच



गया है, जो 25 दिनों की खपत को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। यह रिकॉर्ड भंडार भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करता है, प्रचंड गर्मी के महीनों के दौरान निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करता है।

महाराष्ट्र, तमिलनाडु और राजस्थान के बीच सीधी रेल सेवा का शुभारंभ

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिनांक 3 मई, 2025 को महाराष्ट्र और तमिलनाडु से राजस्थान को जोड़ने वाली दो नई ट्रेनों पुणे (हडपसर)–जोधपुर एक्सप्रेस और एमजीआर चेन्नई सेंट्रल–जोधपुर (भगत की कोठी) एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

रेल मंत्री ने कहा कि आज दुनिया में सबसे बड़ा स्टेशन पुनर्विकास कार्यक्रम भारत में चल रहा है। 1300 रेलवे स्टेशनों के पुनर्निर्माण की परिकल्पना को धरातल पर उतारना एक ऐतिहासिक कार्य है। बीते 10 वर्षों में देश में 34,000 कि.मी. नए रेलवे ट्रैक बिछाए गए हैं, जिसमें डबलिंग, गेज कनवर्जन, तीसरी और चौथी लाइनें शामिल हैं। यह कार्य जर्मनी जैसे देश के कुल रेल नेटवर्क के बराबर है। वंदे भारत ट्रेनों के संदर्भ में उन्होंने कहा कि ये आधुनिक ट्रेनें देश की प्रगति की प्रतीक बन चुकी हैं और जनता में इनका उत्साह देखते ही बनता है। जल्द ही नागपुर से पुणे के बीच वंदे भारत सेवा भी शुरू की जाएगी। पुणे से नगर तक सीधी डबल लाइन परियोजना का कार्य शीघ्र प्रारंभ होगा।

पुणे जंक्शन के पुनर्विकास को लेकर भी रेल मंत्री ने महत्त्वपूर्ण घोषणाएँ कीं। उन्होंने बताया कि हडपसर, खड़की, शिवाजीनगर, अलांदी, उरुली और पुणे जंक्शन को एक समेकित मास्टर प्लान के अंतर्गत विकसित किया जाएगा। इस योजना के तहत चार नए प्लेटफॉर्म बनाए जाएंगे, आधुनिक डिजिटल कंट्रोल सिस्टम लागू होगा और प्रवेश–निकासी की व्यवस्था बेहतर की जाएगी। उन्होंने कहा कि पुणे एक ऐतिहासिक नगरी है, जो छत्रपति शिवाजी महाराज की पुण्यभूमि रही है, इसलिए इसका विकास विशेष गौरव का विषय है। रेल मंत्री ने नासिक में आगामी महाकुंभ की तैयारियों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि प्रयागराज की तर्ज पर नासिक, उज्जैन और राजमुंद्री में भी कुंभ मेले की व्यापक तैयारी रेलवे द्वारा की जा रही है। उन्होंने यह भी बताया कि पिछले वर्ष देशभर में रेलवे ने 1200 से अधिक फ्लाईओवर और अंडरपास बनाकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है।



रेल मंत्री ने दिखाई पुणे–जोधपुर एक्सप्रेस और एमजीआर चेन्नई सेंट्रल–भगत की कोठी एक्सप्रेस को हरी झंडी

इस अवसर पर केंद्रीय सहकारिता और नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल, सांसद मेधा कुलकर्णी, विधायक सुनील कांबले के साथ-साथ केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन, केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, सांसद राजेंद्र गहलोत और विधायक अतुल भंसाली भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहे।

भारतीय रेल / Indian Railways

पत्रिका की सदस्यता एवं पत्रिका नहीं मिलने की शिकायत हेतु

फोन या व्हाट्सएप करें

92205 05349

सोमवार से शुक्रवार (सुबह 10 से 5 बजे तक)

Email: bmpr310rb@gmail.com, irbrhelp@gmail.com

रेलवन

वन-स्टॉप सॉल्यूशन ऐप

यात्रियों को एक ही प्लेटफार्म पर मिल रहा है संपूर्ण समाधान



क्रिस के 40वें स्थापना दिवस पर नए ऐप 'रेलवन' का शुभारंभ करते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। साथ में हैं अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीश कुमार एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिनांक 1 जुलाई, 2025 को नई दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में क्रिस के स्थापना दिवस पर एक नए ऐप, 'रेलवन' का शुभारंभ किया। रेलवन, रेलवे के साथ यात्री संपर्क को बेहतर बनाने पर केंद्रित है।

यह उपयोगकर्ता के अनुकूल इंटरफेस के साथ एक व्यापक, ऑल-इन-वन एप्लिकेशन है। यह ऐप एंड्रॉइड प्ले स्टोर और आईओएस ऐप स्टोर पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। यह सभी यात्री सेवाओं को एकीकृत करता है जैसे कि :

- **अनारक्षित एवं प्लेटफॉर्म टिकट पर 3 प्रतिशत छूट**
- **लाइव ट्रेन ट्रैकिंग**
- **शिकायत निवारण**
- **ई-कैटरिंग, पोर्टर बुकिंग और लास्ट माइल टैक्सी**

आईआरसीटीसी पर टिकटों का आरक्षण जारी रहेगा। आईआरसीटीसी के साथ साझेदारी करने वाले कई अन्य वाणिज्यिक ऐप की तरह ही रेलवन ऐप को भी आईआरसीटीसी द्वारा अधिकृत किया गया है। रेलवन में सिंगल साइन-ऑन की सुविधा है, जिसमें एम-पिन या बायोमिट्रिक के जरिए लॉगिन किया जा सकता है। यह मौजूदा रेलकनेक्ट और यूटीएस क्रेडेंशियल को भी सपोर्ट करता है। यह ऐप स्पेस सेविंग है, क्योंकि इसके कारण उपयोगकर्ताओं को अलग-अलग सेवाओं के लिए अलग-अलग ऐप रखने की जरूरत नहीं पड़ती।

दिसंबर 2025 तक आधुनिक यात्री आरक्षण प्रणाली

रेल मंत्री ने क्रिस की पूरी टीम को उसके स्थापना दिवस पर बधाई दी। उन्होंने क्रिस से भारतीय रेल के डिजिटल कोर को और मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया।

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मौजूदा पीआरएस को अपग्रेड करने की दिशा में हुई प्रगति के लिए क्रिस टीम की सराहना की। आधुनिक पीआरएस तेज, बहुभाषी और मौजूदा लोड से 10 गुना अधिक भार संभालने में सक्षम होगा। इसमें प्रति मिनट 1.5 लाख टिकट बुकिंग और 40 लाख पूछताछ की सुविधा होगी।

नया पीआरएस व्यापक होगा, जिस में सीट चयन, टिकट मूल्य कैलेंडर तथा दिव्यांगजनों, छात्रों और मरीजों के लिए एकीकृत विकल्पों के लिए उन्नत सुविधाएँ होंगी।

प्रौद्योगिकी का सही उपयोग

भारतीय रेल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दृष्टिकोण के साथ काम कर रहा है ताकि इसे भारत की विकास यात्रा का इंजन बनाया जा सके। रेलवन ऐप का लॉन्च भारतीय रेल की प्रौद्योगिकी को लोकतांत्रिक बनाने और हर यात्री को विश्व स्तरीय गतिशीलता प्रदान करने की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।

ट्रेनों के रवाना होने से 8 घंटे पहले आरक्षण चार्ट बनना प्रारम्भ

रेल मंत्री ने समीक्षा बैठक में यात्री सुविधा प्रगति पर दिया जोर

भारतीय रेल ने आरक्षण चार्ट 8 घंटे पहले तैयार करने का निर्णय लेकर यात्रियों को एक बड़ी सौगात दी है। दिनांक 1 जुलाई, 2025 से यह नई व्यवस्था शुरू हो गई है। अब तक ट्रेन के चलने से 4 घंटे पहले आरक्षण चार्ट तैयार किया जाता था, जिससे स्टेशन से दूर-दराज इलाकों में रहने वालों में यात्रा को लेकर अनिश्चितता बनी रहती थी।

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में यात्री सुविधा सुधारों की प्रगति की समीक्षा में टिकट प्रणाली स्मार्ट, पारदर्शी, सुलभ और कुशल होने पर जोर दिया था। उन्होंने कहा था कि योजनाओं में यात्रियों की सुविधा पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। यह प्रणाली हमारे यात्रियों के लिए एक सहज और आरामदायक यात्रा अनुभव सुनिश्चित करेगी।

दिनांक 1 जुलाई, 2025 से यह 8 घंटे पहले चार्ट बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई, जो ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों के लिए बड़ा तोहफा है। चार घंटे पहले चार्ट तैयार होने का सबसे बड़ा फायदा उन यात्रियों को होगा, जिनके टिकट वेटिंग में होते हैं। उन्हें पहले ही यह पता चल जाएगा कि उन्हें सीट मिली या नहीं, और जरूरत पड़ने पर वे दूसरा विकल्प चुन सकते हैं। रेलवे का यह कदम यात्रियों की सुविधा बढ़ाने की दिशा में एक सकारात्मक बदलाव माना जा रहा है।

यात्रा की अनिश्चितता को दूर करने के लिए रेलवे बोर्ड ने प्रस्थान से आठ घंटे पहले आरक्षण चार्ट तैयार करना शुरू कर दिया है। उदाहरण के लिए, 14:00 बजे से पहले प्रस्थान करने वाली ट्रेनों के लिए, चार्ट एक दिन पहले ही 21:00 बजे तैयार किया जाएगा। रेल मंत्री ने इस प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त कर इसे अलग-अलग चरणों में लागू करने का निर्देश दिया था ताकि यात्रा में कोई व्यवधान न हो।

यह कदम प्रतीक्षा सूची टिकट वाले यात्रियों के लिए अनिश्चितताओं को कम करेगा। यात्रियों को प्रतीक्षा सूची की स्थिति के बारे में पहले ही जानकारी मिल जाएगी। यह लंबी दूरी की ट्रेनों को पकड़ने के लिए प्रमुख शहरों के दूरदराज के स्थानों या उपनगरों से यात्र करने वाले यात्रियों को लाभान्वित करेगा। यह प्रतीक्षा सूची की पुष्टि नहीं होने की स्थिति में वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए अधिक समय भी प्रदान करेगा।

तत्काल बुकिंग के लिए मोबाइल ऐप

'तत्काल बुकिंग' के लिए व्यवस्थित प्रमाणीकरण- भारतीय रेल दिनांक 1 जुलाई, 2025 से केवल सत्यापित उपयोगकर्ताओं को ही आईआरसीटीसी वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर 'तत्काल टिकट बुक' करने की अनुमति देगा।

इसके अतिरिक्त, जुलाई 2025 के अंत से तत्काल बुकिंग के लिए ओटीपी-आधारित सत्यापन लागू किया जाएगा। रेल मंत्री ने अधिकारियों को तत्काल बुकिंग के लिए ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म को व्यापक बनाने का निर्देश दिया। यह प्रमाणीकरण आधार या उपयोगकर्ता के डिजिलॉकर खाते में उपलब्ध किसी अन्य सत्यापन योग्य सरकारी पहचान पत्र का उपयोग करके किया जाना चाहिए। ये पहल भारतीय रेल द्वारा अपनी प्रणालियों को आधुनिक बनाने तथा उन्हें अधिक नागरिक अनुकूल बनाने के निरंतर प्रयासों को दर्शाती हैं।

तत्काल बुकिंग के नये नियम

प्रभावी तिथि : 01.07.2025 से

आधार उपयोगकर्ताओं के लिए

1 जुलाई 2025 से, IRCTC वेबसाइट/ ऐप के माध्यम से तत्काल टिकट बुकिंग केवल आधार प्रमाणीकरण वाले उपयोगकर्ताओं के लिए ही मान्य है।

15.07.2025 से OTP आधारित आधार सत्यापन अनिवार्य है।

गैर-आधार उपयोगकर्ताओं के लिए

PRS काउंटर एवं अधिकृत एजेंट बुकिंग

15 जुलाई 2025 से, PRS काउंटरों/अधिकृत एजेंटों (YTSK) के माध्यम से तत्काल टिकट बुकिंग करने के लिए उस व्यक्ति के मोबाइल पर OTP सत्यापन अनिवार्य होगा, जिसके नाम पर टिकट बुक हो रहा है।

ट्रेवल एजेंटों के लिए

अधिकृत एजेंट तत्काल टिकट बुकिंग आरंभ होने के समय से 30 मिनट तक टिकट बुक नहीं कर सकेंगे :

- एसी श्रेणियाँ : प्रातः 10:00 बजे से 10:30 बजे तक
- नॉन-एसी श्रेणियाँ: प्रातः 11:00 बजे से 11:30 बजे तक

रेल राज्य मंत्री ने खानापुर जंक्शन पर माल गोदाम की रखी आधारशिला



रेल राज्य मंत्री वी. सोमण्णा ने दिनांक 31 मई, 2025 को बिदर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्यों की विस्तृत निरीक्षण यात्रा की। उन्होंने सिकंदराबाद मंडल के नागलपल्ली-बिदर खंड का रियर विंडो से भी गहन निरीक्षण किया।

इसी दिन, रेल राज्य मंत्री ने खानापुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर माल गोदाम के निर्माण तथा एक रोड अंडर ब्रिज की आधारशिला भी रखी। इस अवसर पर कर्नाटक सरकार के नगर प्रशासन मंत्री रहीम खान, सांसद, विधायकगण एवं दक्षिण मध्य रेलवे के महाप्रबंधक अरुण कुमार जैन भी उपस्थित रहे।

थिम्मराजनहल्ली रेलवे यार्ड का रेल राज्यमंत्री ने किया निरीक्षण

रेल राज्य मंत्री वी. सोमणा ने दिनांक 19 मई, 2025 को तुमकुर-चित्रदुर्ग-दावणगेरे नई रेलवे लाइन परियोजना के अंतर्गत निर्माणाधीन थिम्मराजनहल्ली रेलवे यार्ड के कार्यों का निरीक्षण किया।

मंत्री ने तुमकुर-दावणगेरे रेलवे लाइन की प्रगति की समीक्षा की। 191 कि.मी. लंबी यह नई रेल परियोजना चित्रदुर्ग, सीरा, हिरियूर, लक्ष्मीसागर और तोलहुनसे जैसे महत्त्वपूर्ण स्थानों को जोड़ती है। इस अवसर पर तुमकुर शहर से विधायक ज्योति गणेश भी उपस्थित थे।



रेल राज्यमंत्री ने इंटीग्रल कोच फैक्ट्री का किया दौरा



रेल राज्य मंत्री वी. सोमण्णा ने दिनांक 26 जून, 2025 को इंटीग्रल कोच फैक्ट्री (आईसीएफ) का दौरा किया। उन्होंने वंदे भारत, अमृत भारत, कोलकाता मेट्रो कोच तथा हाइड्रोजन ट्रेन सेट के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया।

आईसीएफ के महाप्रबंधक यू. सुब्बा राव ने इन सभी कोचों की विशेषताओं पर उनके साथ चर्चा की। मंत्री ने आईसीएफ में चल रही विभिन्न परियोजनाओं को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इसके साथ ही उन्होंने विभिन्न ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात कर संक्षिप्त चर्चा की।

क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्श समिति की बैठक सम्पन्न

दिनांक 25 जून, 2025 को क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्श समिति सत्र 2024-26 की प्रथम बैठक का आयोजन महाप्रबंधक उत्तर मध्य रेलवे उपेंद्र चन्द्र जोशी की अध्यक्षता में प्रयागराज में आयोजित की गई। इस बैठक में सांसद हाथरस अनूप प्रधान, सांसद राज्य सभा, सीमा द्विवेदी, सांसद फूलपुर प्रवीण पटेल एवं विधायक सिरमौर दिव्यराज सिंह एवं विधायक राठ मनीषा अनुरागी एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। महाप्रबंधक ने उत्तर मध्य रेलवे की उपलब्धियों के बारे में विस्तार से बताया।



अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने पूर्वोत्तर रेलवे के विभिन्न स्टेशनों का किया निरीक्षण



रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीश कुमार ने दिनांक 19 जून, 2025 को गोरखपुर-छपरा रेल खंड का विंडो ट्रेलिंग निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ पूर्वोत्तर रेलवे की महाप्रबंधक सौम्या माथुर एवं वाराणसी मंडल के मंडल रेल प्रबंधक विनीत कुमार श्रीवास्तव भी उपस्थित थे। निरीक्षण के क्रम में सतीश कुमार ने देवरिया सदर, भटनी, मैरवा तथा सीवान रेलवे स्टेशनों का दौरा कर अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत चल रहे विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की एवं आवश्यक सुधारात्मक निर्देश दिए।

इसके पश्चात् उन्होंने छपरा जंक्शन का भी गहन निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने छपरा जं. स्थित क्रू लॉबी का निरीक्षण किया तथा स्टेशन पर उपलब्ध यात्री सुविधाओं एवं सर्कुलेटिंग एरिया में और अधिक सुधार करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए।

सदस्य, रेलवे बोर्ड का आरडीएसओ दौरा

हितेन्द्र मल्होत्रा, सदस्य (परिचालन एवं व्यवसाय विकास), रेलवे बोर्ड ने दिनांक 2 जून, 2025 को आरडीएसओ का दौरा किया। उदय बोरवणकर, महानिदेशक/आरडीएसओ एवं रेलवे बोर्ड, सीआरआईएस आदि के अन्य अधिकारियों का इस समीक्षा बैठक में स्वागत किया।

मल्होत्रा एवं महानिदेशक/आरडीएसओ, उदय बोरवणकर ने आरडीएसओ अधिकारियों एवं अनुमोदित आपूर्तिकर्ताओं के साथ इलेक्ट्रॉनिक इन-मोशन वेइब्रिज (ईआईएमडब्ल्यूबी) के प्रदर्शन की समीक्षा की।



विश्व पर्यावरण दिवस पर भारतीय रेल ने चलाया जागरूकता अभियान

- **740 से अधिक कार्यशालाएँ आयोजित की गईं, 1200 स्टेशनों पर स्वच्छता कार्यक्रम हुए**
- **पूरे अभियान में लगभग 150 टन प्लास्टिक कचरे का सुरक्षित निपटान किया गया**

भारतीय रेल द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में जागरूकता दिनांक 22 मई से 5 जून तक पंद्रह दिवसीय विशेष अभियान चलाया। इस वर्ष की थीम "प्लास्टिक प्रदूषण समाप्त करें" के अंतर्गत भारतीय रेल के सभी क्षेत्रीय रेलवे, मंडल, स्टेशन और कार्यालयों में जन-जागरूकता की विभिन्न गतिविधियाँ आयोजित की गईं। इस अभियान में रेलवे कर्मचारियों, यात्रियों, आम नागरिकों और अन्य साझेदारों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रमों की प्लास्टिक कचरे का आकलन, कचरे को अलग-अलग छाँटना, प्लास्टिक बोतल क्रशिंग मशीनों की स्थिति की समीक्षा, स्वच्छता एवं जल संरक्षण के प्रयास, तथा प्लास्टिक उपयोग में कमी हेतु जागरूकता प्रसार शामिल थे।

5 जून को पर्यावरण संरक्षण को लेकर संकल्प दिलाया गया, जिसमें प्लास्टिक उपयोग में बदलाव, स्वच्छता और ऊर्जा बचत जैसे विषयों पर जोर दिया गया। रेलवे बोर्ड में यह संकल्प सदस्य (ट्रैक्शन एवं रोलिंग स्टॉक) द्वारा दिलाया गया, जिसमें अन्य बोर्ड सदस्य और क्षेत्रीय रेलवे के महाप्रबंधक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। इस अवसर पर रेलवे की वार्षिक पर्यावरण सततता रिपोर्ट भी जारी की गई। पूरे अभियान में लगभग 150 टन प्लास्टिक कचरे का सुरक्षित निपटान किया गया। 1230 से अधिक स्टेशनों पर पोस्टर व डिजिटल माध्यमों से जागरूकता फैलाई गई, 740 से अधिक कार्यशालाएँ आयोजित की गईं, 1200 स्टेशनों पर स्वच्छता अभियान चलाया गया, 180 से अधिक प्लास्टिक बोतल क्रशिंग मशीनों की कार्यप्रणाली की समीक्षा की गई और 230 नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से स्थानीय स्तर पर जन-जागरूकता को बल मिला।



भारतीय रेल पर्यावरणीय स्थायित्व को लेकर निरंतर प्रतिबद्ध है। वर्ष 2025-26 के लिए 750 करोड़ रुपये की एक समग्र योजना को स्वीकृति दी गई है, जो पर्यावरण से जुड़ी गतिविधियों को समर्पित है। अब तक 98% ब्रॉड गेज मार्गों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। 3512 स्टेशनों एवं सेवा भवनों पर सौर रूफटॉप की स्थापना के माध्यम से लगभग 227 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता सृजित की गई है। सभी रेलवे स्टेशनों, कार्यालयों और आवासीय परिसरों में 100% एलईडी लाइट्स की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त, हाइड्रोजन ईंधन आधारित ट्रेनों के विकास, 2014 से अब तक 9.7 करोड़ पौधारोपण और यात्री कोचों में 100% बायो-टॉयलेट्स की स्थापना जैसे कदमों के जरिए रेलवे ने पर्यावरण की दिशा में ठोस पहल की है।

भारतीय रेल अपनी पर्यावरणीय जिम्मेदारी को समाहित करते हुए, भविष्य में भी एक हरित और स्वच्छ परिवहन प्रणाली के निर्माण हेतु कृतसंकल्पित है।



आपको यह अंक कैसा लगा हमें जरूर बताएं

ई-मेल : editorbhartiyarailrb@gmail.com

पत्र लिखें ▶ **संपादक,** भारतीय रेल, कमरा नं. 411, रेल भवन, नई दिल्ली-110 001


भारतीय रेल
भारत को स्थायी रूप से हरित
भविष्य ट्रेक पर आगे बढ़ा रही है
रेल परिवहन सड़क की तुलना में 6 से 9 गुना ऊर्जा कुशल है
2014-24 के दौरान उसके पहले के दशक की तुलना में 36% ज्यादा कार्गो की वृद्धि हुई
भारतीय रेल यात्री परिवहन से प्रतिवर्ष लगभग 8.4 मीट्रिक टन CO2 की बचत कराता है
कुल CO2 की बचत लगभग 15 करोड़ कार/प्रतिवर्ष से होने वाले उत्सर्जन के बराबर है
सड़क परिवहन से CO2 उत्सर्जन में बचत


भारतीय रेल
रेल आधारित माल ढुलाई स्वच्छ परिवहन का समाधान
हरित भविष्य के लिए माल ढुलाई
502.11 मीट्रिक टन
682.04 मीट्रिक टन
वित्त वर्ष 2004-14
वित्त वर्ष 2014-24
36%


भारतीय रेल की हरित पहल
स्वच्छ भविष्य की ओर बढ़ते कदम
2004-14
शून्य
2014-24
755
प्लास्टिक बोतल क्रशर के उपयोग से
स्टेशन बने ईको-फ्रेंडली


भारतीय रेल हरित दिशा की ओर अग्रसर
स्वच्छ भारत के भविष्य की ओर एक पहल
सौर ऊर्जा से रोशन हो रही भारतीय रेल की यात्रा
3.68 MW
वित्त वर्ष 2004-14
175x
646 MW
वित्त वर्ष 2014-25
सड़क परिवहन से CO2 उत्सर्जन में बचत


भारतीय रेल हरित दिशा की ओर अग्रसर
स्वच्छ भारत के भविष्य की ओर एक पहल
पवन ऊर्जा से पूरी हो रही ऊर्जा की जरूरतें
10.50 MW
वित्त वर्ष 2004-14
9x
92.90 MW
वित्त वर्ष 2014-25
सड़क परिवहन से CO2 उत्सर्जन में बचत


भारतीय रेल की हरित पहल
भविष्य की स्वच्छता के लिए बढ़ता बारत
21
2004-14
138
2014-24
जल शुद्धिकरण प्लांट
OIL & GREASE TRAP
AERATION TANK
AERATION TANK
संसाधन की स्थिरता के लिए भारतीय रेल के जल शुद्धिकरण प्लांट्स

मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना

डीएफसीसी ट्रैक पर 100 मीटर लंबे स्टील ब्रिज का निर्माण

मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना की निरंतर प्रगति के अंतर्गत, गुजरात में भरूच के पास डीएफसीसी ट्रैक पर 100 मीटर लंबे स्टील ब्रिज का निर्माण पूरा किया गया। परियोजना के लिए यह गुजरात में बनने वाले 17 स्टील ब्रिज तथा संपूर्ण कॉरिडोर के लिए 28 स्टील ब्रिज में से आठवां स्टील ब्रिज है।

लगभग 1,400 मीट्रिक टन वजनी यह स्टील ब्रिज 14.6 मीटर ऊँचा और 14.3 मीटर चौड़ा है। इसे त्रिची की एक कार्यशाला में तैयार किया गया है और विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए ट्रेलरों का उपयोग करके साइट पर ले जाया गया। ब्रिज को 84 मीटर लंबे लॉन्चिंग नोज का उपयोग करके लॉन्च किया गया, जिसका वजन लगभग 600 मीट्रिक टन है।

निर्माण में लगभग 55,300 टोर-शियर टाइप हाई स्ट्रेंथ (टीटीएचएस) बोल्ट का उपयोग किया गया है, जिसमें सी5 सिस्टम पेंटिंग और इलास्टोमेरिक बियरिंग शामिल हैं और जिन्हें 100 साल के जीवनकाल के लिए डिज़ाइन किया गया है। ब्रिज को अस्थायी ट्रेस्टल्स पर जमीन से 18 मीटर की ऊँचाई पर साइट पर जोड़ा गया और मैक-अलॉय बार का उपयोग करके 2 अर्ध-स्वचालित जैक की स्वचालित प्रणाली के साथ खींचा गया, जिनमें से प्रत्येक की क्षमता 250 टन है।

डीएफसीसी ट्रैक पर इंटरमिटेंट ब्लॉक के साथ लॉन्चिंग पूरी की गई। ब्रिज लॉन्चिंग की सुरक्षा और सटीकता सुनिश्चित करने के लिए ट्रैफिक ब्लॉक्स आवश्यक है जिसे माल ढुलाई सेवाओं में व्यवधान को कम करने के लिए चरणबद्ध तरीके से किया जाता है।

गुजरात में पूर्ण किए गए स्टील पुलों का विवरण

स्थान	स्टील पुल की लंबाई (मीटर में)	स्टील पुल का भार (मीट्रिक टन में)
राष्ट्रीय राजमार्ग 53 पर, सूरत	70	673
भारतीय रेल की वडोदरा-अहमदाबाद मुख्य लाइन पर, नडियाद के पास	100	1486
दिल्ली-मुंबई नेशनल एक्सप्रेसवे पर, वडोदरा के पास	230 (130 + 100)	4397
दादरा और नगर हवेली में, सिलवासा के पास	100	1464
पश्चिम रेलवे, वडोदरा	60	645
दो डीएफसीसी ट्रैकों और दो पश्चिम रेलवे ट्रैकों पर, सूरत	100, 60	2040
दो डीएफसीसी ट्रैकों पर, वडोदरा के पास	70	674
डीएफसीसी ट्रैकों पर, भरूच के पास	100	140



जीआरपी प्रमुखों का छठा अखिल भारतीय सम्मेलन सम्पन्न

भारतीय रेल में अपराध नियंत्रण हेतु बनाई एकीकृत राष्ट्रीय रणनीति

रेलवे सुरक्षा बल के तत्वावधान में आयोजित सरकारी रेलवे पुलिस प्रमुखों का छठा अखिल भारतीय सम्मेलन दिनांक 22 जून, 2025 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। आरपीएफ के महानिदेशक मनोज यादव की अध्यक्षता में आयोजित उच्च स्तरीय सम्मेलन में रेल मंत्रालय के प्रतिनिधियों के साथ-साथ विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के डीजीपी, एडीजीपी और जीआरपी के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

इस सम्मेलन द्वारा भारतीय रेल पर अपराध नियंत्रण की बढ़ती चुनौतियों से निपटने और लाखों रेल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सामूहिक तंत्र को मजबूत करने के लिए एक ठोस प्रयास की पहल की गई। सम्मेलन का मुख्य विषय खुफिया जानकारी साझा करने को बढ़ाना, संयुक्त परिचालन रणनीति तैयार करना और आपराधिक तत्वों की बदलती कार्यप्रणाली का मुकाबला करने के लिए अंतर-एजेंसी समन्वय को बेहतर बनाना था।

सम्मेलन में यात्रियों को चोरों और धोखेबाजों के आम हथकंडों और जाल के बारे में शिक्षित करने के लिए यात्री जागरूकता अभियान को तेज करने पर चर्चा हुई। सम्मेलन में रेल मदद पोर्टल पर दर्ज यात्री संपत्ति चोरी की शिकायतों को औपचारिक एफआईआर में बदलने के लिए जोर दिया गया, जिससे अपराधियों का पता लगाने की दर में वृद्धि होगी और बार-बार अपराध करने से रोका जा सकेगा।

यात्रियों के कीमती सामान चुराने वाले संगठित अंतरराज्यीय आपराधिक नेटवर्क को खत्म करने के लिए, सक्रिय निगरानी, राज्यों में समन्वित संचालन और चेहरे की पहचान प्रणाली सहित प्रौद्योगिकी के उत्तम तरीकों का लाभ उठाने पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की जीआरपी इकाइयों के बीच एकीकृत प्रतिक्रिया प्रणाली की आवश्यकता पर जोर दिया गया ताकि क्षेत्राधिकार संबंधी अंतराल को रोका जा सके, जिसका फायदा अक्सर अपराधी उठाते हैं।

सम्मेलन में महिला यात्रियों पर बढ़ते अपराधों पर विशेष ध्यान दिया गया तथा प्रतिभागियों ने विशेष गश्त, स्टेशनों और कोचों में सीसीटीवी कैमरे तथा महिला यात्रियों में सुरक्षा की भावना बढ़ाने के लिए मेरी सहेली टीमों की तैनाती सहित कई उपायों पर सहमति व्यक्त की।

ड्रग तस्करों और तस्करों द्वारा रेलवे परिसरों के दुरुपयोग पर भी चर्चा की गई, जिसमें गहन जाँच और तत्काल खुफिया सूचनाओं के माध्यम से ऐसी अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए



रणनीतियों पर चर्चा की गई। खुफिया ब्यूरो द्वारा एक महत्त्वपूर्ण प्रस्तुति में संवेदनशील रेलवे प्रतिष्ठानों के लिए संभावित आतंकवादी खतरों और भेद्यता आकलन और मजबूत सुरक्षा प्रोटोकॉल की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया। इसके अतिरिक्त, रेलवे परिसरों में बाल सुरक्षा के मुद्दे पर भी विचार-विमर्श किया गया, जिसमें तस्करी और शोषण से बचाए जा रहे कमजोर बच्चों की समय पर पहचान और पुनर्वास के लिए तंत्र पर ध्यान केंद्रित किया गया।

सम्मेलन के समापन पर, आरपीएफ महानिदेशक मनोज यादव ने कहा, ''विशाल भारतीय रेल पर अपराध नियंत्रण किसी एक एजेंसी की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह एक सामूहिक मिशन है, जिसके लिए तालमेल, समन्वय और साझा खुफिया जानकारी की आवश्यकता है। आज पूरे देश में जीआरपी और आरपीएफ नेतृत्व द्वारा दिखाया गया संकल्प रेलवे यात्रा को अधिक सुरक्षित और आपराधिक तत्वों के खतरे से मुक्त बनाने के लिए हमारी प्रतिबद्धता को आश्वस्त करता है। हम हर यात्री, हर बच्चे और हमारे रेलवे नेटवर्क के हर कोने को नुकसान से बचाने के अपने प्रयास में एकजुट हैं।''

सम्मेलन में भारतीय रेल को अपराध के प्रति शून्य सहनशीलता वाले क्षेत्र में बदलने तथा राष्ट्र की जीवन रेखा के रूप में इसकी स्थिति की रक्षा करने के लिए आरपीएफ और जीआरपी बलों की संयुक्त प्रतिबद्धता की पुष्टि की गई।

भारतीय रेल ने मनाया अंतराष्ट्रीय योग

चिनाब, अंजी और पांबन ब्रिज पर अनोखा योग सत्र आयोजित

सभी क्षेत्रीय रेलवे, मंडल और परिसर में योग कार्यक्रम आयोजित











अंजी खड्ड ब्रिज

दिवस 2025

पश्चिम बंगाल में योग को समर्पित विशेष ईएमयू ट्रेन चलाई गई, जिसमें विभिन्न योग मुद्राओं का प्रदर्शन किया गया





पांबन ब्रिज




चिनाब ब्रिज


योग को समर्पित विशेष ईएमयू ट्रेन

11 वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भारतीय रेल ने पूरे देश में भव्य और उत्साहपूर्ण योग सत्र आयोजित किए। 'एक पृथ्वी, एक स्वास्थ्य के लिए योग' विषय के साथ पूरे भारत में सभी क्षेत्रीय रेलवे, मंडल, स्टेशनों और रेलवे परिसरों में योग कार्यक्रम आयोजित किए गए।

केन्द्रीय रेल राज्य मंत्री वी. सोमन्ना और रवनीत सिंह ने क्रमशः कर्नाटक के हसन और चंडीगढ़ की सुखना झील में आयोजित योग सत्रों में भाग लिया। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीश कुमार ने भी नई दिल्ली के करनैल सिंह स्टेडियम में आयोजित योग सत्र में भाग लिया।

इस वर्ष योग दिवस को असाधारण बनाने वाली बात यह रही कि न केवल स्टेशनों और कार्यालय परिसरों में बल्कि भारतीय रेल के प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग चमत्कारों पर भी योग सत्र आयोजित किए गए। पहली बार, जम्मू-कश्मीर में स्थित दुनिया के सबसे ऊँचे रेलवे ब्रिज-चिनाब पर योग सत्र आयोजित किया गया, जो भारतीय रेल के आत्मविश्वास और इंजीनियरिंग क्षमताओं का प्रतीक है। भारत के केबल पर टिके पहले रेल ब्रिज-अंजी खड्ड ब्रिज और देश के पहले वर्टिकल-लिफ्ट रेल ब्रिज-तमिलनाडु स्थित पांबन ब्रिज पर योग सत्र आयोजित किए गए, जिसमें योग और इंजीनियरिंग उत्कृष्टता का एक अनूठा मिश्रण दिखाया गया।

पश्चिम बंगाल में हावड़ा मंडल द्वारा योग को समर्पित एक विशेष ईएमयू ट्रेन चलाई गई, जिसमें विभिन्न योग मुद्राओं के साथ-साथ उनके स्वास्थ्य लाभों के चित्रण भी दिखाए गए।

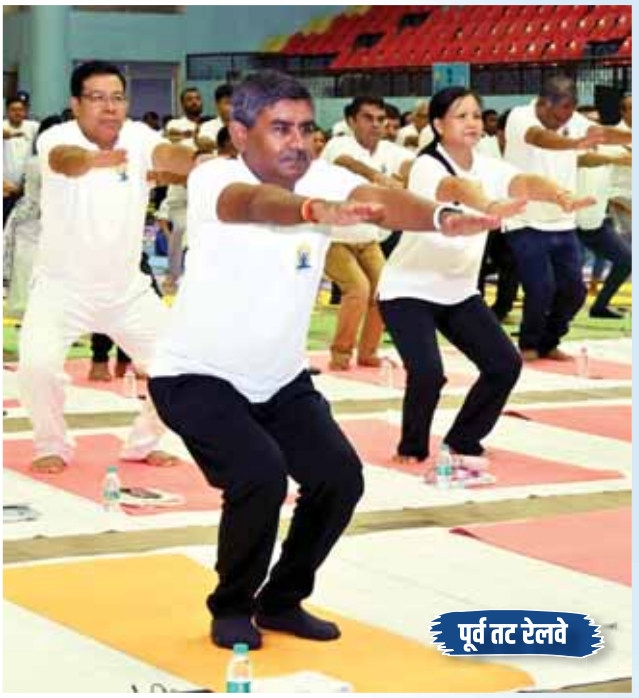
विभिन्न क्षेत्रों में, रेलवे अधिकारियों, कर्मचारियों, रेलवे सुरक्षा बल के कर्मियों, स्काउट्स और गाइड्स, स्कूली छात्रों, जन प्रतिनिधियों और आम जनता की ओर से उत्साहपूर्ण भागीदारी देखी गई। सत्रों में आसन (शारीरिक मुद्राएँ), प्राणायाम (श्वास तकनीक), ध्यान और योग के समग्र लाभों पर केन्द्रित जागरूकता गतिविधियाँ शामिल थीं।

इस राष्ट्रव्यापी पहल के माध्यम से, भारतीय रेल ने न केवल अपने कर्मचारियों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया, बल्कि आम जनता के बीच योग के परिवर्तनकारी लाभों के बारे में जागरूकता फैलाने में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।


मध्य रेल


पूर्व रेलवे


पूर्व मध्य रेल

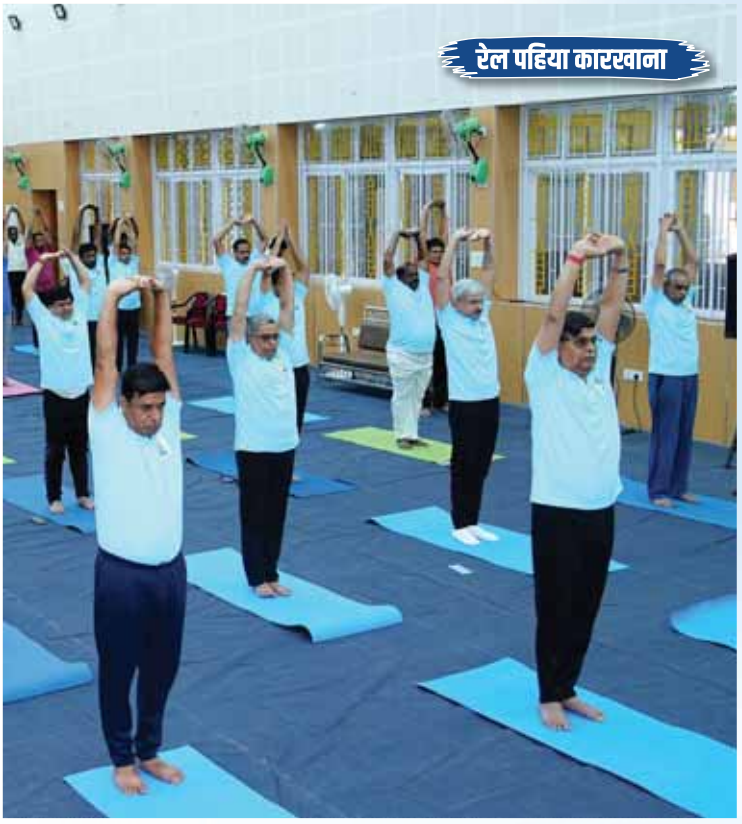

पूर्व तट रेलवे


मेट्रो रेलवे


उत्तर मध्य रेलवे


पूर्वोत्तर रेलवे


दक्षिण मध्य रेल


रेल पहिया कारखाना


रेल डिब्बा कारखाना


बनारस रेल इंजन कारखाना


इरिसेट

बरेका का स्वच्छता और नवाचार की दिशा में एक और कदम

वॉटरलेस शौचालय युक्त डब्ल्यूएजी-9 फ्रेट लोको का किया निर्माण

भारतीय रेल के 'स्वच्छ और सुरक्षित शौचालय' मिशन के अंतर्गत बनारस लोकोमोटिव वर्क्स (बरेका) ने महाप्रबंधक नरेश पाल सिंह के कुशल नेतृत्व में एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। रेलवे बोर्ड द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुरूप, बरेका ने 37 डब्ल्यूएजी9 मालवाहक लोको एवं 2 डब्ल्यूएपी7 यात्री वाहक लोको में वॉटरलेस यूरिनल की सुविधा के साथ CO_2 सिलेंडर और हैंडब्रेक की नई व्यवस्था को सफलतापूर्वक लगाया गया है।



प्रमुख विशेषताएँ

वॉटरलेस यूरिनल को फिट करने हेतु विशेष मॉडलिंग और इंजीनियरिंग समाधानों को अपनाया गया, जिससे लोको की संरचना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। केबिन के अंदर यूरिनल के लिए 180 मिमी गहराई की नई जगह चिन्हित की गई, जिससे चालक दल को सुविधा मिले और लोको की बनावट बरकरार रहे। लोको में स्थापित यह वॉटरलेस सिस्टम पर्यावरण के अनुकूल होने के साथ-साथ जल संरक्षण में भी सहायक सिद्ध होगा। डब्ल्यूएजी-9 लोको नंबर 43929 (निर्माण शेल संख्या 136) इस नवाचार का पहला उदाहरण बना है, जिसमें सभी नई सुविधाएँ- वॉटरलेस यूरिनल और मशीन रूम से दरवाजा खोले बिना केब से CO_2 सिलेंडर तक पहुँच की व्यवस्था की गई। बरेका द्वारा किया गया यह अभिनव प्रयास न केवल रेलवे कर्मचारियों को स्वच्छता सुविधा प्रदान करेगा, बल्कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी एक मजबूत संदेश देगा। यह उपलब्धि 'स्वच्छ भारत मिशन' और 'ग्रीन रेल' की दिशा में एक सार्थक पहल है।



करही-सगमा के बीच नई कॉर्ड रेल लाइन को मिली स्वीकृति



मध्य प्रदेश में रेल बुनियादी ढाँचे को मजबूती प्रदान करने की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम उठाते हुए, रेलवे बोर्ड ने पश्चिम मध्य रेल क्षेत्र के तहत एक महत्त्वपूर्ण नई रेल लाइन परियोजना को स्वीकृति प्रदान की है। प्रस्तावित कॉर्ड रेल लाइन करही और सगमा के बीच 5.31 कि.मी. की है। इस नई रेल लाइन परियोजना को ₹165.20 करोड़ लागत की स्वीकृति प्रदान की गई है। प्रदेश में कनेक्टिविटी बढ़ाने के उद्देश्य से रेलवे परियोजनाओं की स्वीकृति और विकास में महत्त्वपूर्ण कदम है।

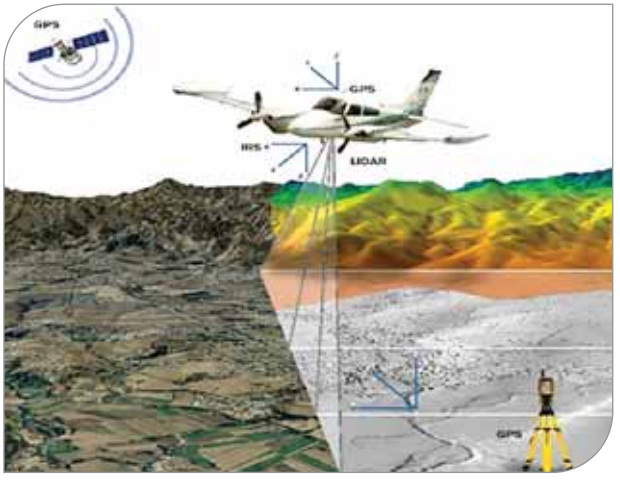
अम्ब्रेला वर्क के तहत प्रस्तावित करही से सगमा (5.31 कि.मी.) के बीच कॉर्ड रेल लाइन रेल कनेक्टिविटी के लिए महत्त्वपूर्ण है क्योंकि इसका उद्देश्य लाइनों की क्षमता में वृद्धि, फ्लाई ओवर एवं बाईपास लाइनों के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाना है। करही स्टेशन सतना-पन्ना-खजुराहो निर्माणाधीन नई लाइन पर एक नया स्टेशन है और सगमा स्टेशन सतना-मानिकपुर-प्रयागराज डबल लाइन रूट पर स्थित है। वर्तमान में सतना-मानिकपुर खंड की लाइन क्षमता की उपयोगिता 120% है, जो आगामी वर्ष 2027 तक इसकी उपयोगिता 143% तक बढ़ने का अनुमान है। ललितपुर-सिंगरौली नई रेल परियोजना के अंतर्गत रीवा-सिंगरौली के बीच नई लाइन का कार्य भी प्रगति पर है। करही और सगमा के बीच प्रस्तावित द्वि-दिशात्मक कॉर्ड लाइन ललितपुर-सिंगरौली नई लाइन को इटारसी-मानिकपुर मौजूदा लाइन से जोड़ेगी। इससे मानिकपुर-पन्ना इसके विपरीत जाने वाली ट्रेनों को सतना जंक्शन स्टेशन पर जाए बिना सीधे चलने में सुविधा होगी और इस तरह सतना में इंजन को बदलना नहीं पड़ेगा, जिससे समय की बचत होगी।

यह रेल संपर्क क्षेत्रीय व्यापार, गतिशीलता और संसाधनों तक पहुँच को बढ़ावा देगा। करही से सगमा कॉर्ड रेल लाइन बनने से मध्य प्रदेश के महत्त्वपूर्ण राज्यों सतना, पन्ना एवं खजुराहो के पर्यटक संपर्क को मजबूती मिलेगी। सतना एवं पन्ना औद्योगिक शहर है, जिनमें प्रचुर मात्रा में सीमेंट और खनिज उद्योग हैं, जो मध्य प्रदेश के कई हिस्सों को जोड़ता है। इस लाइन से क्षेत्र में माल ढुलाई, औद्योगिक विकास, पर्यटन और बेहतर यात्री संपर्क में मदद मिलने की उम्मीद है।

लामडिंग-बदरपुर हिल सेक्शन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए

पू. सी. रेलवे द्वारा अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग

रेलवे सुरक्षा और बुनियादी संरचना को अधिक सुदृढ़ करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे (पू. सी. रेलवे) ने अपने लामडिंग मंडल के अधीन असम में लामडिंग-बदरपुर हिल सेक्शन पर भूस्खलन, जल निकासी संबंधी मुद्दों और तटबंध स्थिरता से संबंधित चुनौतियों का समाधान करने के लिए अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग किया है। दीमा हसाओ और कछार जिलों के पहाड़ी इलाकों में फैला यह सेक्शन त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और असम की बराक घाटी को भारत के अन्य हिस्सों से जोड़ने वाला एक महत्त्वपूर्ण मार्ग है। कठिन स्थलाकृति और अत्यधिक मॉनसून की स्थिति के कारण यह मार्ग प्राकृतिक आपदाओं के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील हो जाता है, जिससे अक्सर रेल यातायात बाधित होता है और महत्त्वपूर्ण संरक्षा जोखिम पैदा होते हैं।



इन चुनौतियों को कम करने के लिए, पू. सी. रेलवे ने कि.मी.-45 से कि.मी.-125 तक पहाड़ी सेक्शन के 80 कि.मी. हिस्से पर एक व्यापक हवाई और भूभौतिकीय सर्वेक्षण शुरू किया है। यह पहल उन्नत ड्रोन-आधारित लाइडर (लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग), हाई-रिजॉल्यूशन एरियल इमेजिंग और विद्युत चुम्बकीय सर्वेक्षण का उपयोग करती है।

महाप्रबंधक, दक्षिण मध्य रेलवे राजभाषा स्वर्ण पदक से सम्मानित



अरुण कुमार जैन, महाप्रबंधक, दक्षिण मध्य रेलवे को 'कमलापति त्रिपाठी राजभाषा स्वर्ण पदक' से रेलवे बोर्ड स्तर पर सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उन्हें रेलवे में राजभाषा के प्रचार-प्रसार और उपयोग बढ़ाने में उनके उत्कृष्ट एवं अनुकरणीय योगदान के लिए प्रदान किया गया। 'सी' क्षेत्र में स्थित इस रेलवे के महाप्रबंधक को संपूर्ण रेलवे स्तर पर स्वर्ण पदक प्राप्त होना गर्व की बात है।

हाई हॉर्स पावर डीजल रेल इंजन के लिए अत्याधुनिक डायनेमिक हाइड्रोलिक टेस्टिंग अरेंजमेंट विकसित

महाप्रबंधक नरेश पाल सिंह के दिशा निर्देशन में बनारस रेल इंजन कारखाना द्वारा हाई हार्स पावर रेल इंजन में वॉटर पंप असेम्बली के लिए एक अत्याधुनिक डायनेमिक हाइड्रोलिक टेस्टिंग अरेंजमेंट विकसित किया गया है, जिससे पंप की गुणवत्ता परीक्षण की प्रक्रिया और भी प्रभावशाली, सुरक्षित तथा भरोसेमंद बन गई है।

इस प्रणाली के अंतर्गत वॉटर पंप असेम्बली को मोटर, वी-बेल्ट और पुली की सहायता से संचालित किया जाता है। यह एक कॉम्पैक्ट सिस्टम है, जिसमें न तो किसी प्रकार की तेज आवाज उत्पन्न होती है और न ही लुब्रिकेशन की आवश्यकता होती है।

टेस्टिंग के दौरान वॉटर इनलेट पाइप से पानी खींचा जाता है और आउटलेट पाइप से 30 से 55 पी एस आई (PSI) के दबाव पर डिस्चार्ज किया जाता है। संपूर्ण प्रक्रिया को सुरक्षित बनाने हेतु वी-बेल्ट और पुली ड्राइव पर सेफ्टी गार्ड लगाया गया है। साथ



ही, बेल्ट की टाइटनेस को नियंत्रित करने हेतु मोटर को आगे-पीछे समायोजित करने की सुविधा भी उपलब्ध है।



विजयवाड़ा मंडल के ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन (टीआरडी) विभाग को 22 प्रमुख स्थानों पर ISO 9001:2015 गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन प्राप्त हुआ है। यह ओएचई और विद्युत आपूर्ति प्रणालियों में सुरक्षा और संचालन उत्कृष्टता की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है।

पश्चिम रेलवे : 'छोटा भीम' के साथ सुरक्षा पर जागरुकता



उज्जैन रेलवे स्टेशन

जन जागरूकता और रेलवे सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठी पहल के तहत पश्चिम रेलवे छोटा भीम के साथ जुड़ गया है। पश्चिम रेलवे शैक्षणिक और आउटरीच गतिविधियों के लिए छोटा भीम की दुनिया के प्रिय पात्रों का उपयोग करेगी। पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी विनीत अभिषेक और छोटा भीम के निर्माता, ग्रीन गोल्ड एनिमेशन प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ और प्रबंध निदेशक राजीव चिलाकलापुडी ने दिनांक 2 मई, 2025 को जियो वर्ल्ड सेंटर, मुंबई में आयोजित विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन (WAVES) 2025 में लैटर ऑफ कोलेबरेशन पर हस्ताक्षर किए। पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी के अनुसार, पश्चिम रेलवे आम जनता के दिलों तक पहुँचने के लिए अपरंपरागत तरीका अपनाएगी। 'छोटा भीम' और उसके परिवार के चरित्रों का उपयोग प्रिंट, डिजिटल, टेलीविजन, रेडियो और पोस्टर तथा स्कूल कार्यक्रमों जैसे भौतिक प्रतिष्ठानों सहित विभिन्न मीडिया प्रारूपों में एक वर्ष की अवधि के लिए किया जाएगा।



दार्जिलिंग की पारंपरिक वाष्प इंजन-782बी ने अपनी सेवा के पूरे किए 125 वर्ष



भारत की समृद्ध रेलवे विरासत के सम्मान में, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे (डीएचआर) ने दिनांक 17 अप्रैल, 2025 को अपनी प्रतिष्ठित बी श्रेणी की वाष्प इंजन संख्या 782बी की लगातार सेवा के 125 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाया। एक स्पेशल धरोहर वाष्प ट्रेन को भारत के सबसे ऊँचे रेलवे स्टेशन–घुम रेलवे स्टेशन से रेलवे संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष डॉ. सी. एम. रमेश ने औपचारिक रूप से रवाना किया। उनके साथ पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के महाप्रबंधक चेतन कुमार श्रीवास्तव भी मौजूद थे। यह कार्यक्रम इतिहास, इंजीनयरी और संस्कृति का एक जीवंत उत्सव था। दार्जिलिंग हिल्स के पारंपरिक संगीत और लोक नृत्यों पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम ने समारोह में उत्सव का माहौल बना दिया।

स्मारक गतिविधियों के हिस्से के रूप में, संसदीय स्थायी समिति के सदस्यों ने घुम में रेलवे संग्रहालय का दौरा किया, जहाँ उन्हें दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे द्वारा किए जा रहे जीर्णोद्धार और संरक्षण प्रयासों से अवगत कराया गया। समिति ने इस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के संरक्षण में निहित समर्पण और शिल्प कौशल की सराहना की। शार्प, स्टीवर्ट एंड कंपनी द्वारा 1900 में निर्मित बी श्रेणी की इंजन संख्या 782बी, पूर्वी हिमालय की छोटी लाइन की पटरियों पर निरंतर चल रही है। 125 वर्षों की निरंतर सेवा के साथ, यह इंजन ब्रिटिश काल की रेलवे इंजीनयरी का एक जीवंत प्रतीक है और भारतीय रेल की स्थायी विरासत को दर्शाता है।

दक्षिण मध्य रेलवे के लालागुड़ा शेड एवं दक्षिण रेलवे के रोयापुरम् को मिला सर्वश्रेष्ठ कैब डिज़ाइन का पुरस्कार

बनारस रेल इंजन कारखाना (बरेका) में दिनांक 23 एवं 24 मई, 2025 को 42वीं एम.एस.जी. (मेंटिनेंस सर्विस ग्रुप) बैठक एवं लोको कैब प्रतियोगिता का आयोजन सम्पन्न हुआ।

बैठक के दौरान विद्युत लोकोमोटिव में उत्पन्न होने वाली तकनीकी समस्याओं, संभावित समाधानों तथा ड्राइवर सुविधा बढ़ाने हेतु किए जा रहे नवाचारों पर व्यापक चर्चा हुई। अपर सदस्य (कर्षण), रेलवे बोर्ड, वी.पी. सिंह ने बताया कि ड्राइवर की सुविधा हेतु अब नए लोको में A.C. एवं यूरिनल की व्यवस्था की जा रही है और पुराने लोको में भी इन सुविधाओं को शीघ्र जोड़ा जाएगा। साथ ही वंदे भारत जैसी आरामदायक सीटें, एलईडी हेडलाइट, इलेक्ट्रिक वाइपर जैसी सुविधाओं को नए लोको में लगाया जाएगा।

इस अवसर पर बरेका परिसर में लोको कैब इंटीरियर डिज़ाइन प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया, जिसमें देशभर के क्षेत्रीय रेलवे और उत्पादन इकाइयों के कुल 14 विद्युत लोकोमोटिव ने भाग लिया। ड्राइवर कैब की सुविधा, डिज़ाइन और कार्यकुशलता के आधार पर इनका मूल्यांकन किया गया।



बनारस रेल इंजन कारखाना (बरेका), दक्षिण मध्य रेलवे के लालागुड़ा शेड एवं दक्षिण रेलवे के रोयापुरम (आरपीएम) को संयुक्त रूप से प्रथम स्थान मिला। क्षेत्रीय रेलवे श्रेणी में-दक्षिण मध्य रेलवे के लालागुड़ा शेड को प्रथम स्थान मिला। संयुक्त रूप से द्वितीय पुरस्कार-कानपुर, अजनी एवं वाल्टेयर शेड को मिला। संयुक्त रूप से तृतीय पुरस्कार-डीडीयू, हुबली एवं वडोदरा शेड को प्रदान किया गया।

हम सभी का **भारतीय रेल** के साथ अटूट रिश्ता है

भारतीय रेल के साथ आप अपने संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, लेख आदि हिन्दी में हमें भेज सकते हैं। पसंद आने पर रचनाओं को हम रेल मंत्रालय की आधिकारिक मासिक पत्रिका

भारतीय रेल

में प्रकाशित करेंगे

ई-मेल editorbhartiyarailrb@gmail.com

चयनित सामग्री/लेख की जानकारी ई-मेल द्वारा दी जाएगी,
प्रकाशित रचनाओं के लिए रेल मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानदेय भी दिया जाएगा

आगरा मंडल में इतिहास और विरासत का उत्सव

आगरा सिटी एवं आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशनों का महोत्सव दिवस धूमधाम से मनाया गया



आगरा मंडल द्वारा अप्रैल 2025 में अपनी ऐतिहासिक धरोहरों को सम्मान देने के लिए दो महत्त्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों, आगरा सिटी और आगरा फोर्ट के स्थापना दिवस पर स्टेशन महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य न केवल इन स्टेशनों के ऐतिहासिक महत्त्व को उजागर करना था, बल्कि जनता को भारतीय रेल की समृद्ध विरासत से भी जोड़ना रहा।

122वें महोत्सव दिवस पर सजी आगरा सिटी की विरासत

दिनांक 17 अप्रैल, 2025 को आगरा सिटी रेलवे स्टेशन के 122वें स्टेशन महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य, विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल और मंडल रेल प्रबंधक तेज प्रकाश अग्रवाल ने शिरकत की। इस अवसर पर लगाई गई फोटो गैलरी एवं एलईडी प्रेजेंटेशन के माध्यम से स्टेशन के ऐतिहासिक पहलुओं को प्रदर्शित किया गया। स्टेशन की स्थापना वर्ष 1903 में हुई थी, जिसकी आधारशिला ब्रिटिश अधिकारी जॉन स्ट्रैची ने रखी थी।

यह स्टेशन व्यापारिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण बेलनगंज क्षेत्र की आपूर्ति आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु तैयार किया गया था। इसकी वास्तुकला में ब्रिटिश औपनिवेशिक युग की झलक मिलती है– कास्ट आयरन के खंभों वाला प्रवेश द्वार और चीनी मिट्टी की टाइलों से सजे उपमार्ग इसकी विशेषताएँ हैं। यह स्टेशन स्वतंत्रता संग्राम के कई सेनानियों से भी जुड़ा रहा है, जिनमें श्रीकृष्ण दत्त पालीवाल, बाबूलाल पाठक और किशनलाल स्वर्णकार जैसे नाम प्रमुख हैं।

151 वर्षों की गौरवगाथा

दिनांक 27 अप्रैल, 2025 को आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन के 151वें स्टेशन महोत्सव का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रो. एस.पी. सिंह बघेल (राज्य मंत्री, भारत सरकार), विशिष्ट अतिथि योगेन्द्र उपाध्याय (कैबिनेट मंत्री, उत्तर प्रदेश), सांसद डॉ. नवीन जैन एवं मंडल रेल प्रबंधक तेज प्रकाश अग्रवाल उपस्थित रहे। वर्ष 1874 में स्थापित यह स्टेशन ब्रिटिश राज के दौरान राजपूताना–मालवा रेलवे के अधीन बना था और राजस्थान एवं मध्य भारत को जोड़ने में इसकी प्रमुख भूमिका रही।

इस स्टेशन की वास्तुकला में लाल बलुआ पत्थर, धनुषाकार गलियारे और मुगलकालीन प्रभाव शामिल हैं, जो ताजमहल व आगरा किला जैसे स्मारकों से सामंजस्य रखते हैं। यह स्टेशन कभी ब्रिटिश प्रशासन के लिए रणनीतिक केंद्र रहा और आज भी देश के प्रमुख रेल मार्गों का हिस्सा है। आगरा में मीटर गेज की पहली रेलवे लाइन यहीं से शुरू हुई थी। वर्तमान में अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत इसका पुनर्निर्माण व सौंदर्यीकरण किया जा रहा है।



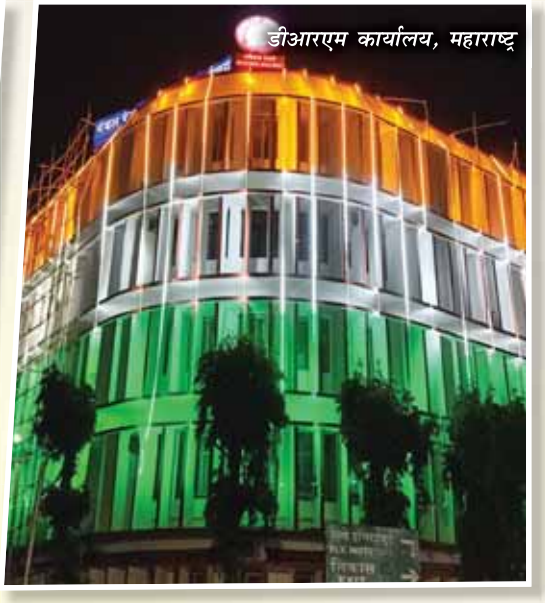
ऐतिहासिक पहलों को बढ़ावा

इन दोनों महोत्सवों ने यह स्पष्ट किया कि भारतीय रेल सिर्फ यातायात का माध्यम नहीं, बल्कि भारत की ऐतिहासिक चेतना को जीवंत बनाए रखने वाला स्तंभ भी है। आगरा सिटी और आगरा फोर्ट जैसे स्टेशन न केवल स्थापत्य और इंजीनियरिंग की मिसाल हैं, बल्कि ये देश की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विरासत को भी संजोए हुए हैं। इन आयोजनों के माध्यम से भारतीय रेल ने यह संदेश दिया कि बीते युग की गौरव गाथाओं को संजोकर भविष्य की दिशा तय करना ही सच्चे विकास का आधार है। ऐसे महोत्सव न केवल नागरिकों में गर्व का भाव भरते हैं, बल्कि ऐतिहासिक पहलों को संरक्षण और प्रोत्साहन देने की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम हैं।

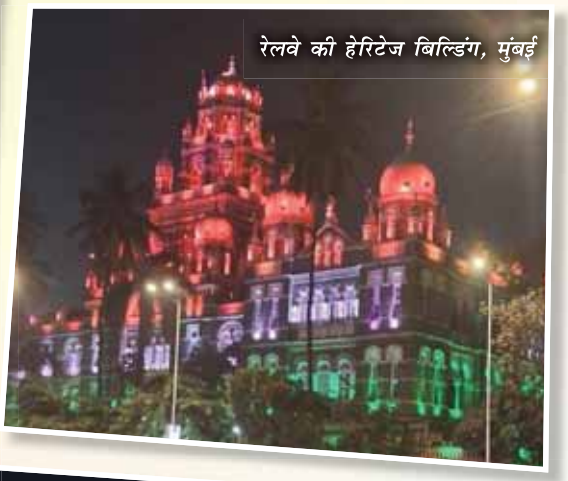
OPERATION SINDOOR

वीर सैनिकों के सम्मान में जगमगाए देशभर के रेलवे स्टेशन


न्यू पांबन ब्रिज


डीआरएम कार्यालय, महाराष्ट्र


अयोध्या धाम जंक्शन


रेलवे की हेरिटेज बिल्डिंग, मुंबई


काचीगुडा रेलवे स्टेशन, तेलंगाना


छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, मुंबई



कामाख्या रेलवे स्टेशन, असम



हरियाणा का सिरसा रेलवे स्टेशन


उत्तर प्रदेश का मथुरा छावनी रेलवे स्टेशन


पश्चिम बंगाल का अलीपुरद्वार डीआरएम कार्यालय


मध्य प्रदेश का रानी कमलापति स्टेशन


राजस्थान का सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन

ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना के अदम्य शौर्य और पराक्रम के सम्मान में देश भर के रेलवे स्टेशन जगमगा उठे। भारतीय रेल ने वीर सैनिकों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए यह अनूठा आयोजन किया। इस मौके पर कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से असम तक के रेलवे स्टेशनों पर राष्ट्रभक्ति का अलग जोश देखने को मिला। इस दौरान तिरंगे की रोशनी में नहाए रेलवे परिसर देशभक्ति के गीतों से गूंज उठे। वहीं स्टेशनों पर लगी स्क्रीनों पर राष्ट्रभक्ति से जुड़े विजुअल्स ने यात्रियों को राष्ट्र प्रेम की भावनाओं से भर दिया।

इस ऑपरेशन की सफलता को जन-जन तक पहुँचाने के लिए भारतीय रेल ने देश के विभिन्न हिस्सों में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया, जिसने देशवासियों के मन मस्तिष्क में राष्ट्रप्रेम और सेना के प्रति सम्मान की भावना को और मजबूत किया। इसके अलावा भारतीय रेल ने तिरंगा यात्रा के साथ तमाम स्थानों पर नुक्कड़ नाटक के जरिए भी ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को जनमानस तक पहुँचाया।

भारतीय रेल की इस पहल ने ना केवल सेना के रणबांकुरों का अभिनंदन किया, बल्कि आम जनता को भी ऑपरेशन सिंदूर की गौरव गाथा से जोड़ा। यह आयोजन दर्शाता है कि देश का प्रत्येक नागरिक अपने वीर सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद न्याय की अखंड प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए शुरू हुआ ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना की वह गौरव गाथा है, जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा।

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे : अनुपपुर-कटनी तीसरी रेल लाइन बनी यात्री सुविधाओं की नई दिशा



दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य में रेल नेटवर्क को और सशक्त बनाने के उद्देश्य से अनुपपुर-कटनी तीसरी रेल लाइन परियोजना (165.52 कि.मी.) का कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के सभी महत्त्वपूर्ण शहरों को रेलमार्ग द्वारा उत्तर भारत से जोड़ने वाली बिलासपुर-कटनी मार्ग पर तीसरी लाइन की कार्य क्षमता बढ़ाने की दृष्टि से किया गया था। दिनांक 31 मार्च, 2025 को कमीशन की गई इस परियोजना के अंतिम खंड, बीरसिंहपुर-नौरोजाबाद-करकेली-उमरिया (29.52 कि.मी.) की सीआरएस निरीक्षण प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न हुई। वर्तमान में अब इस सेक्शन मे पेंड्रारोड से कटनी तक तीसरी लाइन है।

नई रेल लाइन से यात्रियों के लिए अतिरिक्त ट्रेनों की सुविधा उपलब्ध होगी। इससे विभिन्न शहरों और कस्बों के बीच यात्रा करना अधिक सुगम होगा। ट्रेनों की संख्या में वृद्धि से भीड़भाड़ कम होगी और यात्रियों को अधिक आरामदायक यात्रा अनुभव प्राप्त होगा। तीन लाइनें होने से ट्रेनों की निर्बाध आवागमन सुनिश्चित होगी। अत्याधुनिक सिगनलिंग और ट्रैक संरचना से यात्रा अधिक संरक्षित होगी।

पर्यटन को बढ़ावा: यह परियोजना बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और अन्य पर्यटन स्थलों तक पहुँच को और सरल बनाएगी। रेलवे द्वारा नई ट्रेनों के संचालन से पर्यटकों को बेहतर सुविधा मिलेगी, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी लाभ होगा।

परियोजना का संक्षिप्त विवरण

- कुल लंबाई : 165.52 कि.मी.
- स्वीकृत लागत : ₹2311.02 करोड़
- कुल स्टेशन : 17 (1 जंक्शन स्टेशन : अनुपपुर)
- यात्री हॉल्ट : 2 (सिंहपुर, विलायतकलां)

इस परियोजना के अंतर्गत कुल 27 बड़े ब्रिज और 108 छोटे ब्रिज के निर्माण किए गए हैं। इन ब्रिजों के निर्माण से रेलवे लाइन की मजबूती बढ़ी है और ट्रेनों की आवाजाही अधिक संरक्षित व निर्बाध हो गई है। नदी-नालों और पहाड़ी क्षेत्रों से गुजरने वाली इस रेल लाइन में ब्रिजों का विशेष महत्त्व है, जिससे वर्षा ऋतु में भी यातायात प्रभावित न हो। इसके अतिरिक्त, एक रेलवे ओवर ब्रिज और 16 रेलवे अंडर ब्रिज का निर्माण किया गया है। ओवर ब्रिज के माध्यम से सड़क और रेल यातायात के बीच संरक्षा को और अधिक सुनिश्चित किया गया है। वहीं, रेलवे अंडर ब्रिज से स्थानीय ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच आवागमन सुगम हुआ है।

भारतीय रेल
पत्रिका

अब
सोविनियर शॉप
राष्ट्रीय रेल संग्रहालय
चाणक्यपुरी, नई दिल्ली में भी उपलब्ध है

प्रगति रिपोर्ट

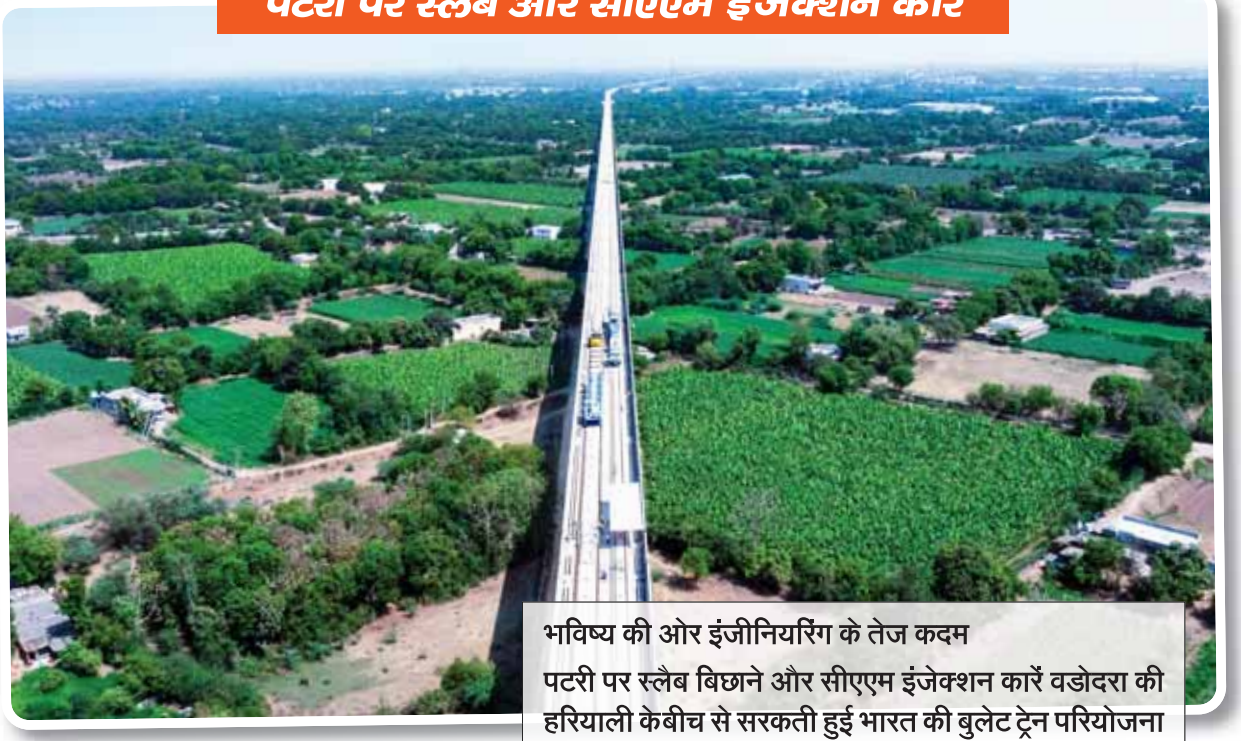
मुंबई के विक्रोली शाफ्ट का काम प्रगति पर



मुंबई के विक्रोली शाफ्ट के कार्य प्रगति पर : महाराष्ट्र में स्थित यह स्थान भारत की सबसे बड़ी भूमिगत रेल सुरंग के लिए एक महत्त्वपूर्ण प्रवेश बिंदु है, जो मुंबई–अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना का हिस्सा है।

23 जून, 2025

पटरी पर स्लैब और सीएएम इंजेक्शन कारें



भविष्य की ओर इंजीनियरिंग के तेज कदम

पटरी पर स्लैब बिछाने और सीएएम इंजेक्शन कारें वडोदरा की हरियाली केबीच से सरकती हुई भारत की बुलेट ट्रेन परियोजना को तेजी से आगे बढ़ा रही हैं।

25 जून, 2025

वडोदरा, गुजरात में एमएएचएसआर कॉरिडोर का कार्य प्रगति पर



सुसंगठित तालमेल के साथ तेजी से आगे बढ़ते हुए, वडोदरा में एमएएचएसआर कॉरिडोर पर ट्रैक निर्माण कार्य जारी है। यहाँ पहले ट्रैक पर स्लैब बिछाए जा रहे हैं, सीमेंट-डामर मोर्टार का इंजेक्शन किया जा रहा है। यहाँ उच्च गति वाली ट्रेन सेवा के लिए मजबूत नींव तैयार हो रहा है।

24 मई, 2025

विरार बुलेट ट्रेन स्टेशन, महाराष्ट्र में स्लैब कास्टिंग शुरू



महाराष्ट्र के विरार बुलेट ट्रेन स्टेशन में स्लैब कास्टिंग का कार्य शुरू हो गया है। नौ स्लैबों में से पहले स्लैब पर ट्रैक बिछाकर उसे स्थापित कर दिया गया है। यह स्टेशन एक पहाड़ी पर स्थित है। इसकी डिजाइन पर्वतीय हवाओं को समेटने के उद्देश्य से तैयार की गई है।

2 जून, 2025

एमएएचएसआर कॉरिडोर का काम प्रगति पर



महाराष्ट्र–गुजरात सीमा के संधि–स्थल पर, एमएएचएसआर कॉरिडोर की प्रगति का एक अद्भुत क्षण सामने आया–वलसाड (गुजरात) में लॉन्चिंग गैंट्री सक्रिय है और पृष्ठभूमि में जरौली की पहाड़ी सुरंग अपने अंतिम चरण में है।

2 जुलाई, 2025

ऋषिकेश–कर्णप्रयाग ब्रॉड गेज परियोजना



ऋषिकेश–कर्णप्रयाग ब्रॉड गेज परियोजना ने गुलर और ब्यासी के बीच 6.67 कि.मी. लंबी सुरंग का सफल ब्रेकथ्रू की एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। यह सफलता अत्याधुनिक टनलिंग तकनीक और सटीक योजना का परिणाम है।

12 जून, 2025

कालंबोली, महाराष्ट्र में रेल फ्लाईओवर गर्डर



भारतीय रेल ने डिजाइन और माल परिवहन की सीमाओं को पार करते हुए, पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारे पर महाराष्ट्र के कालंबोली में 1500 टन वजन वाले और 110.5 मीटर लंबा रेल फ्लाईओवर गर्डर लॉन्च किया है।

25 मई, 2025

एडवांस टेक्नोलॉजी से सुरक्षित रेल ट्रैक



सुरक्षित रेल संचालन के लिए उत्तर प्रदेश के आगरा मंडल में अल्ट्रासोनिक फ्लॉ डिटेक्शन मशीनों से 1,300 कि.मी. से अधिक ट्रैक की नियमित जाँच हो रही है।

24 जून, 2025

पहली 3डी प्रिंटेड इमारत 'गैंगमैन हट'



भारतीय रेल ने सतत अवसंरचना के क्षेत्र में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। आंध्र प्रदेश के परवतिपुरम रेलवे स्टेशन पर अपनी पहली 3डी प्रिंटेड इमारत 'गैंगमैन हट' का निर्माण केवल 25 दिनों में 3डी कंक्रीट प्रिंटिंग तकनीक से किया गया।

2 जुलाई, 2025

मिजोरम की भैरबी–साईरंग सेक्शन रेल सुरंग



मिजोरम की भैरबी–साईरंग सेक्शन रेल सुरंग क्षेत्रीय विशेषताओं से सजी है, जो समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का उत्सव है।

23 जून, 2025

अनूपुर–कटनी तीसरी लाइन परियोजना (165.52 कि.मी.)



पूर्ण रूप से तैयार

लाभ

- लाइन की क्षमता बढ़ी और कोयला व खनिज ढुलाई में तेजी आई
- बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के पर्यटन में वृद्धि
- छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बीच यातायात में प्रोत्साहन

14 जून, 2025

अत्याधुनिक 503–रूट इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम, गोरखपुर जंक्शन



गोरखपुर जंक्शन ट्रेन की गति और रफ्तार और सुरक्षा देते हुए अत्याधुनिक 503–रूट इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम से संचालित हो रहा है।

6 मई, 2025

नागपुर स्टेशन पर अनोखा रेल पुस्तकालय



महाराष्ट्र के नागपुर स्टेशन पर एक अनोखी 'रेल लाइब्रेरी' की शुरुआत हुई है। 'हर पन्ने पर एक यात्रा' थीम पर आधारित इस लाइब्रेरी में 'पुस्तक लें, पुस्तक दें' की अवधारणा के तहत मुफ्त पुस्तकें उपलब्ध हैं, जो हर यात्रा को और भी ज्ञानवर्धक बनाती है।

4 जुलाई, 2025

धुले स्टेशन बना महाराष्ट्र का तीसरा पूर्णतः हरित 'अमृत स्टेशन'



सौर ऊर्जा से रेल को नई दिशा : धुले रेलवे स्टेशन, देवलाली और रावेर के बाद, महाराष्ट्र का तीसरा पूर्णत: हरित अमृत स्टेशन बना है। यहाँ 47 किलोवाट पीक क्षमता वाला रूफटॉप सोलर प्लांट लगाया गया है, जिसका लक्ष्य हर साल लगभग 68,620 यूनिट सौर ऊर्जा उत्पन्न करना है।

3 जुलाई, 2025

अमृत भारत स्टेशन

भारतीय रेल ढाँचे की कायापलट करने वाली योजना

















वी. सी. प्रमोद

भारत का रेल नेटवर्क, जिसे देश की जीवनरेखा भी कहा जाता है, इन दिनों 'अमृत भारत स्टेशन योजना' (एबीएस) के तहत एक व्यापक बदलाव के दौर में है। रेल मंत्रालय द्वारा शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य देशभर के 1300 से अधिक रेल स्टेशनों का आधुनिकीकरण और पुनर्विकास करना है, ताकि वे अधिक सुलभ, सुविधाजनक और वैश्विक मानकों के अनुरूप बन सकें। यह योजना भारत के बुनियादी ढाँचे के विकास की व्यापक दृष्टि का हिस्सा है, जो सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखते हुए यात्रा अनुभव को बेहतर बनाने के साथ एक विकसित राष्ट्र बनने की आकांक्षा को दर्शाती है।

पृष्ठभूमि और शुभारंभ

अमृत भारत स्टेशन योजना (एबीएसएस) की औपचारिक शुरुआत वर्ष 2022 में हुई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य रेलवे स्टेशनों को विश्वस्तरीय यात्रा केंद्रों में बदलना है। इससे पहले केवल कुछ चुनिंदा बड़े स्टेशनों पर ध्यान दिया जाता था, जबकि यह योजना एक समावेशी और व्यापक दृष्टिकोण अपनाती है, जिसमें छोटे कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों के स्टेशन भी शामिल हैं। यह विकेंद्रीकरण सुनिश्चित करता है कि विकास केवल शहरी केंद्रों तक सीमित न रहे, बल्कि देश के हर हिस्से में समान रूप से फैले।

इस योजना का औपचारिक उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दिनांक 6 अगस्त, 2023 को किया गया। उस एक ही दिन में 508 स्टेशनों के पुनर्विकास के शिलान्यास किए गए। इन स्टेशनों का चयन क्षेत्रीय और जनसांख्यिकीय संतुलन को ध्यान में रखकर किया गया, ताकि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व हो सके।



अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कई मुख्य उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं :

1. **आधुनिकीकरण और पुनर्विकास**– मूलभूत सुविधाओं, प्रतीक्षालयों, टिकट प्रणाली और प्लेटफॉर्म सुधार किए गए, ताकि यात्रियों को स्वच्छ, सुविधाजनक और आधुनिक सेवाएँ मिल सकें।
2. **मल्टीमॉडल एकीकरण**– स्टेशन को बस, मेट्रो और हवाई अड्डों जैसे अन्य परिवहन माध्यमों से जोड़ना, जिससे यात्रा सहज और सरल बने।
3. **सतत विकास और हरित पहल**– सौर पैनल, वर्षा जल संचयन और अपशिष्ट प्रबंधन जैसी पर्यावरण-अनुकूल तकनीकों का समावेश।
4. **सांस्कृतिक समावेश**– स्थानीय कला, संस्कृति और विरासत को स्टेशन की वास्तुकला और आंतरिक साज-सज्जा में दर्शाना।
5. **डिजिटल परिवर्तन**– स्मार्ट टेक्नोलॉजी जैसे स्वचालित टिकटिंग, एआई आधारित निगरानी, मुफ्त हाई-स्पीड वाई-फाई और सूचना डिस्प्ले सिस्टम का समावेश।
6. **वाणिज्यिक और खुदरा विकास**– स्टेशन परिसर का उपयोग व्यावसायिक गतिविधियों के लिए करना ताकि यात्रियों की सुविधा और रेलवे की आय दोनों में वृद्धि हो।

पुनर्विकसित स्टेशनों की विशेषताएँ

अमृत भारत योजना के तहत विकसित स्टेशनों में निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएँ होंगी :

- भीड़-भाड़ से राहत के लिए खुले विशाल कोनकोर्स (प्रांगण), जिन्हें बढ़ती यात्री संख्या को संभालने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- यात्रियों की प्रतीक्षा और विश्राम के लिए रूफ प्लाजा, जिसमें फूड कोर्ट, खुदरा दुकानें और लाउंज जैसी सुविधाएँ होंगी।
- कई भाषाओं में स्पष्ट और प्रभावी संकेतक, जिससे सभी प्रकार के यात्रियों को मार्गदर्शन मिल सके।
- दिव्यांग यात्रियों के लिए सुविधाजनक रैंप, दृष्टिबाधितों के सहयोग के लिए स्पर्श पथ और सहायता काउंटर।
- बेहतर प्रकाश व्यवस्था, वेंटिलेशन और सुरक्षा के लिए उच्च स्तरीय निगरानी प्रणाली।

इन सुविधाओं का उद्देश्य रेलवे स्टेशनों को हवाई अड्डों जैसे आधुनिक और आरामदायक सुविधाओं में बदलना है, ताकि स्टेशन केवल यात्रा के बिंदु न रहकर सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र बन सकें।



वित्तपोषण और क्रियान्वयन

एबीएसएस केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित है और इसे भारतीय रेल के क्षेत्रीय रेलवे, मंडलों के माध्यम से रेल मंत्रालय की निगरानी में क्रियान्वित किया जा रहा है। किसी भी स्टेशन के पुनर्विकास में आमतौर पर ₹20 करोड़ से ₹400 करोड़ तक का खर्च आता है, जो स्टेशन के आकार, यात्री भार और रणनीतिक महत्त्व पर निर्भर करता है।

रेलवे भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए), इरकॉन इंटरनेशनल और अन्य सार्वजनिक उपक्रमों के साथ मिलकर भारतीय रेल इन परियोजनाओं को पारदर्शी निविदा प्रक्रिया के तहत निजी ठेकेदारों और सलाहकारों की मदद से पूरा कर रहा है। परियोजनाओं के लिए निर्धारित समय सीमा और गुणवत्ता मानकों का पालन अनिवार्य है।

सामाजिक और आर्थिक प्रभाव

अमृत भारत योजना केवल सौंदर्यीकरण की योजना नहीं है, बल्कि यह एक दूरदर्शी निवेश है, जिसके व्यापक सामाजिक और आर्थिक प्रभाव हैं :

- **रोजगार सृजन**– निर्माण, इंजीनियरिंग और संचालन में प्रत्यक्ष तथा खुदरा, खाद्य और सेवा क्षेत्रों में परोक्ष रूप से हजारों नौकरियाँ।
- **स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा**– बेहतर रेलवे बुनियादी ढाँचे से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, लॉजिस्टिक्स में सुधार होगा और ग्रामीण उत्पादकों को बाजार तक बेहतर पहुँच मिलेगी।



- **समावेशी विकास**– छोटे और मझौले स्टेशनों पर ध्यान देने से जमीनी स्तर तक विकास पहुँचेगा, जिससे क्षेत्रीय असंतुलन में कमी आएगी।
- **पर्यावरणीय लाभ**– सुविधाओं और संपर्क व्यवस्था में सुधार के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन को प्रोत्साहित कर, अमृत भारत स्टेशन योजना (एबीएसएस) भारत के जलवायु लक्ष्यों का समर्थन करती है, क्योंकि इससे निजी वाहनों पर निर्भरता कम होती है।

अब तक की प्रगति और उपलब्धियाँ

वर्ष 2025 की शुरुआत तक 500 से अधिक स्टेशन सक्रिय रूप से पुनर्विकास प्रक्रिया में हैं और दर्जनों स्टेशन पूरे होने की कगार पर हैं। कुछ स्टेशन, जैसे अयोध्या (उत्तर प्रदेश), रानी कमलापति (मध्य प्रदेश) और गांधीनगर कैपिटल (गुजरात) पहले ही





आधुनिक और आर्कषक परिवर्तनों के साथ सामने आ चुके हैं और अन्य स्टेशनों के लिए मिसाल बने हैं।

कई स्टेशनों पर अब विरासत दीर्घाएँ (हेरीटेज गैलरीज) भी बनाई जा रही हैं, जहाँ स्थानीय इतिहास और हस्तशिल्प प्रदर्शित किए जाते हैं- जिससे ये स्टेशन सांस्कृतिक केंद्र बन जाते हैं।

चुनौतियाँ और आगे की राह

इस महत्त्वाकांक्षी योजना को कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ रहा है, जो इस प्रकार हैं-

- **भूमि अधिग्रहण**- शहरी क्षेत्रों में स्टेशन विस्तार के लिए जमीन उपलब्ध कराना कठिन।
- **राज्य एजेंसियों के साथ समन्वय**- परियोजनाओं में बिजली, पानी, सीवर आदि के लिए स्थानीय निकायों से अनुमति और सहयोग आवश्यक है।
- **बजट सीमाएँ**- निधियों की समय पर फंड की उपलब्धता और प्रभावी उपयोग अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।
- **संवेदनशील पुनर्विकास**- ऐतिहासिक महत्त्व के स्टेशनों के आधुनिकीकरण में वास्तुकला विरासत को बनाए रखना।

इन समस्याओं से निपटने के लिए भारतीय रेल चरणबद्ध रणनीति अपना रही है, जिसमें पहले उच्च यात्री भार और रणनीतिक महत्त्व वाले स्टेशनों को प्राथमिकता दी जा रही है।

निष्कर्ष

अमृत भारत स्टेशन योजना भारत की बुनियादी ढाँचा विकास यात्रा में एक ऐतिहासिक कदम है। यह रेलवे स्टेशनों को आधुनिक, कुशल और समावेशी स्थानों में बदलने का संकल्प है, जिससे यात्रियों का अनुभव तो सुधरे ही, साथ ही क्षेत्रीय विकास, सतत प्रथाओं और भारत की उन्नत छवि को भी बल मिले।



स्टेशन अब केवल यात्रा के प्रवेश द्वार नहीं, बल्कि आर्थिक गतिविधियों और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के केंद्र बनेंगे। राजनीतिक इच्छाशक्ति, तकनीकी नवाचार और जनभागीदारी के साथ, यह योजना विकासशील देशों के लिए आधारभूत ढाँचे के परिवर्तन का एक मॉडल बन सकती है।



प्लेटफॉर्म पर खड़ी वैगई एक्सप्रेस

दक्षिण भारत में वादियों की सैर कराती वैगई एक्सप्रेस

विमलेश चंद्र
सेवानिवृत्त, रेल अधिकारी

एक ही दिन में दो बड़े शहरों के बीच यात्रा कराने वाली देश की तीन ट्रेनें विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं– मध्य रेलवे की डेक्कन क्वीन, दक्षिण रेलवे की वैगई एक्सप्रेस और पश्चिम रेलवे की कर्णावती एक्सप्रेस। इनमें दक्षिण रेलवे की वैगई एक्सप्रेस सुप्रसिद्ध और ऐतिहासिक ट्रेन है। वैसे तो इस तरह की और भी ट्रेनें प्रसिद्ध हैं, लेकिन उन सभी का स्थान इनके बाद ही आता है। शायद इन तीनों ट्रेनों के प्रसिद्ध होने का मुख्य कारण यह है कि इससे ज्यादातर यात्री प्रतिदिन अप-डाउन यात्रा करते हैं, जिनमें अधिकतर नौकरी करने वाले और मध्यम वर्ग के व्यापारी हैं। मजे की बात है कि इन तीनों में नियमित यात्रा करने वाले यात्री इन ट्रेनों का जन्मदिन भी मनाते हैं।

रेलवे भी इन ट्रेनों का विशेष तौर पर ध्यान रखती है, क्योंकि इनमें यात्रा करने वाले ज्यादातर लोग नौकरी पेशा से हैं, तो वे तय समय पर नौकरी पर पहुँच जाएं। इन तीनों ट्रेनों में लगे पैंट्रीकार में उच्च क्वॉलिटी के खाने की व्यवस्था है। वैगई एक्सप्रेस में भी खाने की व्यवस्था शानदार है। मदुरै से जब यह ट्रेन खुलती है तो काफी दूर तक घाटियाँ इसका साथ देती हैं। मतलब रेल



लाइन के दोनों तरफ ऊँचे-ऊँचे पर्वत दिखाई देते हैं, जिसकी खूबसूरती के क्या कहने? पहली बार मुझे दिनांक 1 मार्च, 2025 को वैगई एक्सप्रेस में यात्रा करने का अवसर मिला। लिहाजा इसकी रोचक जानकारी लिखना उचित लगा।

गौरवपूर्ण इतिहास- वैगई एक्सप्रेस मदुरै जंक्शन से एग्मोर के लिए दिनांक 15 अगस्त, 1977 की सुबह 06:00 बजे पहली बार रवाना हुई। वह इस ऐतिहासिक ट्रेन की उद्घाटन यात्रा थी। उस दिन इस ट्रेन में पीले और हरे मिलेजुले रंग वाले कुल 16 कोच जुड़े थे। इन कोचों को मीटर गेज के दो डीजल इंजन YDM4 से जोड़ा गया था। उस दिन यह रेलगाड़ी दोपहर 01:05 बजे मद्रास एग्मोर स्टेशन पहुँची थी और 7 घंटे, 15 मिनट में अपनी यात्रा पूरी कर ली थी। ऐसा करके इस ट्रेन ने दक्षिण रेलवे की कई बड़ी रेलगाड़ियों की गति से बराबरी कर ली थी। बाद में इसकी गति को धीमा कर दिया गया और फिर यह ट्रेन 7 घंटे और 40 मिनट में अपनी यात्रा पूरी करने लगी। वैगई नदी, मदुरै शहर से होकर गुजरती है। इस रेलगाड़ी का नाम वैगई नदी के नाम पर रखा गया है। दिनांक 15 अगस्त, 1984 को इस रेलगाड़ी को विभाजित कर दिया गया और एक नई रेलगाड़ी पल्लवन सुपरफास्ट एक्सप्रेस (12605/12606) की शुरुआत की गई, जिसमें आठ कोच थे। वर्ष 2000 तक चेन्नई-तिरुचिरापल्ली-मदुरै रेलवे खंड पर वैगई एक्सप्रेस और पल्लवन एक्सप्रेस, दोनों एकमात्र सुपरफास्ट रेलगाड़ियाँ थीं। उस समय इस रेलगाड़ी के केवल तीन स्टॉपेज थे- विल्लुपुरम जंक्शन, तिरुचिरापल्ली जंक्शन और डिंडीगुल जंक्शन। बाद में इसके स्टॉपेज की संख्या बढ़ा दी गई।

बदलता रहा कलेवर- वैगई सुपरफास्ट का शुरुआत में रेलगाड़ी नंबर 135/136 था। फिर चार अंकों के नंबर होने पर इसका नंबर 2635/2636 हो गया। फिर पाँच अंकों का नंबर होने पर इस रेलगाड़ी का नंबर 12635/36 हो गया। यह एक इंटरसिटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन है। यह मदुरै और चेन्नई एग्मोर के बीच तिरुचिरापल्ली के रास्ते प्रतिदिन चलती है। वैगई सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन को प्यार से ष्दक्षिण रेलवे का राजाष कहा जाता है, जबकि चेन्नई एग्मोर और कराईकुडी जंक्शन के बीच चलने वाली इसकी रैक शेयर करने वाली रेलगाड़ी का नाम 'पल्लवन एक्सप्रेस' है, जिसे 'दक्षिण रेलवे का राजकुमार' कहा जाता है। इन दोनों रेलगाड़ियों को एक साथ मिलाकर मतलब सामूहिक रूप से 'कॉर्ड लाइन ब्रदर्स' ट्रेन के नाम से जाना जाता है।

इस रेलगाड़ी का रैक पहले, यानी मीटर गेज के समय भी केवल वैगई एक्सप्रेस और पांडियन एक्सप्रेस में शेयर होता था और अभी भी केवल इसी दो ट्रेन में शेयर होता है। इस रेलगाड़ी को दिनांक 30 जून, 2019 से आधुनिक एलएचबी कोच के साथ संचालित किया जा रहा है। वर्तमान में इसके कुल 12 स्टेशनों पर स्टापेज हैं और इसमें कुल 22 कोच लगते हैं। वर्तमान में इसकी औसत गति 75 कि.मी. प्रति घंटे है और वर्तमान में यह चेन्नई एग्मोर से तिरुचिरापल्ली तक कोर्ड रेलवे लाइन और तिरुचिरापल्ली से मदुरै तक मेन रेल लाइन के रूट से चलती है।

बिजली इंजन से संचालन- जैसा कि हम जानते हैं, भारतीय रेल में सर्वप्रथम मीटर गेज विद्युतीकृत रेलमार्ग वर्ष 1931 में मद्रास बीच स्टेशन से ताम्बरम स्टेशन के बीच शुरू किया गया था, जिसका उद्घाटन सर जॉर्ज एफ. स्टेनली ने दिनांक 2 अप्रैल, 1931 को उपनगरीय रेल सेवा के अंतर्गत उद्घाटन किया था। इसे जनसामान्य के लिए दिनांक 11 मई, 1931 को खोल दिया गया था। यह 1500 वोल्ट DC संकर्षण वाली प्रणाली थी। फिर वर्ष 1965 में इसे 1500 वोल्ट DC संकर्षण प्रणाली से 25KV-AC संकर्षण प्रणाली में बदल दिया गया था।

इसके लिए वर्ष 1964 में जापान से 25KV-AC संकर्षण प्रणाली वाली मीटर गेज के 20 बिजली इंजन मँगवाए गए थे। जापान से मीटर गेज के जो 20 बिजली इंजन मँगवाए गए थे, उसी में से कुछ बिजली इंजन, वैगई एक्सप्रेस में काफी दिनों बाद, वर्ष 1995 में लगनी शुरू हो गई थी और फिर वर्ष 1997 में गेज परिवर्तन के कारण इस ट्रेन को कैंसिल कर दिया गया। अंततः चेन्नई (मद्रास) से जुड़े पूरे खंड का गेज परिवर्तन करने के लिए मीटर गेज की बिजली रेलगाड़ी को दिनांक 30 जून, 2004 को और इस उपनगरीय मीटर गेज बिजली वाले रेल मार्ग को दिनांक 1 जुलाई, 2004 को 73 वर्षों की सेवा के बाद हमेशा के लिए बंद कर दिया गया।

इस बीच चेन्नई एग्मोर से ताम्बरम और फिर मदुरै के बीच मीटर गेज परिवर्तन का कार्य छोटे-छोटे खंड में चलता रहा, जिसमें दिनांक 1 जनवरी, 1998 को ताम्बरम से तिरुचिरापल्ली तक के कोर्ड लाइन के 310 कि.मी. लंबे सेक्शन को बड़ी लाइन में बदल दिया गया। फिर तिरुचिरापल्ली से डिंडीगुल जंक्शन रेलवे स्टेशन तक के 93 कि.मी. लंबी कोर्ड लाइन दिनांक 6 जनवरी, 1999 को खोला गया। वर्ष 1998-99 में मीटर गेज परिवर्तन का कार्य पूरा होने पर वैगई सुपरफास्ट एक्सप्रेस को मीटर गेज से बदल कर ब्रॉड गेज में परिवर्तित कर दिया गया और वैगई सुपरफास्ट एक्सप्रेस की डीजल इंजन से शुरुआत की गई और इसे गोल्डन रॉक डीजल शेड के डीजल इंजनों द्वारा चलाया जाने लगा। वैगई एक्सप्रेस को दिनांक 12 फरवरी, 2014 से 9 जुलाई 2015 तक, WAP-4 श्रेणी के बिजली इंजन द्वारा चलाया जाता



रहा। फिर दिनांक 9 जुलाई, 2015 से अब तक इसे नियमित रूप से WAP-7 श्रेणी के बिजली इंजनों द्वारा चलाया जा रहा है। इस इंजन का रखरखाव इलेक्ट्रिक लोको शेड, रॉयपुरम द्वारा किया जाता है।

रोचक रिकॉर्ड– यह दक्षिण रेलवे में मीटर गेज लाइन पर चलने वाली पहली सुपरफास्ट ट्रेन रही है। इस सेक्शन में दोहरी रेल लाइन होने से वैगई एक्सप्रेस के गति में रुकावट नहीं होती थी। दिनांक 3 मार्च, 2022 को वैगई एक्सप्रेस ट्रेन ने मदुरै से चेन्नई तक 495 कि.मी. की दूरी 6 घंटे 40 मिनट में तय करके ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया था। ऐसा करके इसने दिनांक 15 अगस्त, 1977 को स्थापित 7 घंटे 5 मिनट का अपना ही उद्घाटन रिकॉर्ड तोड़ दिया था। यह रिकॉर्ड दिनांक 15 अक्टूबर, 2022 को एक बार फिर से टूट गया था, जब मदुरै से चेन्नई की दूरी को इसने 6 घंटे और 34 मिनट में पूरी कर लिया था। शुरुआत में यह दक्षिण रेलवे की एकमात्र रेलगाड़ी थी, जिसके सभी आठ द्वितीय श्रेणी के कोचों के अंदर पहली बार पूरी तरह ट्यूब लाइट लगाए गए थे और साथ ही साथ सूर्य के तेज रोशनी से बचाव वाले स्लाइडिंग ग्लास शटर लगाए गए थे। यह दक्षिण रेलवे में मीटर गेज लाइन पर ऐसी पहली रेलगाड़ी थी, जिसमें विशेष रूप से उन्नत बफर्स लगाए गए थे और यह 110 कि.मी./घंटा की गति से चलने के लिए सक्षम थी। मीटर गेज के समय में पहली बार, आईसीएफ कारखाना चेन्नई ने वैगई एक्सप्रेस और पल्लवन एक्सप्रेस के लिए विशेष रूप से दो, 40-सीटों वाले एसी चेयर कार कोचों का निर्माण किया था और इस रेलगाड़ी में इस एसी चेयरकार कोच का साफल्य सफलता पूर्वक उपयोग किया। यह दिनांक 6 सितंबर, 2011 को डिंडीगुल-त्रिची सेक्शन के 92 कि.मी. लंबे सेक्शन में 25-केवी ऐ सी सिस्टम वाला विद्युतीकरण पूरा होने के बाद मदुरै रेलवे मंडल में इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन पर चलने वाली पहली ट्रेन थी। इसका मीटर गेज बिजली इंजन और ट्रेन, पहले 1500 वोल्ट DC पर चली थीं और फिर जब इस बिजली वाली रेल लाइन को 1500 वोल्ट डीसी से 25 KV AC में बदला गया तो इस रेलगाड़ी यह मीटर गेज बिजली इंजन पहली बार हाई रॉइज पेंटोग्राफ के साथ 25 KV AC पर भी चली थी। एक तरह से यह भारतीय रेल की की पहली हाई राइज पेंटोग्राफ वाली रेलगाड़ी थी।

इसका एक रिकार्ड यह भी हुआ कि वैगई एक्सप्रेस पहले मीटर गेज के डीजल इंजन से चली और फिर मीटर गेज कर बिजली इंजन से चली। फिर गेज परिवर्तन के बाद बड़ी लाइन के डीजल इंजन से चली और फिर विद्युतीकरण होने पर बड़ी लाइन की बिजली इंजन से चल रही है। ऐसा अनोखा रिकार्ड शायद और कोई न हो।

वर्ष 1977 में इसके मीटर गेज कोच को 100 कि.मी. प्रति घंटा की गति से चलने के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किया गया था। इसके इंजन को भी 100 कि.मी. प्रति घंटा की गति से चलने के लिए कनाडा से डीजल इंजन को आयात किया गया था। दक्षिण रेलवे में 100 कि.मी. प्रति घंटे की गति से चलने वाली यह पहली मीटर गेज ट्रेन थी। इसके कोच और इंजन को स्पेशल हरे रंग और पीले रंग के साथ मिलाकर के पेंटिंग किया गया था। मीटर गेज का यह पहला इंजन था, जिसमें जनता की सुरक्षा के पहली बार किसी इंजन में 2 हॉर्न लगाया गया था। यह पहली ऐसी रेलगाड़ी थी, जिसमें गार्ड और ड्राइवर के बीच में संचार या बातचीत के लिए कोड (वायर) वाली इंटर कनेक्शन फोन प्रदान किया गया था। इसके पहले दिन का गति का रिकॉर्ड, बड़ी लाइनों के तेज गति वाली रेलगाड़ियाँ के बराबर थी। इस ट्रेन को हमेशा काफी महत्त्व दिया जाता था और मीटर गेज के समय हमेशा इसके लिए में डबल सेक्शन में लाइन क्लियर दिया जाता था। यह भारत की पहली ऐसी रेलगाड़ी थी, जिसमें अल्मुनियम वाली खिड़की और कोच में ट्यूबलाइट लगाया गया था। यह भारत की पहली ऐसी मीटर गेज ट्रेन थी, जिसमें सबसे पहले एसी चेयर कार लगाया गया था। यह भारत की पहली ऐसी मीटर गेज ट्रेन थी, जिसमें शटर विंडो और ग्लास विंडो लगाया गया था। 3 मार्च को इसने मदुरई से चेन्नई एग्मोर के बीच 495 कि.मी. की दूरी की यात्रा करने में केवल 6 घंटा 43 मिनट लिया और अपनी उद्घाटन के समय का रिकॉर्ड तोड़ दिया था और इसकी यह गति देश की प्रतिष्ठित राजधानी एक्सप्रेस, दुरंतो एक्सप्रेस और तेजस एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों से गति के रहती है।

कुछ यादगार मौके– दिनांक 15 अगस्त 1977 को इसका उद्घाटन हुआ था, उस दिन इसकी अधिकतम गति 100 कि.मी. प्रति घंटे थी और इसने 495 कि.मी. की दूरी केवल 7 घंटे 5





मिनट में पूरी कर ली थी लेकिन सुरक्षा कारणों से बाद में इसका यह समय बढ़ाकर 7 घंटा 40 मिनट कर दिया गया। यह उस समय भारतीय रेल में मीटर गेज की सबसे तेज गति वाली ट्रेन थी। बीच-बीच में यह कई बार देर होती रही, तो इसकी वजह से वर्ष 1979 में इसमें शक्तिशाली मीटर गेज के YDM-4A वाले दो इंजन लगाए जाने लगे। वर्ष 1994 में एसी चेयर कार कोच लगाया गया। इस तरह से यह भारतीय रेल में मीटर गेज की पहली ट्रेन हो गई, जिसमें पहली बार एसी चेयर कर लगाया गया। वर्ष 1995 में इसमें पहली बार चेन्नई एग्मोर से विजुपुरम के बीच में YAM-1 मीटर गेज बिजली इंजन लगाया गया। वर्ष 1997 में गेज परिवर्तन के कारण इस ट्रेन को कैंसिल कर दिया गया। वर्ष 1998-99 में इस रेलगाड़ी को फिर से 16 कोच और एक बड़ी लाइन वाला डीजल इंजन WDM-2 के साथ फिर से शुरुआत की गई। वर्ष 2003 में चेन्नई एग्मोर और विल्लुपुरम स्टेशन तक के सेक्शन का विद्युतीकरण हो जाने के बाद इसे चेन्नई एग्मोर से विल्लुपुरम स्टेशन तक WAP-4 बिजली इंजन द्वारा चलाया जाने लगा जबकि बाकी सेक्शन, विल्लुपुरम स्टेशन से मदुरई स्टेशन तक के बीच में इसे दो डब्ल्यूडीएम-2 डीजल इंजन द्वारा चलाया जाने लगा। वर्ष 2006 में इसमें कोचों की संख्या 16 से बढ़ा कर 24 कर दिया गया। फिर विल्लुपुरम स्टेशन से तिरुचिरापल्ली तक विद्युतीकरण पूरा होने पर इसे वर्ष 2008 में चेन्नई एग्मोर से तिरुचिरापल्ली के बीच, बिजली इंजन द्वारा चलाया जाने लगा। जमें इसमें बिजली इंजन लगाया गया। वर्ष 2014 में इसे मदुरै तक बिजली इंजन से चलाए जाने लगा। वर्ष 2015 में इसमें थर्ड एसी चेयर कार कोच लगाया गया। वर्ष 2018 में चेन्नई से मदुरई तक की पूरी रेल लाइन, दोहरी रेल लाइन हो गई तो इसका यात्रा समय कम करके 7 घंटा 45 मिनट कर दिया गया। इस तरह से वैगई एक्सप्रेस, उस समय की सबसे तेज एक्सप्रेस इंटरसिटी ट्रेन हो गई थी। वर्ष 2019 में वैगई एक्सप्रेस को एलएचबी कोच में बदल दिया गया। वर्ष 2022 में वैगई एक्सप्रेस के यात्रा समय को फिर से घटा कर के 7 घंटा 25 मिनट कर दिया गया। जो शताब्दी एक्सप्रेस के बराबर की गति हो गई। वर्ष 2023 में फिर इसका यात्रा समय कम करके 7 घंटा 15 मिनट कर दिया गया।

रेल, पर्यटन व साहित्य को एक साथ संजोए

रेल मंत्रालय द्वारा विगत 69 वर्षों
से भी अधिक समय से प्रकाशित मासिक पत्रिकाओं

अब ई-पत्रिका भी उपलब्ध

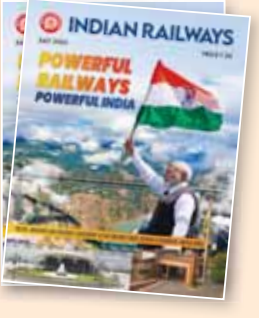
की सदस्यता अब
ऑनलाइन
भी उपलब्ध



भारतीय रेल
(हिन्दी)

क्यू आर कोड स्कैन करें

विज़िट करें



Indian Railways
(English)

www.irctctourism.com/IRBRmag/#/home/hn

दरें एवं शर्तें लागू

एक पृथ्वी, एक स्वास्थ्य

योग



डॉ. वी चन्नामल्लिकार्जुना (आईआरपीएफएस)
उप महानिरीक्षक सह, मुख्य सुरक्षा आयुक्त, रेसुब, उपरे जयपुर

योग शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक अभ्यास की एक शाश्वत परंपरा है, जिसकी उत्पत्ति भारत में हुई। महर्षि पतंजलि ने अपने मौलिक ग्रंथ 'योगसूत्र' में योग के रूपों को व्यवस्थित किया। योग का शाब्दिक अर्थ है 'जुड़ना या एकजुट होना' जो मन और आत्मा के साथ शरीर के सामंजस्यपूर्ण मिलन का प्रतीक है। योग अभ्यास में आसन, ध्यान और श्वास शामिल हैं। इसे आठ अंगों में संरचित किया गया है, जिसमें यम- संयम; नियम-तपस्या का पालन, आसन-मुद्राएँ, प्राणायाम-सांस पर नियंत्रण, प्रत्याहार-इंद्रियों को नियंत्रित करना, धारणा-चिंतन, ध्यान एकाग्रचित होना और समाधि-गहन ध्यान आदि शामिल हैं।

योग को अब वैश्विक स्तर पर वैज्ञानिक और समग्र स्वास्थ्य अनुशासन के रूप में मान्यता प्राप्त है। तनाव, चिंता और अवसाद को कम करने से लेकर मोटापा, उच्च रक्तचाप और मधुमेह आदि जैसी जीवनशैली विकारों को दूर करने तथा शरीर और मन पर इसके परिवर्तनकारी प्रभावों को अच्छी तरह से उल्लेखित किया गया है। यह मानसिक स्पष्टता, भावनात्मक स्थिरता को बढ़ावा देता है और समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है, जिससे व्यक्तियों को स्वस्थ जीवन विकल्प चुनने में मदद मिलती है। योग और जीवनशैली आपस में जुड़े हुए हैं। आज की तेज रफ्तार जीवनशैली की आदतें मन और शरीर दोनों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है। जीवनशैली संबंधी विकार और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ आम हैं जो व्यक्ति, समुदाय और राष्ट्रों के लिए बड़ी चुनौती पेश करती हैं। योग पहले की तुलना में अधिक प्रासंगिक हो गया है। हृदय संबंधी स्वास्थ्य को बढ़ाने, प्रतिरक्षा को बढ़ाने, मनोवैज्ञानिक लचीलापन आदि के लिए योग का अभ्यास करने के लाभों को विभिन्न वैज्ञानिक अध्ययनों में अच्छी तरह से प्रलेखित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा 'योग दिवस अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण की खोज में सबसे बड़े जन आंदोलनों में से एक बन गया है।'

खुशहाल और स्वस्थ मानवता के योगदान में सांस्कृतिक विरासत योग के महत्त्व को समझाते हुए, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस घोषित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र में एक ऐतिहासिक प्रस्ताव रखा। संयुक्त राष्ट्र ने स्वास्थ्य और कल्याण के लिए योग के समग्र दृष्टिकोण को मान्यता दी। विश्व की आबादी के स्वास्थ्य के लिए योग अभ्यास के लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता एक दीर्घकालिक विकास का उद्देश्य है। बेहतर व्यक्तिगत जीवनशैली के निर्माण के उद्देश्य से सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान-प्रदान के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है। दिनांक 11 दिसंबर, 2014 को जनरल असेंबली (यूएनजीए) में सर्वसम्मति से उक्त प्रस्ताव पारित कर 21 जून को 'अंतरराष्ट्रीय योग दिवस' (आईडीवाई) घोषित किया गया। इस प्रस्ताव का 175 संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों ने समर्थन किया। यह व्यापक रूप से समर्थित संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों में से एक है। 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में चुनने के पीछे कारण यह है कि यह तिथि उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन (ग्रीष्म संक्रांति) है और कई देशों में विशेष सांस्कृतिक महत्त्व रखती है।

पहला अंतरराष्ट्रीय योग दिवस दिनांक 21 जून, 2015 को पूरे विश्व में बड़े उत्साह और उल्लास के साथ मनाया गया। इस प्रयास ने योग को वैश्विक मान्यता प्रदान की है और यह सबसे बड़े सार्वजनिक स्वास्थ्य आंदोलनों में से एक बन गया है। अब दुनिया का हर देश भारत की संस्कृति, विरासत और परंपरा अर्थात् योग का जश्न मनाता है। संपूर्ण मानव जाति के हित के लिए योग को दुनिया द्वारा अपनाया जाना देशों के बीच सफल अंतर-सांस्कृतिक संवाद और समझ का प्रमाण है। इसके अलावा, योग को वर्ष 2016 में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) द्वारा 'मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची' में शामिल किया गया था।

आयुष मंत्रालय (एमओए), भारत सरकार अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के वार्षिक उत्सव हेतु नोडल मंत्रालय है। विगत वर्षों में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस को अलग-अलग विषयों के साथ मनाया गया है जैसे कि सद्भाव और शांति के लिए योग (2015, नई दिल्ली); सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए योग (2016, चंडीगढ़); स्वास्थ्य के लिए योग (2017, लखनऊ); शांति के लिए योग (2018, देहरादून); हृदय के लिए योग (2019, रांची); घर पर योग और परिवार के साथ योग (2020); कल्याण के लिए योग (2021); मानवता के लिए योग (2022, मैसूर); वसुधैव कुटुम्बकम् के लिए योग (2023, संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय, न्यूयॉर्क); स्वयं और समाज के लिए योग (2024, श्रीनगर) तथा अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, 2025 का विषय 'एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग' है।

> *"योग दिवस अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण की खोज में सबसे बड़े जन आंदोलनों में से एक बन गया है।"*
>
> **नरेन्द्र मोदी**
> प्रधानमंत्री

हर साल 21 जून को 45 मिनट के लिए कॉमन योग प्रोटोकॉल (सीवाईपी) पर आधारित सामूहिक योग सत्र स्कूलों, कॉलेजों, सार्वजनिक संस्थानों, हाउसिंग सोसाइटियों, ग्राम पंचायतों, खेल स्टेडियम, व्यावसायिक फर्मों, कॉरपोरेट कंपनियों, सांस्कृतिक संगठनों आदि में व्यापक सार्वजनिक भागीदारी के साथ आयोजित किया जाता है। इसके अलावा, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस दुनिया भर के विरासत और प्रतिष्ठित स्थानों, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय (यूएन मुख्यालय) न्यूयॉर्क, ओपेरा हाउस, एफिल टॉवर और ब्रासीलिया के कैथेड्रल आदि पर मनाया जाता रहा है। भारत के प्रधानमंत्री प्रत्येक वर्ष आईडीवाई के समारोह में देश का नेतृत्व करते हैं। यह भारत के स्वतंत्रता समारोह 'आजादी का अमृत महोत्सव' के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में वर्ष 2022 में दुनियाभर के 75वें विरासत और प्रतिष्ठित स्थानों पर आयोजित किया गया था। उक्त वार्षिक उत्सव हेतु सशस्त्र बल और सुरक्षाकर्मी एक साथ आते हैं और सियाचिन ग्लेशियर तक पूरे देश में बड़े उत्साह के साथ अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं।







अंतरराष्ट्रीय योग दिवस अपनी एक व्यापक सार्वजनिक आंदोलन बन गया है, जो स्वास्थ्य, एकता और सद्भाव को बढ़ावा देता है। इसी संदर्भ में आयुष मंत्रालय सेमिनार, प्रतियोगिताएँ और जागरूकता अभियान आयोजित करता है, जिसमें भागीदारी में तेजी से वृद्धि हुई है। वर्ष 2015 में 35,000 प्रतिभागियों से लेकर वर्ष 2023 में 135 से अधिक देशों के 23.4 करोड़ से अधिक लोगों ने भाग लिया और पिछले कुछ वर्षों में कई गिनीज और लिम्का बुक रिकॉर्ड बनाए गए हैं।

योग का क्षितिज तेजी से और व्यापक रूप से फैल रहा है। इसे केंद्रीय सशस्त्र अर्धसैनिक बलों (सीएपीएफ) के प्रशिक्षण के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। विद्यालयों में, योग के क्षेत्र में शिक्षा, अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान (एमडीएनआईवाई) जैसे समर्पित संस्थान स्थापित किए गए हैं। इसे कारागृहों, कॉरपोरेट वातावरण, वेलनेस टूरिज्म आदि में भी बढ़ावा दिया जा रहा है। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर योग को बढ़ावा देने और विकसित करने के लिए व्यक्तियों और संगठनों को वार्षिक पीएम योग पुरस्कार दिए जाते हैं।

दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क में से एक भारतीय रेल (आईआर) देश की जीवन रेखा है। वर्ष 2023-24 में, इसने प्रतिदिन लगभग 19 मिलियन यात्रियों और 4.4 मिलियन टन माल का परिवहन किया। पूरे देश में फैला विशाल रेल सरंचना दुर्भावनापूर्ण कृत्य के लिए एक आसान लक्ष्य है और एक अनूठी सुरक्षा चुनौती पेश करता है। रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) लगभग 75,000 कर्मियों के साथ रेल मंत्रालय के तहत एक सशस्त्र बल है, जिसे इस महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय संपत्ति, यात्री सुरक्षा एवं संरक्षा की रक्षा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आरपीएफ रेलवे संपत्ति और रेल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

आरपीएफ की भूमिका और जिम्मेदारियां अनेक हैं। आरपीएफ कर्मियों की जिम्मेदारियों में अपराध की रोकथाम और पता लगाना, ट्रेनों को एस्कॉर्ट करना, जाँच प्रकरण, बंदोबस्त ड्यूटी, अभियोजन, आपदा प्रतिक्रिया, महिलाओं की सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण, खुफिया जानकारी एकत्र करना और कई प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समन्वय करना इत्यादि शामिल है। आरपीएफ ड्यूटी की प्रकृति अत्यधिक मांग वाली, तनावपूर्ण, कठोर और अत्यधिक चुनौतीपूर्ण वातावरण में की जाने वाली होती है, जिसका कर्मियों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है।

शारीरिक सहनशक्ति, मानसिक लचीलापन और स्वास्थ्य को बढ़ाने में योग के समग्र दृष्टिकोण को पहचानते हुए, आरपीएफ ने योग को अपने संस्थागत ढाँचे में सक्रिय रूप से एकीकृत किया है। योग को न केवल एक नियमित व्यायाम के रूप में बल्कि एक व्यापक आत्म सुधार, परिचालन तत्परता और तनाव प्रबंधन स्वास्थ्य उपकरण के रूप में बढ़ावा दिया जाता है तथा प्रोत्साहित किया जाता है। इसे सभी प्रशिक्षण मॉड्यूल और नियमित योग कार्यशालाओं, सम्मेलनों, प्रतियोगिता, ऑनलाइन प्रशिक्षण मॉड्यूल आदि में शामिल किया गया है, जो पूरे वर्ष आयोजित किए जाते हैं। इसमें सभी रैंक, इकाइयों और क्षेत्र संरचनाओं के कार्मिक उत्साहपूर्वक भाग लेते हैं।

दिनांक 21 जून 2025 को 11वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर, आरपीएफ अपने कर्मियों के समग्र स्वास्थ्य के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है। आरपीएफ का मार्गदर्शक आदर्श शीर्षक 'यशो लाभस्व'-गौरव प्राप्त करें-प्रत्येक दिन और प्रत्येक कर्तव्य में अपने कर्मियों के बीच अदम्य भावना और क्षमता को दर्शाता है। योग राष्ट्र की सेवा में एक केंद्रित, लचीला और हमेशा योग्य आरपीएफ बनाने में एक महत्त्वपूर्ण उपकरण के रूप में कार्य करता है। योग के इस अंतरराष्ट्रीय दिवस पर, रे.सु.ब. प्राचीन अनुशासनों जैसे कि मानसिक स्पष्टता, शारीरिक जीवन शक्ति, एकता, सद्भाव तथा राष्ट्रीय सेवा के प्रतीक को अपनाने के लिए अपनी प्रतिज्ञा की पुष्टि करता है।



पर्यटकों का पसंदीदा ठिकाना

गुजरात का शिवराजपुर बीच

नीलेश शुक्ला

गुजरात, जो भारत के औद्योगिक हृदय के रूप में जाना जाता है, आज समुद्र तट और द्वीप पर्यटन के क्षेत्र में भी एक नई पहचान बना रहा है। बदलते वैश्विक और राष्ट्रीय पर्यटन रुझानों के बीच, गुजरात अब उन पर्यटकों का पसंदीदा ठिकाना बनता जा रहा है, जो सुंदरता के साथ-साथ सुरक्षा, स्वच्छता और संरचना की तलाश में हैं।

बदलते दौर में गुजरात की बढ़ती लोकप्रियता

अब घरेलू और अंतरराष्ट्रीय पर्यटक ऐसे स्थलों की तलाश में हैं जहाँ स्थायित्व, सुरक्षा और सुविधाएँ प्राथमिकताएं हों। इस परिप्रेक्ष्य में गुजरात एक सुरक्षित, सुव्यवस्थित और सुंदर गंतव्य के रूप में उभर कर सामने आया है।

विशाल समुद्री तट और अपार संभावनाएँ

गुजरात की 1600 कि.मी. से भी लंबी समुद्री सीमा इसे भारत का सबसे लंबा तटीय राज्य बनाती है। यहाँ का तटीय भूभाग न केवल प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है, बल्कि अब सरकार के प्रयासों से पर्यटन के लिए पूरी तरह तैयार भी हो चुका है। शिवराजपुर बीच, जो अब 'ब्लू फ्लैग' प्रमाणित बीच बन चुका है, इसका बेहतरीन उदाहरण है।

शिवराजपुर : एक आदर्श तटीय पर्यटन स्थल

द्वारका के निकट स्थित शिवराजपुर बीच को विश्वस्तरीय सुविधाओं और पर्यावरणीय मानकों के अनुरूप विकसित किया गया है। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन किसी भी समुद्र तट को मिलने वाला एक प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय सम्मान है, जो स्वच्छता, सुरक्षा, पर्यावरणीय शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं पर आधारित होता है। शिवराजपुर न केवल इन मानकों पर खरा उतरा है, बल्कि पर्यटकों को पैरासेलिंग, जेट स्की, स्कूबा डाइविंग जैसे रोमांचक जलक्रीड़ाओं का भी आनंद देता है।



उभरते अन्य तटीय और द्वीपीय स्थल

गुजरात में समुद्र तट केवल शिवराजपुर तक सीमित नहीं हैं। मांडवी बीच (कच्छ), तीथल (वलसाड), चोरवाड़ (सोमनाथ), गोपनाथ (भावनगर) और बेट द्वारका जैसे स्थलों को भी आधुनिक पर्यटन केंद्रों के रूप में विकसित किया जा रहा है।

दीव, जो भले ही संघ राज्य क्षेत्र का हिस्सा है, परंतु पर्यटन के दृष्टिकोण से गुजरात के साथ गहरे रूप से जुड़ा है। यहाँ के समुद्र तट, पुर्तगाली धरोहरें और शराब नीति इसे विशेष बनाते हैं।

पर्यटन में बुनियादी ढाँचे का सशक्तिकरण

गुजरात सरकार द्वारा 2021-25 की पर्यटन नीति के अंतर्गत होटलों, रिसॉर्ट्स और अन्य पर्यटन सुविधाओं के लिए निवेश प्रोत्साहन, टैक्स रिबेट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जैसे कई योजनाओं को क्रियान्वित किया गया है। गुजरात गति शक्ति मास्टर प्लान के अंतर्गत समुद्र तटीय क्षेत्रों को अन्य शहरों से जोड़ने वाली सड़कों, रेलवे और एयर कनेक्टिविटी को तेजी से विकसित किया जा रहा है।

रोजगार और स्थानीय विकास

समुद्री पर्यटन न केवल गुजरात के छवि को एक नया आयाम दे रहा है, बल्कि स्थानीय समुदायों को भी नई जीविकाओं से जोड़ रहा है। मछुआरा समुदाय अब होमस्टे, हैंडीक्राफ्ट बिक्री, बीच कैफे और वॉटर स्पोर्ट्स के माध्यम से अपनी आमदनी बढ़ा रहा है। महिलाओं के स्वयं सहायता समूह भी हॉस्पिटैलिटी और पर्यावरण संरक्षण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

एक सुरक्षित और स्थायी गंतव्य

गुजरात का तटीय पर्यटन केवल सुंदरता का अनुभव नहीं कराता, बल्कि यह सुरक्षा, स्थायित्व और संस्कृति का समावेश भी प्रस्तुत करता है। हर बीच पर लाइफ गार्ड्स, सीसीटीवी, स्वच्छ शौचालय, वेस्ट मैनेजमेंट और दिव्यांगों के लिए सुविधाओं की मौजूदगी इसे एक आदर्श गंतव्य बनाती है।

समुद्र से जुड़ती नई पहचान

गुजरात अब केवल उद्योगों का प्रदेश नहीं, बल्कि समुद्र की गोद में बसा एक सुंदर, सुरक्षित और आधुनिक पर्यटन प्रदेश बन चुका है। शिवराजपुर की सुनहरी रेत से लेकर मांडवी के शांत लहरों तक, गुजरात के समुद्र तट न केवल सुकून का अनुभव देते हैं, बल्कि देश और दुनिया को यह संदेश भी देते हैं कि भारत के पास विश्व स्तरीय तटीय पर्यटन की भी असीम संभावनाएँ हैं।

शिवराजपुर जाने के लिए रेल और एयर कनेक्टिविटी है। राजकोट तक हवाई यात्रा कर द्वारिका जा सकते हैं और द्वारिका से सड़क मार्ग होते हुए शिवराजपुर जा सकते हैं। द्वारिका से शिवराजपुर सिर्फ 16 कि.मी. है।

समुद्र की गोद में गुजरात, अब पर्यटन का नया चेहरा बनकर देश और दुनिया को अपने स्वागत का निमंत्रण दे रहा है।



अपना ज्ञान टटोलें

1. **प्रधानमंत्री ने हाल ही में गुजरात के किस जिले में स्थापित इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री का उद्घाटन किया है?**

   (क) दाहोद (ख) गोधरा

   (ग) वड़ोदरा (घ) राजकोट

2. **दिनांक 22 मई, 2025 को प्रधानमंत्री ने पुनर्विकसित कितने रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया?**

   (क) 508 (ख) 103

   (ग) 100 (घ) 95

3. **दुनिया का सबसे ऊँचा रेलवे आर्च ब्रिज कौन-सा है?**

   (क) पांबन ब्रिज (ख) अंजी ब्रिज

   (ग) चिनाब ब्रिज (घ) बोगीबिल

4. **देश का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल कहाँ है?**

   (क) रेवाड़ी (ख) मानेसर

   (ग) जोधपुर (घ) खुर्जा

5. **दिनांक 1 जुलाई, 2025 से आरक्षण चार्ट कितने घंटे पहले बनाया जा रहा है?**

   (क) 8 (ख) 4

   (ग) 12 (घ) 2

6. **आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन की स्थापना कब हुई थी?**

   (क) 1974 (ख) 1874

   (ग) 1906 (घ) 2000



7. **यूएसबीआरएल परियोजना का संबंध किस राज्य से है?**

   (क) उत्तराखंड (ख) लद्दाख

   (ग) जम्मू-कश्मीर (घ) पंजाब

8. **हाल ही में बनारस लोकोमोटिव वर्क्स द्वारा किस देश को लोकोमोटिव भेजे गए?**

   (क) इंडोनेशिया (ख) श्रीलंका

   (ग) भूटान (घ) मोजाम्बिक

9. **अब तक भारतीय रेल में ब्रॉड गेज नेटवर्क का कितना प्रतिशत विद्युतीकरण हो चुका है?**

   (क) 50 (ख) 90

   (ग) 99 (घ) 86

10. **उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है?**

    (क) गोरखपुर (ख) जम्मू

    (ग) नई दिल्ली (घ) लखनऊ

1. (क) 2. (ख) 3. (ग) 4. (ख) 6. (ख) 8. (ख) 10. (ग)
5. (क) 7. (ग) 9. (ग)

रेल मंत्रालय द्वारा प्रकाशित एक मात्र हिन्दी मासिक पत्रिका

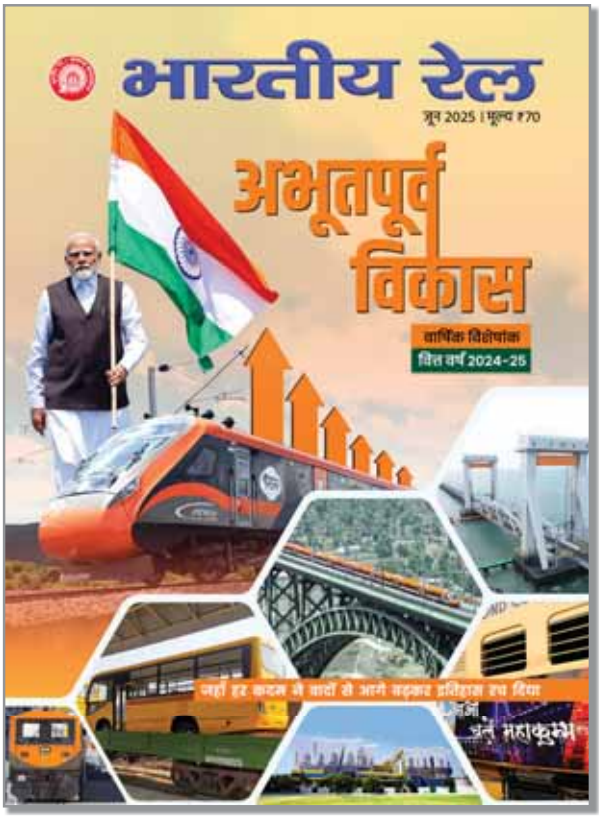


























TRANSFORMING RAILWAYS

THROUGH EXPERIENCE AND INNOVATION

India's 1st Private Railway Engineering Consulting Company



- Four Decades of Industry Experience
- Proven Success in Timely Delivery of Complex Projects
- Practical Solutions Using Latest Technology
- Strong Commitment to Sustainability
- Comprehensive Services Across Railway Sectors

BARSYL
we innovate



Balaji Railroad Systems Private Limited

"BARSYL Towers", Plot No. 3 Sitaram Nagar, Staff Road, Secunderabad - 500009 Telangana, INDIA.

+91 40 27847804 / 06 mail@barsyl.in www.barsyl.in

IRIS Certification
AAR M-1003
Daulat Ram ENGINEERING

PRIME MOVERS FOR RAIL, MINING & URBAN MOBILITY

- Traction Motors / Alternators
- Air Conditioners
- Cooling Fans / Blowers
- Dynamic Brake Resistors
- Pantographs
- E- Buses
- Auxiliary Generators



10/2, NH-12, Simrai, Post Obedullahganj, Distt. Raisen, Near Bhopal, 464993, India
+91 7480 350001 to 350030 +91 8889983336 info@daulatram.org www.daulatram.com

रेल, पर्यटन व साहित्य को एक साथ संजोए
रेल मंत्रालय द्वारा प्रकाशित एकमात्र हिंदी मासिक पत्रिका



भारतीय रेल

की सदस्यता
अब ऑनलाइन भी उपलब्ध

अब ई-पत्रिका भी उपलब्ध

www.irctctourism.com/IRBRmag/#/home/hn

क्यू आर कोड स्कैन करें

सदस्यता शुल्क

मद		ऑफलाइन सदस्यता शुल्क (₹)	ऑनलाइन सदस्यता शुल्क (₹)	ई-पत्रिका सदस्यता शुल्क (₹)
एक प्रति (मासिक अंक)		20	-	-
एक प्रति (विशेषांक)		70	-	-
वार्षिक सदस्यता (सर्व साधारण)	एक वर्ष	250	263	130
	दो वर्ष	460	483	230
	तीन वर्ष	675	709	340
वार्षिक सदस्यता (रेलकर्मी)	एक वर्ष	200	210	100
	दो वर्ष	370	389	190
	तीन वर्ष	540	567	270
वार्षिक सदस्यता (विदेशी) सी-मेल द्वारा		1,250	1,313	----
वार्षिक सदस्यता (विदेशी) एयर-मेल द्वारा		2,500	2,625	----

(सदस्यता शुल्क में वार्षिक विशेषांक भी शामिल है।)

सदस्यता फॉर्म

नाम .....

पता .....

..... पिन कोड .....

मोबाइल ..... ई-मेल .....

पहचान पत्र संख्या (यदि रेल कर्मचारी है तो): ..... वैधता की तारीख .....

ऑफलाइन भुगतान का माध्यम

I) एम.ओ./आई.पी.ओ/डी.डी. व्यापार प्रबंधक के पक्ष में कमरा नं0 310, रेल भवन, रायसीना रोड, नई दिल्ली-110001
II) नगद जमा कराने हेतू : कमरा नं0 310, रेल भवन, रायसीना रोड, नई दिल्ली-110001

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें: व्यापार प्रबंधक, कमरा नं. 310, रेल भवन, रायसीना रोड, नई दिल्ली-110 001,
टेलीफोन: 011-47845089, 45089 (रेल) **bmpr310rb@gmail.com**

पंजीयन संख्या : दिल्ली पोस्टल नं. डी.एल. (एन.डी.)-11/6031/2024-25-2026
आर.एन.आई रजिस्टर्ड नं. 14427/1960
ISSN 2457-0001
दिनांक 08 को प्रकाशित तथा दिनांक 10-11 को प्रेषित



विज्ञापन दरें

विवरण	सामान्य अंक (मासिक दरें)		विशेष अंक (वार्षिक अंक)
	सामान्य दरें	अनुबंधित दरें*	
बैक कवर	₹22,000	₹20,000	₹25,000
सेकेण्ड कवर	₹19,000	₹17,000	₹22,000
थर्ड कवर	₹19,000	₹17,000	₹22,000
पूरा पृष्ठ (विशेष स्थिति, जैसे टेक्स्ट के बाद में)	₹16,000	₹15,000	₹18,000
पूरा पृष्ठ	₹15,000	₹14,000	₹17,000
आधा पृष्ठ	₹9,000	₹8,000	₹11,000
सेंटर स्प्रेड (दो पेज इकट्ठे)	₹28,000	₹25,000	₹32,000

* तीन महीने या इससे अधिक अवधि के लिए विज्ञापन प्रकाशित करवाने का अनुबंध करने पर लागू।
- उपरोक्त दरों के साथ 5% जीएसटी, आइजीएसटी प्राप्य होगी।

भुगतान का माध्यम

'व्यापार प्रबंधक, भारतीय रेल, नई दिल्ली'
के पक्ष में डिमाण्ड ड्राफ्ट, चेक लिखें अथवा एनईएफटी के द्वारा

तकनीकी विवरण

पत्रिका का आकार : 28X20.5 सेमी, छपाई क्षेत्र : 23X16.5 सेमी

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें

ललित कुमार धनकड़, व्यापार प्रबंधक
310, रेल भवन, रायसीना रोड, नई दिल्ली-110 001
टेलीफोन : 011- 47845378, 23382531, email : bmpr310rb@gmail.com

मुद्रक व प्रकाशक : **ललित कुमार धनकड़** द्वारा रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) के लिए मैसर्स विबा प्रेस प्रा. लि., सी-66/3, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-2, नई दिल्ली-110020 में मुद्रित व 310, रेल भवन, रायसीना रोड, नई दिल्ली-110001 से प्रकाशित। संपादक : **योगेश अवस्थी**